हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 मार्च, 2015

खण्ड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 12 मार्च, 2015

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)27
घोषणा–	
अध्यक्ष द्वारा–	
अनुपस्थिति संबंधी सूचना	(4)36
विभिन्न मामलों का उठाना	(4)37
सदन में महात्मा गांधी तथा डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे नेम प्लेट्स को हटाना	(4)41
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)42
विद्यार्थियों का अभिनन्दन	(4)44

मूल्य : ₹ 545

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)44
वैयक्तिक स्पष्टीकारण	(4)66
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)67
वैयक्तिक स्पष्टीकारण	(4)73
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)74
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा	(4)81
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)81
बैठक का समय बढ़ाना	(4)83
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)83
बैठक का समय बढ़ाना	(4)97
राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण	(4)98

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 12 मार्च, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात:10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Open a separate Girls College in Village Mandkola

***330. Shri Kehar Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govenment to open a separate college for girls in village Mandkola of Hathin constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंडकौला गांव एक ऐतिहासिक गांव है। हरियाणा के मानचित्र पर भी इसका विवरण है। इसकी आबादी करीब 14 हजार है। इसके आस-पास करीब 50 गांव हैं जहां कोई भी कॉलेज नहीं है। अगर यहां कॉलेज बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर बेटियों को आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यहां पर कॉलेज बनाने पर पुन: विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त इसी प्रश्न में मैंने मानपुर गांव में कन्या महाविद्यालय के निर्माण की बात रखी थी लेकिन उसे इस प्रश्न से हटा दिया गया। भौगोलिक स्थिति के अनुसार हथीन क्षेत्र करीब 57 किलोमीटर की लम्बाई में पड़ता है, मेरा सदन से अनुरोध है कि मानपुर गांव और बहीर गांव दोनों बड़े गांव हैं। ये ऐतिहासिक गांव हैं, इनकी आबादी भी 12-12 हजार के करीब है। इनके अतिरिक्त दो दर्जन गांव और इनके करीब हैं अगर वहां भी कॉलेज का निर्माण किया जाता है तो निश्चित तौर पर वहां बेटियों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा और जो सरकार का नारा है 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' उसको भी आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर पुन: विचार किया जाए।

श्री रामबिलास शर्मा : माननीय विधायक श्री केहर सिंह जी ने मंडकौला और मंडना गांवों का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, यह डागरों के दो बड़े गांव हैं। एक महाविद्यालय 16 किलोमीटर दूरी पर है और दूसरा 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा यहां एक-दो प्राईवेट कॉलेज भी चल रहे हैं। एक राजकीय महाविद्यालय बनकर तैयार हो गया है और यह नये सत्र से चालू होने वाला है।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है वह गांव है स्वामिका। स्वामिका गांव की ऐसी स्थिति है जो हथीन कस्बे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। हथीन कस्बे की बेटियां वहां पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। हथीन कस्बे की वर्षों से मांग चली आ रही है कि हमारे कस्बे के अन्दर एक कॉलेज बनाया जाए। तीन महीने पहले हथीन कस्बे में जहां विवाद हुआ वह साढ़े 6 एकड़ जमीन है। दोनों समुदाय राजी हैं अगर उस जगह पर बेटियों के लिए कॉलेज का निर्माण किया जाता है तो ज्यादा उपयुक्त होगा। जो कॉलेज स्वामिका गांव में बन रहा है उसका कन्या महाविद्यालय का नाम हटा कर लड़कों के कॉलेज का नाम दिया जाए। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि स्थिति और परिस्थिति को शर्मा जी भलीभांति जानते हैं। वह बहुत बार वहां गये हैं। वहां के सारे हालात आपक समक्ष हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन दोनों बिन्दुओं पर अमल किया जाए।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री केहर सिंह जी की उस क्षेत्र के प्रति जो संवेदनशीलता है, वह बिल्कुल सही है और जहां तक स्वामिका गांव की बात है उसमें कन्या महाविद्यालय बनकर तैयार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों के बारे में जिक्र सदन में करना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े गांव मंडना और मंडकौला है, उनकी लोकेशन से मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। मैंने इस बारे में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात की थी। जहाँ तक बेटियों की शिक्षा का सवाल है "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" यह हमारा एक प्राईम प्रोजैक्ट है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए इसका दिनांक 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से शुभारंभ किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक की समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नरवाना हल्के के के.एम. गवर्नमैंट कॉलेज में वर्ष 2014-15 में 1500 के आसपास लड़कियाँ हैं और बीते वर्षों में भी लगभग इतनी ही लड़कियों की संख्या थी। अध्यक्ष महोदय, इस समय कॉलेज में बच्चों की कुल संख्या 3300 के करीब है जबकि नरवाना क्षेत्र से इतनी ही संख्या में बच्चों को दाखिला न मिलने के कारण आसपास के दूसरे प्राईवेट कॉलेजों में बी.ए. फाईनल का पैकेज लगभग 80,000 रुपये होता है जबकि सरकारी कॉलेजों में बी.ए. की पढ़ाई कम से कम फीस देकर की जाती है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे पता चला है कि सरकार ने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है। जिस भी कॉलेज में लड़कियों की संख्या 1000 हजार से ज्यादा हो वहाँ सरकार की ओर से नया महिला कॉलेज बनाये जाने का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी में स्टेट गवर्नमैंट को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता क्योंकि इस पॉलिसी के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज दिया जाता है। अगर सरकार का इस प्रोजैक्ट में नर्म रवैया है तो जमीन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आयेगी क्योंकि गवर्नमैंट कॉलेज, नरवाना के पास काफी जमीन है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि नरवाना में एक सरकारी महिला कॉलेज जल्द से जल्द बनाया जाये। आपकी अति कृपा होगी।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए अलग से प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना

चाहती हूँ कि पिछली सरकार ने बड़ी मुश्किल से बाढड़ा विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज बनाने की बात कही थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने "बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ" अभियान चला रखा है, फिर भी लड़कियों को 70 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाया जाये ताकि माननीय मंत्री इसका उद्घाटन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, आपका प्रश्न अलग है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह अलग प्रश्न जरूर है, मगर बेटियों का सवाल है, इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वहाँ पर बिल्डिंग कब तक तैयार हो जायेगी ? (विघ्न)

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैडम किरण चौधरी कहीं से भी प्रश्न पूछेगी हम उसका जवाब देंगे। मैं किरण चौधरी जी को बधाई देता हूँ कि अपने शासनकाल में सरकार के साथ काफी संघर्ष करने के बाद जाते-जाते चाहे वह भिवानी विश्वविद्यालय की बात हो या बाढड़ा कॉलेज बनवाने की बात हो इन्होंने सरकार से जमीन मंजूर करवाई। अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण चौधरी जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो काम बेटियों के हित में है हमारी सरकार उनको जल्दी से जल्दी पूरा करेगी।

Old Age Pensioners

***70. Smt. Kiran Choudhary :** Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state—

(a) the number of old age pensioners in Tosham Constituency as on 31st March, 2014 togetherwith the number of old age pensioners at present;

(b) the number of old age pension holders in Haryana State as on 31st March, 2014 togetherwith the number of old age pensioners at present ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमति कविता जैन) :

(क) 31 मार्च, 2014 तक तोशाम विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की संख्या 16,796 थी तथा 31-01-2015 को वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की संख्या 17,367 है।

(ख) 31 मार्च, 2014 तक हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था पेंशनधारकों की संख्या 13,54,297 थी तथा 31-01-2015 को वृद्धावस्था पेंशनभोगियों की संख्या 13,90,486 है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज के दिन पेंशन बैंक के जरिए वितरित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में 50 प्रतिशत ऐसे गांव हैं जहां पर बैंक उपलब्ध नहीं है।

[श्रीमती किरण चौधरी]

पेंशन पाने के लिये बूढ़े बुजुर्गों को बहुत तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न तो यह है कि बुजुर्ग होने के कारण लोग धक्के खाते हैं और उनको पेंशन के लिये आने-जाने के लिये भाड़ा भी देना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, काफी बुजुर्ग होने के कारण वे पेंशन लेने के लिये जा भी नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों का खाता तो है यदि उनके लिये चैक बुक की व्यवस्था की जाये तो वे दूसरे व्यक्ति को चैक देकर अपनी पेंशन मंगवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो ऐज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यह व्यवस्था नये पेंशन धारकों के लिए तो ठीक है मगर पुराने पेंशन धारकों को यह मालूम नहीं है कि वे कब पैदा हुये थे। अध्यक्ष महोदय, उनके पास एज सर्टिफिकेट नहीं है, जिस कारण वे आज धक्के खाते फिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय एक बोर्ड बिठाया जाता था। बोर्ड के अधिकारी देख लिया करते थे कि यह बूढ़ा बुजुर्ग है तो वे उसकी फाइल के ऊपर अपने कमैंट्स वगैरह लिख कर दे देते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस तरह का कोई प्रावधान करने की सरकार ने कोशिश की है?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूँ कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन नि:संदेह हमारे बूढ़े बुजुर्गों के लिए हैं और यह एक सम्मान की तरह ही उन्हें वितरित की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक धक्के खाने का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बैंकों के माध्यम से नई स्कीम शुरू करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2011 में हमारे बुजुर्गों ने पेंशन पाने के लिए धक्के खाये थे। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने बैंक एकाउंट खोले बगैर ही उनको पेंशन देनी शुरू की थी, लेकिन अब हमारी सरकार सही ढंग से बैंकों के माध्यम से पेंशन देने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार 3 चरणों के द्वारा पेंशन वितरित करेगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार सबसे पहले तो उन 51 गांवों में जहां पर 96 प्रतिशत से अधिक खाते खोले गये हैं उनमें पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से बैंकों में पेंशन दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी माननीय सदस्या को पहले चरण की डिटेल भी बता सकती हूँ कि हम किन-किन बैंकों के माध्यम से पेंशन देने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खाता खोलने के साथ-साथ नि:संदेह चैक बुक व ए.टी.एम. वगैरह की तमाम सुविधाएं देने का प्रावधान भी करेंगे। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग वृद्धावस्था होने के कारण बैंक में नहीं जा सकते, वे चैक बुक के माध्यम से अपने किसी अथोरिटी को चैक देकर अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से एज सर्टिफिकेट की बात सामने आई है, पिछली सरकार के दौरान पेंशन बनती रही है, उनमें बहुत सी कमियां सामने आती रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में करनाल के अंदर एक ऑडिट करवाया था और मुझे सदन को बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ पर करोड़ों रुपयों की गलत पेंशन बनी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, इस गलत कार्य के लिए बाकायदा 3 एफ.आई.आर. भी दाखिल की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार एज़ सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र वर्तमान में जो वोटिंग आई कार्ड है उसको ऐज़ का आधार मानते हैं। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने पेंशन बनाने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाने के साथ-साथ सैल्फ अटैस्टेड, स्वयं हस्ताक्षरित की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार केवल इतना ही चाह रही है कि अब आगे से जितनी भी पेंशन दी जायेगी वे खाता धारकों को अपना बैंक अकाउंट खोलने के साथ-साथ उसे बैंक पासबुक की कॉपी के पहले पेज की फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी। नि:संदेह आने वाली 1 अप्रैल, 2015 को जितने भी पैंडिंग फार्म्स हैं उनको हम अपलोड करने जा रहे हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बहुत अच्छी बात कही है कि बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन के लिए धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम तो स्वयं चाहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग धक्के ना खायें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से एक बात ओर पूछना चाहती हूँ कि जिस गांव में बैंक की सुविधा नहीं है और बूढ़े बुजुर्गों के खाते कहीं ओर खुले हुए हैं तो वहां जाने के लिए उनको क्या भाड़ा मिलेगा?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल क्लीयर कर दिया था कि पहले चरण में हम लोग उन बैंकों के माध्यम से पेंशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर बैंकों की शाखाएं मौजूद हैं। हमारा दूसरा चरण वहाँ पर शुरू होगा जहां पर बैंकों ने अपने कियोसक लगाएं हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हरियाणा सरकार पेंशन वितरण पंचायतों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से और नगर परिषदों के माध्यम से दे रही हैं, उसी तरह से पेंशन देते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी हमारे सम्मानित बुजुर्गों को पेंशन के लिये धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि गांवों में पेंशन सही ढंग से, समय पर, सरपंचों के माध्यम से बंट रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि मंत्री जी जो बात कह रही हैं वह गलत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि स्वर्गीय चौ. देवीलाल जी ने 1987 में सबसे पहले यह सम्मान पेंशन शुरू की थी। जहां तक मुझे याद है उस समय बुजुर्गों की संख्या तकरीबन 14 लाख थी। उसके बाद सन् 1991 में चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने करीब 6 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी थी। अब जबकि पेंशन शुरू हुए इतने वर्ष बीत गए हैं और आबादी काफी बढ़ चुकी है आज भी बहन जी के मुताबिक पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों की संख्या 14 लाख ही बताई है। माननीय मंत्री जी के अनुसार अब पेंशन को बैंको या चेक के माध्यम से दिया जाएगा। बैंको के द्वारा दिया जाने वाला पैसा बुजुर्ग के परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त हो सकता है। इससे बुजुर्गों को पैसा मिलने में कठिनाई आती है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अभी पेंशन बैंकों द्वारा न दी जाए। अभी आपको सरपंचों, पटवारी या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा ही पेंशन बंटवानी चाहिए। बैंक या चेक सिस्टम को आप 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दीजिए। कुछ वर्षों के बाद शिक्षित लोग पेंशन प्राप्त करने लग जाएंगे, तब यह सही रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अभी इसी पुरानी व्यवस्था को जारी रखें और सरपंचों या सरकारी अधिकारियों के द्वारा ही पेंशन बंटवाएं। बैंक या चैक द्वारा पेंशन देने से ये पैसे बुजुर्गों तक नहीं पहुंचेंगे।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अभी बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त करने के लिए सरपंचों या नगर पार्षदों के पास जाना पड़ता है। जैसा मैंने पहले बताया है कि पेंशनधारकों की संख्या लगभग 14 लाख है। (विघ्न)

श्री जसविंद्र सिंह संधू : मैडम, आप अपने अधिकारियों से पता करवा लें। सन् 1987 में भी पेंशनधारकों की संख्या 14 लाख थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर जिले में पेंशन के लिए दोबारा से वैरिफिकेशन करवा रहें हैं और दोबारा लिस्ट

[श्रीमती कविता जैन]

डाउनलोड करवा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि कोई भी वृद्ध पात्र पेंशन प्राप्त करने से वंचित न रहे। जैसा कि माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि बुजुर्ग बैंक या चेक से या ए.टी.एम. से पेंशन प्राप्त नहीं कर सकते। हम निशक्त बुजुर्गों को उनकी पेंशन उनके घर तक पहुंचायेंगे। (विघ्न) आप पेंशन की चिंता न करें। अगर बुजुर्ग बैंक, चैक या ए.टी.एम. से पैसा नहीं ले सकेंगे तो हम उनके प्रतिनिधि के द्वारा या किसी भी तरीके से जिससे बुजुर्ग चाहेगा पेंशन दी जाएगी। कोई बुजुर्ग कहेगा तो हम डोर स्टैप तक भी पेंशन पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी पेंशन डोर स्टैप पर देने की बात कह रही हैं तो फिर कोई परेशानी नहीं है।

श्री जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, बुजुर्गों के हाथ में कैश जाना चाहिए। डोर स्टैप पर चैक नहीं जाना चाहिए। (विघ्न)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि ये बुजुर्गों की पेंशन की चिंता न करें। हम उनकी इच्छा का मान रखेंगे। अगर वे कहेंगे तो हम उनको डोर स्टैप पर कैश भी देंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं कि खाते खुलवाने के लिए चलाई गई स्कीम में एक प्रैक्टीकल प्रोब्लम आ रही है जैसे किसी का नाम है रामेसर और वह रामेसर के नाम से पेंशन ले रहा है जबकि उसका खाते में नाम रामेश्वर है। ऐसे हजारों केसिज हैं इसके बारे में विभाग ने क्या कार्रवाई की है ?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जिन भी लाभार्थियों के नाम में मामूली गलतियां हैं उनके लिए विभाग ने बैंकों को क्लीयर कट निर्देश जारी किए हुए हैं कि वे उनके एकाउंट में एक कॉलम बनाकर यह रिमार्क्स दे दें कि फलां आदमी के नाम में यह गलती है। जैसे हिन्दी में किसी का नाम सीता है और इंग्लिश में उसके नाम की स्पेलिंग में कोई गलती आ जाती है तो उसके बैंक एकाउंट में बैंक के द्वारा यह रिमार्क्स दे दिया जाए कि उसके नाम में यह गलती है यह ठीक कर दी जाए। इसके बारे में किसी लाभार्थी को कोई दिक्कत है तो विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भी ये निर्देश दे रखे हैं कि वे ऐसी गलतियों को ठीक करें। इसके अलावा विभाग ने एक यूनिक आई.डी. नम्बर भी सभी लाभार्थियों को दिया हुआ है वे अपने अकाउंट के साथ अपना यूनिक आई.डी. नम्बर भी जरूर दें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद बैंक में गया था और बैंक के कर्मचारी ये कहते हैं कि हम तो आधार कार्ड के नाम बेस पर ही बैंक खाता खोलेंगे।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में विभाग ने बैंकों के साथ एक एम.ओ.यू. साईन किया हुआ है और बैंकों को खाते खोलने पड़ेंगे वे इस बारे में इन्कार नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई केस माननीय सदस्य की कॉलेज में है तो वे हमें बतायें हम उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। इसके अलावा विभाग ने सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को ये क्लीयर कट निर्देश जारी कर रखें हैं और उनको इस बारे में पॉवर भी दे रखी हैं वे इस प्रकार की गलतियों को ठीक कर सकते हैं। यह भारत सरकार की योजना है इसलिए बैंक इस से भाग नहीं सकते।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, लाभार्थियों के नाम की गलती को विभाग द्वारा ठीक करना चाहिए फिर बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस बारे में विभाग ने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को पॉवर दे रखी हैं।

श्री मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो नगर निगम का क्षेत्र है खासकर हमारा फरीदाबाद जोकि बहुत पुराना नगर निगम है। वहां पर जब बुजुर्ग लोग बैंक का खाता खुलवाने के लिए जाते हैं तो वहां के अधिकारी यह कहते हैं कि आपका खाता इस बैंक में नहीं खुलेगा। बुजुर्ग आदमी रिक्शा में बैठकर एक बैंक से दूसरे बैंक तक चक्कर काटते हैं। स्टेट बैंक वाले यह कहते हैं कि आपका खाता इस बैंक में नहीं खुलेगा और कोआप्रेटिव बैंक वाले यह कहते हैं कि आपका खाता इस बैंक में नहीं खुलेगा। माननीय मंत्री महोदया कृपया हमें यह क्लीयर करके बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम के कौन से बैंक में बुजुर्गों का खाता खुलेगा। फरीदाबाद सबसे बड़ा नगर निगम है।

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं जो पैंशन लेते हैं वे अपना अकाउंट किसी भी बैंक में चाहे वह कोआप्रेटिव बैंक है या चाहे वह सैन्ट्रलाईज्ड बैंक हैं उसमें अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और उस बैंक में ही उसकी पैंशन डाल दी जायेगी। अगर फिर भी कोई बैंक किसी बुजुर्ग का बैंक खाता नहीं खोलता है तो विभाग के नोटिस में लायें हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

Criteria Adopted for Model Village

***94. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state the criteria adopted by the State Government for declaring a village as a model or as an ideal village ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी। विवरणी सदन के पटल पर रखी है।

विवरणी

सांसद आदर्श ग्राम योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 अक्तूबर, 2014 को आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत संसद सदस्यों द्वारा अपने खुद के या अपनी पत्नी के गांव के अलावा समतल क्षेत्रों में 3000 से 5000 की आबादी वाले एवं पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 आबादी वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जा सकता है।

आदर्श गांव में जहां तक सम्भव हो सके, लोगों की क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता का साझा विजन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें संसद सदस्य, ग्राम पंचायत, सिविल सोसायटी और सरकारी तन्त्रों द्वारा पर्याप्त मदद की जाएगी। स्वाभाविक तौर पर आदर्श ग्राम के घटक संदर्भ विशिष्ट होंगे।

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

आदर्श ग्राम का विकास करने के लिए इस योजना के मानदण्ड निम्न प्रकार से है :-

- निर्धारित ग्राम पंचायतों के समय विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
- आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के द्वारा किया जाएगा-
  - उन्नत बुनियादी सुविधाएं।
  - अधिकतम उत्पादकता।
  - बेहतर मानव विकास।
  - बेहतर आजीविका के अवसर।
  - असमानताओं में कमी।
  - अधिकार और हकदारी के लिए पहुंच दिलाना।
  - वृहत सामाजिक एकजुटता।
  - समृद्ध सामाजिक पूंजी।
- स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आस-पास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सकें।
- निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

मुख्यत: आदर्श ग्राम निम्नलिखित मानकों के साथ विकास को प्राप्त करने का उद्देश्य होंगे :-

क. बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएं

i. सभी बेघर गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्का मकान

ii. परिवारों को शोधित पेयजल नलों से उपलब्ध करवाना

iii. ढकी हुई नालियों युक्त भीतरी बारहमासी सड़कें

iv. मुख्य सड़क नेटवर्क तक बारहमासी सड़क संपर्क

v. सभी परिवारों में बिजली का कनेक्शन और स्ट्रीट लाईट जिसमें बिजली के वैकल्पिक स्त्रोतों, विशेष सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाईट शामिल हैं।

vi. सार्वजनिक संस्थाओं - आंगनवाड़ियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालयों, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना।

vii. सामुदायिक भवन, स्वयं सहायता समूहों के संगठनों के लिए भवन, खेल

परिसर तथा कब्रगाह/शमशान घाट सहित सिविक अवसंरचना।

viii. ग्रामीण बाजार

ix. पीडीएस दुकानों के लिए अवसंरचना

x. माइक्रो मिनी बैंक/डाकघर/एटीएम

xi. ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी और साझा सुविधा केन्द्र

xii. टेलीफोन कनेक्टिविटी

xiii. सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी

ख. सामाजिक सुरक्षा

i. सभी पात्र परिवारों - वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं के लिए पेंशन

ii. आम आदमी बीमा योजना जैसी इंश्योरेंस स्कीमें

iii. स्वास्थ्य बीमा - आर.एस.बी.वाई.

iv. सार्वजनिक वितरण प्रणाली - सभी पात्र परिवारों के लिए सर्वसामान्य उपलब्धता।

ग. पर्यावरण विकास

स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए कार्यकलाप :-

i. प्रत्येक परिवार में और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालयों की व्यवस्था करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना।

ii. उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

iii. सड़कों के किनारों पर पौधारोपण

iv. हरित पट्टी सहित, बस्तियों, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार वृक्षारोपण।

v. सामाजिक वानिकी

vi. वाटरशेड प्रबंधन विशेषकर पारंपरिक जल निकायों का पुर्नद्धार और पुनः उपयोग।

vii. वर्षा जल संचयन-छत पर वर्षा जल एकत्रीकरण और अन्य

viii. वायु, जल और भूमि को स्थानीय रूप से प्रदूषित होने से बचाना।

घ. आर्थिक विकास

i. निम्न के माध्यम से विविधिकृत कृषि कार्यकलाप एवं अन्य आजीविकाएं,

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

जिसमें पशुधन और बागवानी भी शामिल हैं, को बढ़ावा देना :-

- जैविक कृषि
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड
- मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार अवसर
- बीज बैंकों की स्थापना
- गैर-इमारती काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण और मूल्य संवर्धन
- गोबर बैंक मवैशी होस्टल सहित पशुधन का विकास
- लघु सिंचाई
- कृषि सेवा केन्द्र
- फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का उपयोग
- डेयरी विकास और प्रसंस्करण
- पारंपरिक उद्योगों को बढ़ाना
- स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं का कौशल विकास

ङ. **सामाजिक विकास**

i. भारत निर्माण स्वयंसेवियों जैसे स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप।

ii. जनता की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे स्थानीय विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह भाग ले सकें और अपना योगदान दे सकें।

iii. ग्रामीण वृद्धों, स्थानीय रोल मॉडलों विशेषकर महिलाओं स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने वाले कार्यकलाप।

iv. नागरिक समितियों के गठन व ग्रामीणों का संवेदिकरण कर हिंसा और अपराध मुक्त गांवों का कार्यकलाप।

v. ग्रामीण खेलकूद।

च. **मानव विकास**

i. सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ

ii. संपूर्ण टीकाकरण

iii. लिंगानुपात को संतुलित रखना

iv. शत-प्रतिशत संस्थागत सुपुर्दगी

v. सभी के पोषण स्तर को बेहतर बनाना, जिसमें बच्चों, किशोरियों, गर्भवती

महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

vi. विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों पर विशेष ध्यान।

vii. सभी को 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी निरंतरता बनाए रखना।

viii. विद्यालयों में आई.टी. शिक्षा देकर विद्यार्थियों को ई-साक्षर बनाना

ix. 100 प्रतिशत प्रौढ़ शिक्षा

x. युवाओं में ई-साक्षरता

xi. ग्रामीण पुस्तकालय

च. व्यक्तिगत विकास जहां पंचायत/ग्राम पंचायत सभा की उन्नति करना

i. साफ-सिफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास

ii. दैनिक व्यायाम और खेलकूद सहित स्वास्थ्यपूरक आदतों का विकास

iii. जोखिम से जुड़ी आदतों-मद्यपान, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन इत्यादि में कमी।

iv. ग्रामीणों द्वारा सभी करों एवं बिजली के बकाया/बिलों का भुगतान।

छ. सुशासन

i. सुदृढ़ और जवाबदेह पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना।

ii. ई-शासन जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

iii. सभी के लिए यू.आई.ए.डी.आई. कार्डों की व्यवस्था।

iv. सरकारी और पंचायती कर्मियों की नियमित एवं समय पर हाजिरी सुनिश्चित करना।

v. विभाग के सिटिजन चार्टर के अनुरूप समयबद्ध ढंग से सेवा प्रदायगी।

vi. एक वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा का आयोजन।

vii. प्रत्येक तिमाही में बाल सभा का आयोजन।

viii. कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी जानकारियों को पब्लिक डोमेन में डालना, दीवारों पर लिखाई, नोटिस बोर्डों के माध्यम से इन जानकारियों का स्वत: प्रकटन करना। इसमें लाभार्थियों की सूची, मद-वार बजट और

खर्च को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

ix. सूचना सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहीं ग्राम पंचायतें।

x. जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का समय पर निपटान।

xi. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की अर्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी और मनरेगा के तहत स्थापित की गई सामाजिक लेख परीक्षा इकाई इसमें सहयोग करेगी।

प्रत्येक चयनित गांव में सामाजिक, आर्थिक उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि विशेषताओं के लिए एक आधारभूत सर्वेक्षण करवाया जा चुका है। मानव संसाधनों व मूलभूत व्यवस्थाओं आदि की कमियों की पहचान के उपरान्त विकास के उपरोक्त कथित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु एक ग्राम विकास योजना बनाई जाएगी। इस योजना के लिए सभी सम्बन्धित विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वरजंस) के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि उपरोक्त वर्णित विकास संकेतकों के अधिकतर मापदण्डों को पूर्ण करने वाले सक्षम गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा।

सरकार का दृष्टिकोण है कि सभी गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रस्तावित विधायक आदर्श ग्राम योजना एवं स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से आदर्श ग्राम बनाये जाएंगे।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सदन के पटल पर रखी है उसमें वही बातें लिखी हुई हैं जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने आदर्श गाँव योजना में और उनके रखरखाव में कही हैं। वे ही सारी बातें इस सूचना में बताई गई हैं कि प्रत्येक सांसद का अपने हल्के में एक गाँव आदर्श गाँव होगा। इस हिसाब से हरियाणा में केवल 10 गाँव ही आदर्श गाँव बन पायेंगे जबकि हरियाणा राज्य में 6700 से भी ज्यादा गाँव हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न की मूल भावना यह थी कि जिस प्रकार से केन्द्र में यह स्कीम आई है उसके तहत मेरे हल्के जुलाना में जो 72 गाँव हैं उन में से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक भी गाँव नहीं आया है। पिछले 10 वर्षों में तो प्रदेश के अंदर भेदभाव और कुशासन की व्यवस्था थी। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अगले 5 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा योजनायें चलाई गई हैं कि प्रदेश के हर क्षेत्र में समग्र व समान विकास किया जायेगा, सब को साथ लेकर चलेंगे। इस प्रकार से तो एक भी गाँव आदर्श गाँव नहीं बन पायेगा क्योंकि कई विधायक सदन में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जबकि उनके क्षेत्र में सांसद किसी दूसरी पार्टी का बना हुआ है। मेरा हल्का जुलाना बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो पिछले 10 वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। क्या अब भी इस क्षेत्र की उपेक्षा की जायेगी ? आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य यह है कि अच्छी तरह से छांटकर उस गाँव को आदर्श ग्राम का दर्जा दिया जायेगा। क्या इस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर यह आदर्श ग्राम योजना सफल हो पायेगी ? अध्यक्ष महोदय, 1962 में जब सरदार प्रताप सिंह कैरो संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, उस समय मेरे हल्के के शामलो कलां गाँव को आदर्श ग्राम घोषित किया गया था। वहां पर एक पी.एच.सी. बनी थी। आज भी वहां पर एक स्टेडियम का पत्थर लगा है जिसका उस समय उद्घाटन हुआ था। इस आदर्श ग्राम की पी.एच.सी. बहुत अच्छी होती थी। वहां पर प्रतिदिन सी.एम.ओ. खुद जाया करता था, वहां पर डॉक्टर्ज भी नियुक्त थे, लेकिन आज उस पी.एच.सी. का बंटाधार हो गया

है। वहां पर स्टेडियम की सिर्फ चारदीवारी ही खड़ी है। इसी प्रकार से एक रामराय तीर्थ है जो कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के अंतर्गत आता है जिसको आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह कैरो जी शुरू करके आये थे, आज वह जर्जर अवस्था में है। कृपया ऐसे गाँवों की तरफ भी ध्यान दिया जाये जिन गाँवों में 1962 में विकासशील योजनायें शुरू की गई थीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार से हरियाणा के 6700 गाँवों को इस आदर्श ग्राम योजना का लाभ मिल पायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ढुल साहब की चिंता जायज है। इस योजना के बारे में सभी विधायकों को पत्र भेजा गया है। (विघ्न)

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों को यदि यह पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो यह जल्दी ही प्राप्त हो जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक संकल्प है, वह पूरे भारत का विकास चाहते हैं। जैसे कि ढुल साहब ने कहा कि हरियाणा में केवल 10 एम.पीज़. हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हरियाणा में केवल 10 एम.पीज़ नहीं हैं, 5 एम.पी. राज्य सभा के भी हैं। इनके अतिरिक्त हरियाणा में 90 विधायक हैं। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी उपायुक्तों की एक बैठक में यह निर्देश दिये हुए हैं कि हर उपायुक्त, ए.डी.सी., एस.डी.एम. तथा अन्य क्लास-I अधिकारीगण जो हर जिले में कम से कम 15 से ज्यादा की संख्या बनती है, वे सभी एक-एक गाँव अवश्य गोद लेंगे। आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था है। जैसे कि ढुल साहब ने कहा कि उनके क्षेत्र में 72 गाँव हैं, मेरे हल्के में 104 गाँव हैं। इस तरह से यदि शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो हर विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 50 से ज्यादा गाँव होते हैं। गाँवों का समुचित विकास हो तथा गाँवों में फिरनी, सड़कों, विद्यालयों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि की समुचित व्यवस्था को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत बहुत से गाँव कवर होने वाले हैं।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा के अंदर जिला उपायुक्तों के माध्यम से और क्लास वन अधिकारियों के माध्यम से एक गांव गोद लेने की स्कीम शुरू की थी, उसका प्रचार भी हुआ और गांवों को गोद भी लिया गया परंतु वास्तविक रूप से आज तक किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की गतिविधि सरकारी अधिकारियों के द्वारा शुरू नहीं की गई और न ही वे सरकारी अधिकारी गांव में जाकर वास्तविक स्थिति का संज्ञान ले पाए हैं। इस सरकार को बने हुए 4 महीने हो गए हैं लेकिन आज तक लोगों की कोई मीटिंग तक नहीं ली गई। किस प्रकार से सरकार की इस योजना का रूप बनेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि विधायक भी एक गांव गोद लेंगें। आज विधायकों के पास डिवैल्पमैंट फण्ड का कोई पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस स्कीम के अन्तर्गत यह उद्देश्य छिपा हुआ है कि विधायकों को एम.पी. की भांति प्रदेश के अंदर अपने हल्के के विकास के लिए कोई राशि दी जाएगी जिसको वे अपने हल्के के विकास के लिए अपने लैवल पर खर्च कर सकेंगें। हम सारे विधायक दिन रात अपने हल्के में घूमते हैं इसलिए हमें पता है कि किस गांव की कितनी बुरी हालत है और किस गांव के किस काम को प्रायरिटी दी जानी है। हम ही अच्छी प्रकार से उस बारे में लिखकर दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ग्रीवैंसिज कमेटियां बनी हुई हैं जिनमें हमें अपनी रिकमैंडेशंज देनी होती हैं। पिछली सरकार में हम अपनी रिकमैंडेशन उन कमेटियों में देकर भी आते थे लेकिन वे रिकमैंडेशन नीचे फैंक दी जाती थी यानि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंत्री

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

महोदया जींद गई थी तो मैंने कुछ रिकमैंडेशंज दी थी लेकिन उनके जाते ही हमारी रिकमैंडेशंज नीचे फैंक दी गई और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन रिकमैंडेशंज पर कोई कार्यवाही होनी ही नहीं है तो फिर इन ग्रीवैंसिज कमेटियों का क्या फायदा है ? हम लोगों को क्या जवाब देंगें कि हमने फलां फलां गांव में फलां फलां गलियों में क्या काम करवाया ? हम कमेटियों में अपनी रिकमैंडेशंज देकर आते हैं लेकिन वे ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं क्या सरकार इस बारे में जवाबदेही तय करेगी ? अध्यक्ष महोदय, जब मैं पहले विधायक था तो यहीं से ये आदेश हुए थे कि विधायकों के लैटर्स का जवाब दिया जाएगा। मैंने बड़े-बड़े अधिकारियों को, जिला अधिकारियों को बहुत से लैटर्स लिखे लेकिन मुझे अफसोस है कि आज तक 5 सालों में एक भी लैटर का जवाब नहीं आया। क्या इस प्रकार की कार्य प्रणाली इस सरकार के कार्यकाल में भी जारी रहेगी। जो लैटर्स हम सरकारी अधिकारियों को देते हैं, हम लोगों की जो समस्याएं जिला उपायुक्तों के माध्यम से सरकारी अधिकारियों को देकर आते हैं क्या उनको संज्ञान में लेकर उन पर विचार किया जाएगा ताकि विधायक उचित तरीके से अपने हल्के के विकास की योजना में सहायक हो सकें? क्या इस प्रकार की योजना बनाई जायेगी ?

श्री राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, परमिन्द्र ढुल जी बहुत बड़े और संजीदा साथी हैं। ढुल जी की जो चिंता है वह सारे सदन की चिंता है। इस सदन में हम अधिकांश विधायक ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। कुल मिलाकर यह चिंता केन्द्र सरकार से लेकर प्रांत सरकार तक सबकी है। ढुल जी ने शामलो कलां गांव का उदाहरण दिया, प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उसको आदर्श गांव का दर्जा दिया गया। राम राय पिंडारा महाभारत का तीर्थ है। राम राय पिंडारा के बारे में बात आती है कि कोई लड़की थी उसकी दूर शादी कर दी गई तो वह कहने लगी कि बापू कहीं भी ब्याह दे रामराय के कण्ठारे मैं तो आई रहूंगी। ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ राम राय है। अध्यक्ष महोदय, हर जिले में ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें हर विधायक को माननीय डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन के बराबर में बिठाया जाता है। डी-प्लान के तहत हर डिस्ट्रिक्ट की डिवैल्पमैंट योजना बनी है यह सबके ध्यान में है। यह जो आदर्श गांव स्कीम है इसके तहत हर विधायक के साथ साथ हर क्लास वन अधिकारी एक गांव गोद लेगा। आदर्श गांव में पानी की मैक्सिमम निकासी की सुविधा होगी, वहां आने जाने के लिए सड़कों की सुविधा होगी, वहां फिरनी होगी और वहां पर हरिजन बस्तियों के रखरखाव की और उनमें आने जाने के रास्ते होंगें। वहां मिनिमम चिकित्सा सुविधा होगी। 5 हजार से ऊपर की आबादी पर तो हम एक हैल्थ सैंटर बनाते ही हैं और उसके ऊपर की आबादी के गांव में प्राईमरी हैल्थ सैंटर बनाते हैं, उससे ऊपर की आबादी में सी.एच.सी. बनाते हैं। इसके अतिरिक्त गांव को जो सुविधा चाहिए विद्यालय की, प्राईमरी स्कूल की, हाई स्कूल की, सैकेण्डरी स्कूल की इस तरह की कल्पना को ध्यान में रखते हुए गांव गोद लेने की योजना के पीछे यह मानसिकता रखी गई है। ढुल साहब अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमाल कर दिया सी.एम. विंडो से लोगों के जो कार्य हो रहे हैं उस पर लोग तालियां बजा रहे हैं। सी.एम. विंडो में अर्जी लगाने के लिए हर जिले में डी.सी. आफिस के बाहर एक डिब्बा रखा हुआ है जिसमें लोग अपनी शिकायत डाल सकते हैं और एक हफ्ते में संबंधित शिकायतकर्ता को टैलीफोन या लिखित में जानकारी दे दी जाती है कि आपकी एप्लीकेशन फलां विभाग में भेज दी गई और इस समय कार्यवाही चल रही है। पहले की तरह अब किसी को चण्डीगढ़ के चक्कर नहीं काटने पड़ते। बहुत से लोगों के कार्य हुए हैं और लोग मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी कर रहे हैं। यदि माननीय विधायक

साथी की जानकारी में ऐसी कोई बात है तो माननीय साथी बतायें, उस पर सरकार द्वारा पूरा गौर किया जायेगा।

Providing Electricity to various Dhanies

***105. Shri Balwan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the electricity in various 'Dhanies' in Fatehabad constituency togetherwith time by which the electricity is likely to be provided in the Dhanies ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल खट्टर) : श्रीमान, बिजली विभाग ने पहले ही फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य में डेरा-ढाणियों को बिजली सप्लाई देने के लिए एक नीति पहले ही लागू की है।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कोई नीति कागजों में काम कर रही हो तो मुझे जानकारी नहीं है लेकिन हम हल्के में जाते हैं और वहां धरातल पर देखते हैं तो इस तरह की कोई नीति कार्य नहीं कर रही है। मेरे फतेहाबाद हल्के में कंज्यूमर जब बिजली बोर्ड के अधिकारियों के पास ढाणियों में बिजली का कनैक्शन लेने के लिए जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि एफीडेविट दो उसके बाद सैल्फ स्कीम के तहत कनैक्शन दिया जायेगा। यदि कंजूमर पूरे पैसे भरेगा तभी वे सिक्योरिटी जमा करवाते हैं। यदि ढाणी का कोई कंजूमर संघर्ष करके सिक्योरिटी जमा करवा भी देता है तो हफ्ते बाद संबंधित एस.डी.ओ. का लैटर आता है कि आप पूरे पैसे जमा करवायें अदरवाईज आपकी सिक्योरिटी कैंसिल कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी वायदा किया हुआ है कि प्रदेश की सभी ढाणियों में प्रत्येक घर को बिजली के कनैक्शन बिना लाईन का खर्चा लिए दिए जायेंगे तथा जिन लोगों ने पहले इसके लिए पैसे जमा करवाकर कनैक्शन लिए हुए हैं उनके पैसे भविष्य में आने वाले बिलों में ऐडजस्ट किए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे फतेहाबाद हल्के में जो ढाणियां हैं उनमें लाईन का खर्चा न जोड़कर लोगों को बिजली के कनैक्शन दिए जायें।

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जैसा भाई बलवान सिंह जी कह रहे हैं इसके बारे में मैं इनको जानकारी देना चाहूंगा कि जिला फतेहाबाद में इस समय टोटल 7922 ढाणियां हैं जिनमें से 4884 ढाणियों में स्कीम के तहत बिजली के कनैक्शन दिए जा चुके हैं। माननीय साथी के हल्के में टोटल 1529 ढाणियां हैं उनमें से 1268 ढाणियों में बिजली के कनैक्शन दिए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैसे का सवाल है इस बारे में मैं माननीय साथी को जानकारी देना चाहूंगा कि ढाणियों में जो लोग निगम के मौजूदा टर्मिनल से 30 मीटर की दूरी तक रहते हैं उनका खर्च बिजली बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है और जो घर निगम टर्मिनल से 30 मीटर से अधिक की दूरी पर हैं उनसे 75 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना के तहत तो प्रदेश में 100 व्यक्तियों से ज्यादा आबादी को 11 व्यक्तियों की आबादी को भी एक ढाणी का दर्जा दिया हुआ है। हमारे प्रदेश में हर साल हजारों ढाणियां आबाद हो जाती हैं। हमारे प्रदेश में उत्तरी और

[राव नरबीर सिंह]

दक्षिणी बिजली के दो निगम हैं। मैं दक्षिणी हरियाणा से चुनकर आया हूं और दक्षिणी हरियाणा में भी हजारों नई ढाणियां आबाद हो गई हैं। (विघ्न)

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में वायदा किया हुआ है कि ढाणियों में बिजली के कनैक्शन देने के लिए कंज्यूमर्ज से लाईन का कोई खर्चा नहीं लिया जायेगा और मंत्री जी कह रहे हैं कि पैसे भरने पर कनैक्शन दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, 4-5 साल पहले महात्मा गांधी विद्युत परियोजना चालू की गई थी लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में इस परियोजना के तहत कार्य किए गए लेकिन मेरे हल्के फतेहाबाद की ढाणियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि राजीव गांधी विद्युत परियोजना से हमारे जिले को वंचित न रखा जाए। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे हल्के की ढाणियों को लाईन के चार्जिज लिए बगैर डोमैस्टिक लाईन के कनैक्शन दिए जायें।

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, जो मुख्य समस्या है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि लोग ढाणियों में बस जाते हैं। गांवों में बिजली बोर्ड द्वारा 11 से 12 घंटे बिजली की सप्लाई दी जाती है और एग्रीकल्चर सैक्टर में आठ घंटे बिजली दी जाती है। इसलिए वे ढाणियों में रहने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें भी गांवों की तरह 11 से 12 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है। वे यह चाहते हैं कि उन्हें भी 11 से 12 घंटे गांवों के पैटर्न पर बिजली दी जाये। इस बारे में मैं पूरे सदन और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने अब तक 19 हज़ार ढाणियों को बिजली दे दी है और जो बाकी रह गई हैं उनको हम अगले वित्त वर्ष में बिजली दे देंगे।

श्री बलवान सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो महात्मा गांधी विद्युत परियोजना है क्या उसे फतेहाबाद जिले में भी लागू किया जायेगा ?

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, यह एक सैपरेट प्रश्न है इसलिए इसके लिए माननीय सदस्य अलग से नोटिस दें।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेनीफैस्टों में यह लिखा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जिन लोगों ने अपने खर्चे पर कनैक्शन लिये थे हम उनके द्वारा खर्च की गई राशि को उनके अगले बिलों में एडजस्ट करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य सही है।

राव नरबीर सिंह : स्पीकर सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनीफैस्टो में जो-जो घोषणाएं की हुई हैं हम उन सभी को भारतीय जनता पार्टी के इस पांच वर्ष के शासन काल में पूरा करने का काम करेंगे।

श्री रणबीर गंगवा : स्पीकर सर, हमारे प्रदेश का किसान हमारा अन्न दाता है वह अपने खेत के अंदर ढाणी बनाकर रहता है। खासकर हिसार, फतेहाबाद, बरवाला, नलवा, आदमपुर और उकलाना के क्षेत्र में कम से कम 20 प्रतिशत लोग ढाणियों में रहते हैं। इनको अभी तक भी बिजली के कनैक्शन नहीं मिले हैं जिसके अभाव में इनको आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अंधेरे में आदिवासियों की तरह जीवनयापन करना पड़ रहा है। उनके पास बिजली की सुविधा न होने के

कारण उनके बच्चे मोबाईल और इंटरनैट की सुविधा से भी वंचित है जिस कारण वे विकास की इस दौड़ में बुरी तरह से पिछड़ जायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने खर्च पर इन ढाणियों में बिजली के कनैक्शन देने का काम करेगी ? इन लोगों के पास पैसे का इतना बंदोबस्त नहीं होता कि ये बिजली की लाईन को खड़ी करने के लिए सरकार को पैसा दे सकें। जब मैं राज्य सभा का सदस्य था उस समय मैंने अपने एम.पी. लैड फण्ड से बहुत सी ढाणियों में बिजली की सुविधा प्रदान करवाई थी लेकिन एम.एल.एज़. को इस प्रकार का कोई फण्ड नहीं दिया जाता है जिससे इस प्रकार के कामों को अंजाम दिया जा सके। इसके साथ-साथ मैं सरकार से यह भी रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि एम.एल.एज़. के लिए भी एम.पी. लैड फण्ड की तरह विशेष फण्ड की व्यवस्था की जाये उसमें चाहे आप पांच करोड़ रूपये के बजाये चार करोड़ रूपये का प्रावधान कर दिया जाये लेकिन ऐसा विशेष फण्ड एम.एल.एज़. के लिए होना चाहिए जिससे वह अपने हल्के में इस प्रकार के विकास के छोटे-छोटे काम करवा सके। मैं माननीय मंत्री जी से पुन: पूछना चाहता हूं कि क्या वे इन ढाणियों में जल्दी से जल्दी बिजली की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान करेंगे ?

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी 11 व्यक्तियों की ढाणी है और जिन्होंने बिजली का डोमैस्टिक कनैक्शन लेने के लिए एप्लाई किया हुआ है उनको वरिष्ठता के आधार पर डोमैस्टिक कनैक्शन के नॉर्म के हिसाब से कनैक्शन रिलीज कर दिये जायेंगे। आने वाले वित्त वर्ष में तकरीबन सभी को कनैक्शन मिल जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, आज किसान जो कि देश का अन्नदाता है वह ही अन्धेरे में सोने पर मजबूर है जबकि आपके मैनीफैस्टो में भी है कि आप ढाणियों में लाईट देंगे। मेरा प्रश्न केवल यह है कि क्या सरकार अपने खर्चे पर किसानों को ढाणियों में बिजली के कनैक्शन देगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो एक दिन में बिना मंजूरी के ढाणी बसा लेते हैं उनको एक दिन में तो कनैक्शन नहीं दिया जा सकता। वे ऐप्लाई कर दें उनको कनैक्शन दिया जायेगा। हमारे माननीय सदस्य श्री बलवान सिंह ने जो महात्मा गांधी विद्युत परियोजना का जिक्र किया था तो उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस नाम की कोई परियोजना हरियाणा में नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, एक दिन में कोई ढाणी कैसे बस सकती है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि ढाणी तो एक दिन में बस जाती है लेकिन बिजली का कनैक्शन देने में तो टाईम लगेगा। अब श्रीमती सीमा त्रिखा अपना प्रश्न पूछें।

Revival of Historical and Tourist Site

***110. Smt. Seema Trikha :** Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government

[श्री राम बिलास शर्मा]
to revive the historical and famous tourist site, Badkhal Lake Faridabd; if so, the time by which aforesaid proposal is likely to be materialized ?

पर्यटन मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, फरीदाबाद की बड़खल झील के पुर्नउद्धार की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहन सीमा त्रिखा विधायक को बताना चाहता हूँ कि यह प्रश्न फरीदाबाद की बड़खल झील के विकास से संबंधित है। यह बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर अभी 15 दिन पहले एक बहुत सफल सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन हुआ था। यहाँ पर 13.50 लाख लोगों ने इस मेले में भागीदारी की और लगभग 20 देशों के लोग हरियाणा में इस मेले में सिरकत करने आये और यह हरियाणा ट्यूरिज्म का एक बहुत बड़ा सफल इवैंट रहा। हमारी आदरणीय बहन सीमा त्रिखा बड़खल को और ज्यादा विकसित करने की बात कह रही हैं, सरकार इस पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है। इसके विकास के लिए 21 मार्च, 2015 को हमने प्रधान सचिव वन एवं जीव विभाग, प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, प्रधान सचिव स्थानीय निकाय विभाग, महानिदेशक पर्यटन विभाग तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि इन सबके साथ बड़खल, सूरजकुंड का और विस्तार करने के लिए एक बैठक आयोजित की है और सरकार आने वाले दिनों में हरियाणा में ट्यूरिज्म पर पूरा फोकस करेगी। मोरनी से लेकर माधोगढ़ तक तथा ढोसी के पहाड़ से लेकर च्यवन ऋषि के आश्रम तक काम करेगी। बहन किरण चौधरी मुस्करा रही हैं क्योंकि माधोगढ़ इनका प्रिय प्रोजैक्ट रहा है और ये उसको पूरा नहीं कर पाई थी लेकिन हम उसको कर रहे हैं। इस प्रोजैक्ट के लिए किरण चौधरी जी पिछली सरकार में जमकर लड़ी थी उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। हरियाणा सरकार ट्यूरिज्म के ऊपर पूरा ध्यान दे रही है और आने वाले दिनों में हम और भी आगे बढ़ेंगे। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है और एक तरफ शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हैं और दूसरी तरफ च्यवन ऋषि का आश्रम ढोसी का पहाड़ है। आने वाले दिनों में हम ट्यूरिज्म के विस्तार के लिए पूरी तरह से चिंतित हैं।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। बड़खल झील को देख कर बड़ा दुख का अहसास हो रहा है। मैं इस सदन के सामने यह बात कहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों में इस इलाके का बहुत शोषण किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत छोटी सी बात है कि यह वह क्षेत्र रहा जहां पर माईनिंग सक्रिय रही, यह वह क्षेत्र रहा जहां पर जंगलों को काटा गया। जब हम छोटे थे तो सभी किताबों में एक कहानी पढ़ते थे कि एक प्यासा कौआ था वह पानी पीने के लिए एक मटके पर गया, मटके में पानी कम था, तो उस कौऐ ने उस मटके में कंकर डाले और पानी ऊपर लाया। बहुत अफसोस है कि पिछले 10 वर्षों में वहां के पत्थर निकाल कर वहां के पानी को नीचे ले जाने का काम किया गया। उन 10 वर्षों की सजा आज उस विधान सभा के लोग भुगत रहे हैं। वहां पर अगर हम बड़खल झील को विकसित करते हैं तो मेरा माननीय से निवेदन यह है कि जहां हम एक तरफ तो टूरिज्म का स्कोप डिवैलप करते हैं दूसरे तरफ हम पर्यावरण के लिए बहुत मजबूती पैदा करेंगे और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूं वह है पानी जो बहुत इम्पोरटैंट है। वहां पानी का स्तर इतना गिर चुका है कि इसको डिवैलप करने से हमारा जो वाटर लेवल है वह किसी हद तक ऊपर पहुँचेगा। मैं केवल बड़खल विधान सभा के ढाई लाख लोगों की डिमांड की बात नहीं कर रही। मैं पूरे

जोन के 15 लाख लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं कि पहले इस इलाके का जो इतना शोषण किया गया परन्तु अब आप जैसे मजबूत हाथों में कमान है। मैं चाहती हूं कि आपके माध्यम से इस झील को निखारने का इसको भरने का और सम्पूर्ण तरीके से जिसे हम सफल प्रयास कहते हैं वह जनता को सौंप सकें। ऐसी मैं सरकार की तरफ से उम्मीद करती हूं। दूसरी बात जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूं बड़खल झील ऋषि पराशर की तपो भूमि पर है और वहां पर ऋषि पराशर का बहुत प्राचीन मन्दिर भी है। यह ऐसी झील है जिसके साथ न केवल पर्यावरण, ना केवल टूरिज्म बल्कि धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप देखें कि दिल्ली को भारत का दिल कहते हैं तो हरियाणा से सटा हुआ बड़खल का इलाका लंग्स का काम करता है। अगर आप सबके ध्यान में हो पिछले कई वर्षों में फरीदाबाद का नाम मैं कहुंगी इण्डिया के मानचित्र पर नहीं बल्कि विश्व के मानचित्र पर रहा और बहुत बड़ा रैवैन्यू फरीदाबाद हरियाणा को देता रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में फरीदाबाद का इतना शोषण हुआ कि वह बेचारा बनकर रह गया। मेरा निवेदन है कि इस बड़खल झील को भरने के सफल प्रयास किए जाएं। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। धन्यवाद।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी विधायिका ने जो बड़खल झील में पानी की व्यवस्था करने की बात की है हम इस पर विचार कर रहे हैं। उनका आंकलन ठीक है कि पहले झील में पानी आता था वह भी रुक गया। इस बड़खल झील में पानी भरा जाए यह भी हमारे अगले विस्तार के अन्दर एक बिन्दु है।

श्री मनीष ग्रोवर : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहन सीमा त्रिखा ने बड़खल झील और पर्यटक के बारे में और सूरजकुंड और फरीदाबाद के बारे में जिक्र किया। जब बहन सीमा त्रिखा पिछले 10 साल की हालात बता रही थी तो मेरे विपक्ष के मित्र उनकी बात को सुनकर हंस रहे थे उनको मैं देख रहा था। 10 सालों में इन्होंने पर्यटकों की हालात को चिन्ताजनक किया है। रोहतक के अन्दर तिलयार झील जो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर बनी है उसकी हालत जाकर देखें पूर्व मुख्यमंत्री खुद वहीं रोहतक में रहते हैं, झील का पानी इतना गन्दा है कि वहां पर कोई पर्यटक नहीं आ रहा। हरियाणा में यह चर्चा थी कि हरियाणा विकास की तरफ से नम्बर-1 है और तिलयार की हालत बड़ी चिन्ताजनक है। जिसकी वजह से वहां कोई पर्यटक नहीं आ रहा है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ग्रोवर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री मनीष ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल ये है कि तिलयार झील की स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पर तिलयार झील है। क्या उसमें सुधार करने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री मनीष ग्रोवर ने तिलयार के बारे में जो प्रश्न पूछा है। वहां महंत सूर्योनाथ का डेरा होता था और एक मुख्यमंत्री जी उनसे नाराज हो गये थे तब उन्होंने उन किलों में वह डेरा बनाया था और वह कहा करते थे कि सूर्योनाथ से पूछ लीजिए कि उसके किलों में मैंने झील खुदवाई थी। यह तिलयार बड़ा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह चौधरी बंसीलाल जी ने अपने समय में बनाई थी।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में इस की स्थिति ठीक नहीं रही। हम पर्यटन विभाग के विस्तार की योजना में तिलयार को भी आने वाले समय में शामिल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सप्लीमैंट्री जल्दी से जल्दी की जाये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री होने के नाते प्रश्न तो नहीं पूछ सकता लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आंकड़े तो बता रहे हैं कि सारा का सारा पैसा रोहतक में लगा दिया अगर रोहतक में भी विकास नहीं हुआ तो पैसा कौन खा गया? यह तो सदन में बताया जाये। (हँसी)

Construction of Sanskrit School

***125. Shri Gian Chand Gupta :** Will the Education Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the foundation stone of the Sanskrit School was laid in the premises of Mata Mansa Devi by the then Union HRD Minister Dr. Murali Manohar Joshi during the year 2003; and

(b) if so, the status thereof together with the time by which the above said Sanskrit school is likely to be constructed ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

डॉ0 मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा 27 जनवरी, 2003 को श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के परिसर में 2 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले संस्कृत महाविद्यालय तथा सभी भाषा अकादमियों के कार्यालय स्थापित किये जाने का प्रावधान था। संस्कृत भवन के निर्माण का कार्य धनराशि निर्धारित न होने के कारण आरम्भ नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ज्ञान चन्द गुप्ता जी की बात सही है कि उस समय के केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने दिनांक 27 जनवरी, 2003 में माता मनसा देवी कॉम्प्लैक्स (पंचकूला) में संस्कृत भवन बनाने की नींव रखी थी। अध्यक्ष महोदय, बाद की आने वाली सरकारों ने उस पर न ध्यान दिया और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही की।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता (पंचकूला) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 27 जनवरी, 2003 को आदरणीय केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने माता मनसा देवी के परिसर में संस्कृत भवन की नींव रखी थी उसके बाद उसका नक्शा बनाया गया। उसकी पूरी डिटेल तैयार हो गई और संस्कृत भवन के लिए दो एकड़ जमीन दे दी गई लेकिन बदकिस्मती से सरकार बदल गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार बदलने के पश्चात शिलान्यास के लिए

रखा गया पत्थर भी गायब हो गया। अध्यक्ष महोदय, उसका क्या कारण था ? क्या संस्कृत ऋषि मुनियों की भाषा या देवी देवताओं की भाषा नहीं है? अध्यक्ष महोदय, आज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर संस्कृत भाषा को सबसे उपयुक्त भाषा कहा जाता है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जल्दी-जल्दी सवाल पूछे क्योंकि क्वैश्चन ऑवर का टाईम होने वाला है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के द्वारा जो संस्कृत विद्यालय का शिलान्यास किया गया था उसको कैंसिल क्यों किया गया ? अध्यक्ष महोदय, उसके क्या कारण थे? पत्थर रखने के बाद और जगह भी अलॉट होने के बाद उसको कैंसिल क्यों किया गया इसके क्या कारण थे ? आर.टी.आई. के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि later on Education Department starting construction their building in Sector-14, Panchkula. लेकिन पंचकूला के अंदर ऐसी कोई संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग शुरू नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी सरकार माता मनसा देवी के परिसर में जो लाखों भक्तों का श्रद्धा का केन्द्र है उसके लिए कोई विद्यालय सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा तत्व का सवाल पूछा है। क्या हुआ और क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि नेता की नीयत जब खराब होती है तो सरकार के अधिकारी/कर्मधारी बेचारे क्या कर सकते हैं ? संस्कृत भाषा के बारे में नासा का रिसर्च है कि it is the only perfect language of the computer. संस्कृत की जो भाषा है, सरकार उसका लेखा-जोखा तो नहीं देख सकती है। माननीय सदस्य श्री ज्ञानचंद गुप्ता की जो भावना है वह बिल्कुल सही है कि पिछली सरकारों ने संस्कृत के ऊपर विचार नहीं किया लेकिन हमारी सरकार इस पर जरुर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Repir of Sports Stadium

*113. **Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the sports stadium in village Chautala, District Sirsa; and

(b) if so, the time by which the above-said work of repair will be started ?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) मुरम्मत का कार्य आगामी वित्त वर्ष में करवा दिया जायेगा।

Land of Village Badkhalsa

***130. Shri Jai Tirath :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release the land of village Badkhalsa which was acquired with other 8 villages for the Rajiv Gandhi Education City during the year 2005; if so, the time by which it is likely to be released ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : जी, नहीं।

To shift the Bus Stand of Panipat

***121. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Bus Stand of Panipat from present place to avoid traffic jams and accidents ?

परिवहन मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी।

To Connect Dharodi Minor with Bhakra Link Canal

***152. Shri Pirthi Singh :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the Dharodi Minor with the Bhakra link Canal, if so, the time by which the said minor is likely to be connected ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Teachers in Mewat

***134. Shri Naseem Ahmed :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that there is an acute shortage of teachers in Mewat; if so, the time by which the said shortage of teachers is likely to be met out ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी, मेवात जिले में अध्यापकों की भारी कमी है और स्थिति इस प्रकार है :-

पद	कुल स्वीकृत पद	कुल रिक्तियां	वास्तविक रिक्तियां (अतिथि अध्यापक के अतिरिक्त)	विवरण
प्राध्यापक	697	392	336	392 रिक्त पदों में से 56 अतिथि प्राध्यापक कार्यरत है।
मास्टर	724	417	202	417 रिक्त पदों में से 216 अतिथि मास्टर कार्यरत हैं।
जे.बी.टी. अध्यापक	3514	1747	836	1747 रिक्त पदों में से 911 अतिथि जे.बी.टी. अध्यापक कार्यरत हैं। हरियाणा विद्यालय चयन बोर्ड द्वारा 1081 आवेदकों की आगामी अनुशंसा प्राप्त हुई है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार नियुक्ति पूर्व जांच पड़ताल प्रक्रिया जारी है, नियुक्ति पत्र माननीय उच्च न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त होने उपरांत जारी किये जाने हैं।
सी.एण्ड वी. अध्यापक	626	277	186	277 रिक्त पदों में से 91 सी. एण्ड वी. अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं।
कुल	**5561**	**2833**	**1560**	अध्यापकों के 2833 रिक्त पदों में से कुल 1273 अतिथि अध्यापक कार्यरत हैं तथा 1081 जे.बी.टी. अध्यापकों की अनुशंसा प्राप्त हुई है, जो कि प्रक्रिया अधीन है। नियुक्तियां वैज्ञानिक जांच पड़ताल के बाद माननीय उच्च न्यायालय से अनुमोदन उपरांत जारी कर दी जाएगी।

सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत रिक्त पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकुला द्वारा भरे जाने हैं, जिसका पुनर्गठन शीघ्र किया जा रहा है। इसलिए विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि नहीं दी जा सकती, हालांकि, पदोन्नति कोटे के अंतर्गत प्राध्यापकों के 177 पद, मास्टरों के 67 पद तथा सी. एण्ड वी. अध्यापकों के 64 पद (कुल 308 पद) शीघ्र भरे जाने हैं जिनके लिए विभागीय पदोन्नति/समिति बैठकों/पदोन्नति के आवेदन आमन्त्रित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

To Construct a 'Barrage' at Yamuna Canal

***163. Shri Zakir Hussain** : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government

[Shri Zakir Hussain]
to construct a 'Barrage' at Yamuna Canal near Palwal or Hodel to provide Irrigation water to the farmers of District Faridabad, Palwal and Mewat; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी।

Construction of Stadium

***168. Shri Anoop Dhanak** : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a stadium in village Balak of Uklana Constituency for which 6-5 acreage of land has already been provided, if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान् जी। फिर भी हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता नीति, 2015 के तहत ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत में 'योग एवं व्यायामशाला' नाम का एक नया कार्यक्रम चलाया गया है। जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 2 एकड़ या इससे अधिक भूमि में मिनी स्टेडियम विकसित किया जायेगा।

To Supply Round the Clock Electricity

***220. Shri Tek Chand Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the land of village Fatehpur Biloch, Bogaula etc. of Prithla Constituency has been acquired by the Government to set up a 66 KV Power House; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to supply round the clock electricity in the abovesaid villages; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं, श्रीमान।

(ख) फतेहपुर बिलोच तथा बगौला गांवों को विभाग की पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार शहरी पद्धति पर बिजली आपूर्ति देने के लिए विचार किया जा सकता है।

To Open an I.T.I.

***236. Shri Udai Bhan** : Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government

to open an Industrial Training Institute in village Dighout of Hodel Assembly Constituency; if so, the details thereof ?

औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान् जी।

Special Package for Mewat

***145. Sh. Rahish khan :** Will the Finance Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to announce a 'special package' for Mewat District which is most backward district in the State; and

(b) if so, the time by which it is likely to be announced ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : जी नहीं।

Shortage of Doctors

***227. Smt. Shakuntala Khatak :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) wheather it is a fact that there are 11 sanctioned posts of doctors in the Government Hospital, Kalanaur (Rohtak) but only two doctors have been posted in the said Hospital; and

(b) if so, the time by which the vacant posts of the doctors are likely to be filled up ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी। सामान्य अस्पताल कलानौर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का एक स्वीकृत पद भरा हुआ है और चिकित्सा अधिकारियों के 11 स्वीकृत पदों में से 7 भरे हुये हैं।

(ख) नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक उपलब्ध होंगे तो चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर लिये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Facility of Stay for the Visitors

***358. Shri Jaswinder Singh Sandhu :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

[Shri Jaswinder Singh Sandhu]
Government to provide the facility of stay for the visitors in the Saraswati Shrine of Pehowa Constituency; if so, the details thereof ?

पर्यटन मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। पेहवा में सरस्वती तीर्थ से 3 किलोमीटर के दूरी पर अंजन यात्रिका के नाम से एक पर्यटक स्थल जिसमें 10 कमरे उपलब्ध हैं, पहले से ही स्थापित हैं।

Villages falling under Balsamand Distributory

***270. Shri Ranbir Gangwa :** Will the irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply water to the villages falling under the Balsamand Distribuatory in Nalwa and Adampur Constituency ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, नलवा और आदमपुर विधान सभा क्षेत्र में बालसमंद शाखा के अन्तर्गत आने वाले गांवों में पहले से ही विद्यमान नहरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

Demands of Computer Teachers

***406. Shri Ravinder Singh Baliala:** Will the Education Minister be pleased to state the action taken by the Government to accept the demands of the computer teachers togetherwith the time by which the demands of these computer teachers are likey to be accepted ?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : ये कम्प्यूटर शिक्षक जिनको सेवा-प्रदाताओं के द्वारा अनुबंध आधार पर लगाया गया था, कि मांगें निम्न अनुसार हैं :-

(i) 24000/- रुपये जमानत राशि जो कि सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्रत्येक कम्प्यूटर शिक्षक से अनुचित तरीके से प्राप्त की गई ;

(ii) कर्मचारियों के मासिक वेतन में से अनुचित ढंग से ई.एस.आई. (का हिस्सा) काटना ;

(iii) सेवा प्रदाताओं द्वारा वेतन नहीं दिया जाना ;

(iv) उक्त कर्मचारियों की सेवाओं को कम्पनियों के अधिकार क्षेत्र से निकालकर विभाग में विलय करना;

पहले तीन मुद्दों की विभाग द्वारा जांच करवाई गई और जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार सेवा प्रदाताओं को 24000/- की जमानत राशि लौटाने को कहा गया और कम्प्यूटर शिक्षकों के वेतन में से ई.एस.आई. को नियोक्ता का हिस्सा काटने से मना किया गया। विभाग के इस निर्णय

के विरूद्ध सेवा प्रदाताओं ने आर्बिट्रेशन के लिए निवेदन किया और सिविल कोर्ट पंचकूला में चले गए। परिणामस्वरूप प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, जोकि अनुबंध के अनुसार आर्बिट्रेटर भी है, द्वारा आर्बिट्रेशन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई। 16-02-2015 के आर्बिट्रेशन निर्णय के अनुसार सेवा प्रदाताओं ने अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं की। अत: विभाग ने 16-02-2015 को सेवा प्रदाताओं को अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध समाप्त करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया। ये कम्प्यूटर शिक्षक सेवा प्रदाताओं के कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा शर्तें सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए अनुबंध द्वारा निर्धारित होती है। फिर भी आर्बिट्रेटर ने उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (iii) के संदर्भ में कम्प्यूटर शिक्षकों के पक्ष में निर्णय दिया है जिसे जल्द लागू किया जाएगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Refund of VAT

9. Shri Karan Singh Dalal : Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state—

(a) whether any excess refund of vat has been made in the Excise and Taxation Department during the last five years in the State;

(b) if so, the total amount involved with details thereof; and

(c) whether any action has been initiated or proposed to be initiated against the erring officials, firms and other persons involved ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत शून्य।

(ग) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Repair the Road

37. Shri Hari Chand Middha : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the road from Pandu-Pindara to village Nirjan and village Nirjan to village Khokhri of Jind Assembley Constituency which has been damaged completely; and

(b) if so; the by which the above-said roads are likely to be reconstructed ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी। पाण्डू-पिण्डारा से निर्जन गांव तक सड़क का पुनर्निर्माण सरकार के विचाराधीन है तथा गांव निर्जन से गांव खोखरी (हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड सड़क) के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कोई समय सीमा निश्चित नहीं है।

Appointment of Swami Ramdev as the Brand Ambassador

21. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state the terms and conditions set by the Government with respect to the appointment of Swami Ramdev as the Brand Ambassador of the State of promote Yoga together with the tangible benefits received by the state with his appointment so far ?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) : इस सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। नियम तथा शर्तें निर्धारित नहीं किए गए हैं। विस्तृत ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे।

Shortage of Doctors

62. Smt Rohita Rewri : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to meet out the shortage of doctors in Civil Hospital of Panipat; if so, the time by which shortage of doctors is likely to be met out ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : सामान्य अस्पताल, पानीपत में चिकित्सा अधीक्षक का एक स्वीकृत पद तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के चार स्वीकृत पद भरे हुये हैं जबकि चिकित्सा अधिकारियों के 42 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 27 भरे हुये हैं। नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक उपलब्ध होंगे तो चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के प्रयास कर लिये जायेंगे, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Outstanding External Development Charges

10. Shri. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) The amount of external development charges outstanding against the colonizers in the State till date together with the details thereof along with the name and address of the colonizers.

(b) whether there any violation of the condition imposed in the grant of licenses for the development of colonies in the State;and

(c) if so, the action taken or likely to be taken against such colonizers and erring officials responsible for such lapses ?

*मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी,

(क) राज्य के प्रत्येक उपनिवेशक के विरूद्ध आज तक बकाया बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) की राशि, उनके नाम तथा पते अनुबन्ध 'A' पर संलग्न हैं।

(ख) तथा (ग)नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग लाईसेंस प्रदान करते समय ईडीसी के भुगतान के लिए समय सीमा की अनुसूची मुहैया कराते हुए उपनिवेशक के साथ अनुबन्ध करता है। उपनिवेशक को या तो लाईसेंस देने के तीस दिन के भीतर एकमुश्त ईडीसी अन्यथा स्थगित ईडीसी की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान करना होता है। स्थगित ईडीसी के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या लाईसेंस की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार चार से पांच वर्ष के बीच रहती है। समय सीमा की अनुसूची में निहित समय अवधि के अन्दर ईडीसी के भुगतान में चूक के मामले में उपनिवेशक को तीन मास की अवधि के लिए 3% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त राशि दंड के रूप में भुगतान करनी होती है जो और तीन मास के लिए निदेशक द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

विभाग सुनिश्चित करता है कि लाईसेंसों का नवीकरण, भवन योजनाओं का अनुमोदन, आधिपत्य प्रमाण पत्र/आंशिक/अन्तिम पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि केवल ईडीसी की देय राशि, दण्डित ब्याज सहित वसूली के बाद प्रदान किए जाते हैं।

12.04.2012 को अधिसूचित राहत नीति के तहत उपनिदेशक को चार छ:माही किस्तों में बकाया देय राशि के भुगतान के लिए दो वर्ष का समय दिया जाता है, बशर्ते कि वह बकाया राशि, अतिदेय राशि व अब तक न देय राशि सहित कुल बकाया राशि के 25% के समकक्ष बैंक गारंटी प्रस्तुत करें।

विभाग द्वारा बकाया ईडीसी के भुगतान एवं अन्य कमियों के कारण 20 मामलों में (विवरण अनुबन्ध 'B' पर) उपनिवेशकों द्वारा की गई चूक के लिए लाईसेंस रद्द किए गए हैं।

Repair the Roads

38. Shri Hari Chand Middha : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether it is fact that road from Patiala chowk to Railway station and from Rama Krishan Mandir to Julani Railway crossing of

---

* उपरोक्त उत्तर के विवरण लम्बे होने के कारण लाईब्रेरी में रखवाए गए।

[Shri Hari Chand Middha]

Jind city has been damaged completely: and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the above-said road?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी। पटियाला चौक से रेलवे स्टेशन तक सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यद्यपि, रामा कृष्णा मन्दिर से जुलानी रेलवे फाटक तक सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

(ख) पटियाला चौक से रेलवे स्टेशन सड़क पर कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया जा सकता है। रामा कृष्णा मन्दिर से जुलानी रेलवे फाटक तक सड़क पर कोई विशेष मरम्मत की आवश्यकता नहीं है।

Universities Functioning in State

22. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Education Minister be pleased to state the total number of universities, both private as well as Government, operationg within the purview of the State ?

शिक्षा मंत्री (राम विलास शर्मा) :

श्रीमान् जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में 8 सरकारी विश्वविद्यालय और 18 निजी विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी गांव जॉट पाली, महेन्द्रगढ़ में चल रहा है।

सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम तथा पता	विश्वविद्यालय का प्रकार	स्थापना की तिथि तथा वर्ष
1.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	सरकारी विश्वविद्यालय	1956
2.	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	सरकारी विश्वविद्यालय	21.8.1975
3.	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	सरकारी विश्वविद्यालय	28.3.2003
4.	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, (सोनीपत)	सरकारी विश्वविद्यालय	18.8.2006
5.	डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत	सरकारी विश्वविद्यालय	26.4.2012
6.	इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)	सरकारी विश्वविद्यालय	7.9.2013

7.	चौ0 रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द	सरकारी विश्वविद्यालय	7.8.2014
8.	चौ0 बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी	सरकारी विश्वविद्यालय	6.8.2014
9.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांव जांट-पाली, महेन्द्रगढ़।	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009

निजी विश्वविद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम तथा पता	विश्वविद्यालय का प्रकार	स्थापना की तिथि तथा वर्ष
1.	ओ. पी. जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, गांव जगदीशपुर, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	23.3.2009
2.	आई.टी.एम. विश्वविद्यालय, सैक्टर 23-ए, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	21.10.2009
3.	एमिटि विश्वविद्यालय, गांव ग्वालियर, पंचगांव (नजदीक मानेसर), जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	26.4.2010
4.	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गांव सिलानी, तहसली सोहना जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	26.4.2010
5.	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, गांव सदोपुर, अम्बाला	निजी विश्वविद्यालय	29.10.2010
6.	एन.आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, 9 के.एम. माईलस्टोन, मेन एन.एच. 65, कैथल	निजी विश्वविद्यालय	27.9.2011
7.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
8.	एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, गांव औरंगाबाद, पलवल	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
9.	अंसल विश्वविद्यालय, सैक्टर-55, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
10.	श्री गुरु गोबिन्द सिंह विश्वविद्यालय, गांव बुढेश, जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
11.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
12.	जी.डी. गोयन्का विश्वविद्यालय, सोहना रोड़ गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
13.	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड़ गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013

[राम बिलास शर्मा]

14.	एस.आर.एम. विश्वविद्यालय, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
15.	अशोका विश्वविद्यालय, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	2.5.2014
16.	बी.एम.एल. मुंझाल, विश्वविद्यालय, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	2.5.2014
17.	अल-फलाह विश्वविद्यालय, धौज, फरीदाबाद	निजी विश्वविद्यालय	2.5.2014
18.	मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	निजी विश्वविद्यालय	6.8.2014

Ranneywell Water Project

63. Smt. Rohita Rewri : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for setting up a Rannywell water project in Panipat; if so, the time by which it is likely to be set up ?

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। इससे पूर्व पानीपत शहर में रैनीवैल परियोजना स्थापित करने के लिए 462.90 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव विचाराधीन था जो कि भारत सरकार को छोटे और मध्यम शहरों में शहरी बुनायदी ढांचे की विकास योजना के तहत अनुमोदन के लिए भेजा गया था, परन्तु भारत सरकार ने जून, 2014 के दौरान इस परियोजना को यह बताते हुए वापिस भेज दिया कि इस कार्यक्रम के परिवर्तन चरण के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को मंजूरी देने के आदेश 31.03.2014 को समाप्त हो चुके हैं।

Complaints at CM Windows

11. Shri Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the procedure of disposal off the complaints received at CM window in the various districts of the State; and

(b) whether any time frame has been fixed for disposal of such complaints ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी,

(क) राज्य के विभिन्न जिलों में सी.एम. विंडो पर प्राप्त शिकायतों को मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सिस्टम पर दर्ज किया जाता है। इन शिकायतों को मुख्यमंत्री शिकायत

निवारण सैल द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है। संबंधित विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी की सहमति से शिकायत पर अंतिम उत्तर/रिपोर्ट को सिस्टम पर निपटान तथा मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सैल के प्राधिकारियों के लिये डाल दिया जाता है। यदि रिपोर्ट संतोषजनक पाई जाती है और स्वीकार्य है, शिकायत का निपटान कर दिया जाता है।

(ख) संबंधित विभाग के लिए कार्यवाही रिपोर्ट के लिए एक मास का समय निर्धारित है। सरपंच/पंच के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें जिन पर एक जांच की आवश्यकता होती है, कार्यवाही रिपोर्ट के लिए तीन मास का समय दिया जाता है।

Construction of Stadium

39. Shri Hari Chand Middha : Will the Sports & Youth Affairs Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a sports stadium in village Manoharpur in the Jind Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the above-said sports stadium is likely to be constructed ?

खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) जीन्द विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव मनोहरपुर में खेल स्टेडियम के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए इसके निर्माण हेतु कोई देय समय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Total Number of Complaints at CM Window

23. Shri Parminder Singh Dhull
Smt. Kiran Choudhary
Shri Naseem Ahmed : Will the Chief Minister, be pleased to state the total number of complaints received so far at the Chief Minister's window together with the district-wise breakup thereof along with the number of complaints redressed so far ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी,

सी.एम. विंडो पर दिनांक 10.03.2015 तक 35360 शिकायतें/मांगें/सुझाव दर्ज़ हुई जिनमें से 16557 का निवारण कर दिया गया है। जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

[श्री मनोहर लाल]

जिला	शिकायतों/मांगों/ सुझावों की संख्या	निवारण की गई शिकायतें/मांगें/सुझाव
अम्बाला	1138	516
भिवानी	2154	890
फरीदाबाद	1602	807
फतेहाबाद	1086	486
गुड़गांव	1188	550
हिसार	1873	825
झज्जर	1123	557
जीन्द	1538	724
कैथल	1735	769
करनाल	2942	1488
कुरुक्षेत्र	1691	826
महेन्द्रगढ़	2143	1094
मेवात	807	382
पलवल	1300	554
पंचकूला	901	396
पानीपत	3323	1555
रेवाड़ी	1974	954
रोहतक	1388	630
सिरसा	2002	997
सोनीपत	1756	770
यमुनानगर	1295	666
चण्डीगढ़ (मुख्यालय)	401	121
कुल योग	35360	16557

Installation of CCTV Cameras

64. Smt.Rohita Rewri : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to install the CCTV cameras in the main market of the Panipat city; if so, the time by which these cameras are likely to be installed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान् जी। उपायुक्त, पानीपत की अध्यक्षता में 10.03.2015 की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है कि पानीपत के मुख्य बाजार तथा गोल चक्करों पर 73 स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे 30.09.2015 तक लगा दिये जायेंगे, जिनका खर्चा नगर निगम, पानीपत वहन करेगा।

To Waive off Water and Sewerage Charges

12. Shri Karan Singh Dalal : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to waive off the water and sewerage charges of SC/ST families in all the cities of the State; if so, the details thereof togetherwith the time it is likely to be materialized ?

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी। हरियाणा के सभी शहरों में अनुसूचित/अनुसूचित जनजातिओं के परिवारों के पानी तथा सीवरेज शुल्क को माफ करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विधाराधीन नहीं हैं।

Reconstruction of Road

40. Shri Hari Chand Middha : Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether the road from Choudhary Devi Lal Chowk to Old Sabzi Mandi turn via Timber Market, Chakkar Road and Ramrai Gate in Jind city have been damaged completely; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the above said road ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान् जी,

(क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी, चौधरी देवीलाल चौक से रामराय गेट की ओर जाते हुए बरास्ता टिम्बर मार्किट सड़क के कुछ हिस्से की विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। नगर परिषद, जीन्द को निर्देश दिये गये हैं कि इस सड़क की मरम्मत इत्यादि करवाकर सुचारू यातायात के अनुकूल रखें। नगर परिषद को सड़क की विशेष मरम्मत हेतु प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं।

Total Expenditure on Repairing the Roads

24. Shri Parminder Singh Dhull : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state when the link-roads from Julana Mandi to village Devrar

[Shri Parminder Singh Dhull]
(Farmana stand) and Kinana to Buana via Brarkhera were constructed together with the total expenditure incurred by the Government in repairing the aforesaid roads since their construction ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, जुलाना मण्डी से गांव देवसर (फरमाना स्टैंड) 1972-73 तथा किनाना से बुआना वाया बराड़ खेड़ा सड़क 1978-79 के दौरान निर्मित की गई थी। अब तक, इनके निर्माण में 97.39 लाख रुपये खर्च किये गए हैं।

Covering of Drain

65. Smt. Rohita Rewri : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to cover the under construction drain No.1 in Panipat city, if so, the time by which it is likely to be covered ?

सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान् जी। पानीपत ड्रेन को कवर नहीं किया जा रहा है। परन्तु इसके दोनो तरफ पर्याप्त ऊंचाई की सीधी रेलिंग लगाई जा रही है ताकि ड्रेन में कूड़ा-कर्कट न फेंका जा सके तथा इसकी आवश्यकता अनुसार सफाई की जा सके।

घोषणा-

अध्यक्ष द्वारा

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(i)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

> 'मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे गुड़गांव में आयोजित होने वाले कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लेना है, इसलिए मैं हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र दिनांक 12 तथा 13 मार्च, 2015 को सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे परिस्थिति के अनुसार छुट्टी देने की कृपा करें'

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

> कि हरियाणा विधान सभा के सत्र में 12 तथा 13 मार्च, 2015 को छुट्टी देने की अनुमति दी जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

(ii)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री बिक्रम सिंह यादव, सहकारिता राज्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

'मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे गुड़गांव में आयोजित होने वाले कृषि शिखर सम्मेलन में भाग लेना है, मैं हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र दिनांक 13 मार्च, 2015 को सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे परिस्थिति के अनुसार छुट्टी देने की कृपा करें'

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा विधान सभा के सत्र में 13 मार्च, 2015 को छुट्टी देने की अनुमति दी जाये ।

आवाजें : ठीक है जी।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

(iii)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री उमेश अग्रवाल, विधायक से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ :-

'मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से मैं हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र दिनांक 12 मार्च, 2015 को सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए मुझे परिस्थिति के अनुसार छुट्टी देने की कृपा करें'

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

कि हरियाणा विधान सभा के सत्र में 12 मार्च, 2015 को छुट्टी देने की अनुमति दी जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

(प्रस्ताव पारित हुआ)

विभिन्न मामलों को उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 25 श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक का मनुष्यों व पक्षियों पर ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में आया है, वह नामंजूर है। इसके अलावा दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक का हरियाणा प्रदेश के जिला

पलवल व मेवात के प्रत्येक गांव में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का बहुत तेज गति से प्रसार के बारे में आया, वह भी नामंजूर है। इनके अलावा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री परमिन्दर सिंह ढुल, विधायक, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक, प्रो0 रविन्द्र बलियाला, विधायक और श्री बलवान सिंह, विधायक का सरकारी नौकरी में भर्ती न करने व सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त रोष के बारे में आया है, यह विचाराधीन है। इसके अलावा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री परमिन्दर सिंह ढुल, विधायक, श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक और प्रो0 रविन्द्र बलियाला, विधायक का हरियाणा प्रदेश के गांवों में स्थित तालाबों में इकट्ठे हुए गंदे पानी की निकासी का कोई प्रबन्ध न होने के बारे में आया है, यह भी विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री जसविन्द्र सिंह संधू, विधायक, प्रो0 रविन्द्र बलियाला, विधायक, श्री परमिन्दर सिंह ढुल, विधायक और श्री बलवान सिंह, विधायक का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग आधार पर लगे कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं दिये जाने के बारे में आया है, यह भी विचाराधीन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने भी विभिन्न विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे रखें हैं, कृपया करके आप उनका भी स्टेटस बता दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, उनके बारे में आपको कल बता दिया जायेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं और जो आपने हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रिजैक्ट किये हैं, उनके बारे में भी बताइये।

श्री अध्यक्ष : मैडम, मेरे पास अभी आये नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो आ गये हैं और आपके पास आये नहीं है, ये कैसे हो गया ? यह तो कमाल की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैडम, उसकी सूचना आपको दे दी गई है। (विघ्न) मैंने कल जैसे ही आपको जानकारी देने का प्रयास किया, उस समय आपने जानकारी ली नहीं, उस समय आप लोगों ने शोर शराबा किया जिसके कारण आपको जानकारी नहीं मिल सकी। (विघ्न) मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर किये हैं, उनको सदन के पटल पर बतायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ध्वनि प्रदूषण की समस्या से बच्चे और बूढ़े बेहद परेशान हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नामंजूर हो चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप सदन को बतायें कि कौन से इश्यू के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने रिजैक्ट किये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैडम जी, आपके प्रस्ताव विचाराधीन हैं। प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा ने कहा था कि हम हरियाणा के सभी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे लेकिन आज सरकार अपनी घोषणा को इम्प्लीमेंट करने से मुकर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ढुल जी, अभी आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विचाराधीन है। आप बैठिए।

श्री अध्यक्ष : रेणुका जी, आप बैठिए। अगर आप गवर्नर अभिभाषण पर बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। (विघ्न) आप इस बारे में अपना प्रस्ताव लगा सकती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जीरो ऑवर चल रहा है। आप हमारी बात सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुन लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप सभी बैठें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, सदन में पूर्व सत्र के दौरान आपने और मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि पक्ष और विपक्ष को बोलने का पूरा समय दिया जाएगा। खासकर उन सदस्यों को जो पहली बार चुनकर आए हैं उनको अधिक समय दिया जाएगा चाहे वह सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष का सदस्य हो। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो नये मैम्बर्स हैं उनको अपने विधानसभा क्षेत्र की बात ठीक ढंग से रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। कल जब हमारी पार्टी के उपनेता अपनी बात सदन में रख रहे थे तो उस वक्त कम समय बचा था। कम समय की वजह से उनको अपनी बात खत्म करनी पड़ी। उन्होंने बहुत-सी बातें सदन को बतानी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, विधायक जी ने अपनी बात पूरी कर ली थी। मुझे सदन को तीन मिनट पहले ही स्थगित करना पड़ा था। आपके तीन मिनट बच गए थे। उनको पूरा समय दिया गया था। मैंने इनको 7 मिनट का बोलने का समय दिया था लेकिन फिर भी ये 20-22 मिनट तक बोलते रहे और इन्होंने अपनी सभी बातें सदन में रख ली थी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, कल आपने हमें बोलने का कम समय दिया था। अब हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सभी मैम्बर्स को जब बजट आए तो उस पर बोलने के लिए ज्यादा समय दें ताकि वे हाऊस में अपनी बात रख सकें। आपने सभी मैम्बर्स के लिए केवल 7-7 मिनट का समय निश्चित कर रखा है लेकिन यह समय मैम्बर्स के लिए बहुत कम है और इसमें हम अपनी बात को पूरी तरह से नहीं कह सकते। आपको मैम्बर्स को खुला समय देना चाहिए चाहे आपको हाऊस को एक-दो दिन के लिए और क्यों न बढ़ाना पड़े। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष जी, यह जीरो ऑवर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आज दो प्वाइंट्स पर बोलना चाहती हूँ। पहला आज आपने जो हमारी कॉलिंग अटैनशन मोशन को रिजैक्ट कर दिया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने इन्हें किस इश्यु पर रिजैक्ट किया है। दूसरा मैंने 13 चिट्ठियां लिखी हैं जोकि पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की समस्याओं से संबंधित हैं। मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखी थी। आज मैं

[श्रीमती किरण चौधरी]

दोबारा से से इन चिट्ठियों को सदन के पटल पर रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रही हूँ ताकि मुझे एक एकनोलिजमैंट मिल जाएं। मैं ये सारी समस्याएं जनहित के लिए उठा रही हूं। ये मेरी कोई पर्सनल समस्याएं नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इनका कोई हल न निकाल सकें तो कम से कम हमें एक एकनॉलिजमैंट तो दे दें। इसके साथ-साथ हमारे जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं आप उनके बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष : मैडम किरण चौधरी जी, आपका जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की कर्मचारी विरोधी नीति के बारे में है। प्रथम दृष्टि में यह पाया है कि यह विषय हाल की घटनाओं से संबंधित नहीं है इसलिए इस मामले को आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, बजट भाषण 2015 और डिमांड्ज पर जब चर्चा होगी उस समय उठा सकती हैं। आपका दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यूरिया खाद के बारे में हैं। इस विषय में भी अति आवश्यकता का अभाव है इसलिए इस विषय को आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, बजट भाषण 2015 और डिमांड्ज पर सामान्य चर्चा के दौरान उठा सकते हैं। इसलिए इन दोनों विषयों को फिलहाल रिजैक्ट किया जाता है। इस बारे में आपको सूचना पहले ही दी जा चुकी है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन हरियाणा के गावों में शादी और ब्याह के दौरान जो डी.जे. बजता है उसको बन्द करने के बारे में दिया है। इसके बजने से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है इसलिए इनको बन्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पशु और पक्षियों पर भी बुरा असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, डी.जे. तो काफी समय से बज रहे हैं और ऐसी तो बात नहीं है कि डी.जे. गावों में अभी बजने शुरू हुए हों। अचानक आज ऐसी क्या बात हो गई कि आप इसको अब बन्द करवाना चाहते हैं। यह आपका कालिंग अटैंशन मोशन का विषय नहीं था।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे को भी बोलने का मौका दिया जाए।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो तारीख को सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया है उसके बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दिया था जिसमें यह कहा गया था कि बाकी जिलों में तो विकास हो रहा है लेकिन हमारे जिले में विकास नहीं हो रहा है इसके लिए सरकार की तरफ से कोई रोड मैप नहीं आया कि सरकार ने इसके बारे में क्या एक्शन लिया है। क्या हमारे जिले को कोई अलग से आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है ताकि हमारे जिले का विकास हो सके। इसके बारे में आपने मुझे कोई सूचना भी नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : आपके तीनों कालिंग अटैंशन मोशंज विचाराधीन हैं। आपको सूचना दे दी जायेगी अब आप बैठिये।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में ब्याह शादियों में डी.जे. बजने के कारण बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है इसलिए इनको बन्द किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, डी.जे. सिस्टम के शोर से संबंधित जो आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कृपया आप उसको दुबारा दे दें जिस पर हम फिर से विचार कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैंने दिया था, कृपया उसके बारे में भी बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में भी बता देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये प्रैस के साथी सब देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सदन में महात्मा गांधी तथा डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे नेम प्लेटों को हटाना

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, सदन में महात्मा गान्धी जी की तस्वीर लगी हुई है यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों (पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, पूर्व स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री अकरम खान और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) के नाम की इतनी बड़ी बड़ी नेम प्लेट्स महात्मा गान्धी और डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों के नीचे लिखकर लगा रखी हैं उनको हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इनको जनता ने रिजैक्ट कर दिया है और इनकी पार्टी ने भी उनको रिजैक्ट कर दिया है उनके नाम की प्लेटें भी सदन में लगी हुई हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों के नाम की प्लेट्स को सदन से हटवाया जाए।

Shri Kuldeep Sharma : Sir, it is obnoxious. I have never heard such versions in this House. What he is talking about? It is extremely obnoxious.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप फैसला लें कि इन प्लेट्स को हटवाना है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, इसके बारे में हाउस की सहमति ले लेते हैं। अगर हाउस की सहमति होगी तो जरूर इस बारे में कार्यवाही करेंगे। जो माननीय सदस्य इन प्लेट्स को हटवाने के पक्ष में हैं वे हाथ खड़ा करें।

(इस समय ज्यादातर माननीय सदस्यों ने इन नेम प्लेट्स को महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे से हटवाने के समर्थन में अपने हाथ खड़े किए।)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इन नेम प्लेट्स को महात्मा गान्धी की तस्वीर के नीचे से हटवा दिया जाएगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्री अध्यक्ष : अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर पुन: चर्चा आरम्भ की जाती है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी, कृपया आप बोलिए।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, 9 मार्च, 2015 को प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण इस सदन में दिया। पूरा सदन इस बात को जानता है कि गवर्नर एड्रैस सरकार का एक visionary document होता है जो प्रदेश की दशा और दिशा की तरफ संकेत करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस अभिभाषण में बड़े-बड़े शब्दों का मायाजाल दर्शाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं कि आज किसान की हालत ठीक नहीं है। किसान की मजबूती प्रदेश की आर्थिक स्थिति व मजबूती की द्योतक होती है। यदि किसान की जेब में पैसा है तो बाजार में रौनक है, अस्पताल में रौनक है, कोर्ट-कचहरी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आदि में रौनक है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी समृद्धि और खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। लेकिन पिछले 4 महीने में जो किसान की स्थिति हो गई है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आज हरियाणा का किसान भयभीत है, डरा हुआ है। वह अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देख रहा है क्योंकि जैसे कि गर्वनर एड्रैस में बताया गया है कि इस बार पैडी अर्थात् परमल चावल की पर्चेज तकरीबन 29.78 लाख मीट्रिक टन हुई है जबकि पिछले वर्ष परमल जिसको मोटा चावल कहते हैं, आप तो किसान के बेटे हैं, आप तो सब जानते हैं, उसकी पर्चेज़ 36 लाख मीट्रिक टन हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने भारी नुक्सान का कारण क्या है ? इस बार परमल की पैदावार कम क्यों हुई ? गत वर्ष बारीक चावल का दाम 50/- रुपये से 55/- रुपये प्रति किलोग्राम तक चला गया था तथा इस बार बारीक चावल की कल्टीवेशन ज्यादा हुई, इसलिए यह चावल पिट गया। इसका दूसरा कारण एक्पोर्ट है। पिछले वर्ष यू.पी.ए. सरकार इस संबंध में अपने डैलीगेट्स ईरान भेजती थी। अध्यक्ष महोदय, ईराक और ईरान के झगड़े की वजह से एक्सपोर्ट की बात आई। सरकार द्वारा अपना डैलीगेट साल में 3 बार भेजा जाता था लेकिन नई सरकार ने इरान के अंदर अब तक कोई डैलीगेट नहीं भेजा जोकि नवम्बर, 2014 में भेजा जाना था जिसके कारण किसानों को बुरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई और किसान का हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। नई सरकार की लापरवाही की वजह से इरान सरकार ने चावल पर ड्यूटी 22 परसैंट से बढ़ाकर 45 परसैंट कर दी जिसकी वजह से बासमती चावल 1121 और 1509 व डी.पी. चावल के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा। पिछली यू.पी.ए. सरकार बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर 3 परसैंट इंट्रस्ट वहन करती थी जोकि नई सरकार ने बंद कर दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स पर आधारित बात कर रहा हूँ जिसके कारण एक्सपोर्ट पर बुरा असर पड़ा। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता यहां पर नहीं बैठे लेकिन पंडित जी बैठे हैं। नई सरकार ने बासमती जीरी पर मार्किट फीस, सैस फीस और परचेज टैक्स को घटाने का वायदा किया था जिसको सरकार पूरा नहीं कर पाई। जबकि पंजाब, यू.पी., दिल्ली, राजस्थान और बिहार में ये सभी टैक्स हरियाणा से बहुत ज्यादा कम हैं। नई सरकार ने आने वाले साल के लिए पैडी के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है जो बात आगे जाकर इफैक्ट करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अकेले पैडी की बात कर रहा हूं जबकि कॉटन, बाजरा और पापुलर भी पिटा, पापुलर के बारे में तो अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते ही हैं क्योंकि आप पापुलर की बैल्ट से आते हैं। अकेले किसान पॉकेट को हजारों

करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात पर नहीं जाना चाहता। दांगी साहब ने पैडी बोई होगी इसलिए बता रहे हैं कि जीरी का रेट 2500, 2200 और 2000 रुपये तक आया है और अकेले किसान हाउस को 25 से 30 हजार रुपये प्रति एकड़ तक नुकसान हुआ है। इस प्रकार किसान का हजारों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है जोकि बहुत चिंतनीय विषय है। किसान बेमौसमी भारी बारिश और ओला वृष्टि को भी झेल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर वर्ग की एक संरक्षक होती है। Art and science of the administration and art and science of the governance of the Government is to distribute natural and other all type of resources equal and equitably among the masses. It is the art and science of the administration. अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि किसान की हालत के बारे में सरकार को दोबारा अपने विजनरी डाक्यूमैंट में एड करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा हांसी बुटाना नहर को तकरीबन 400 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया गया इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब तक एस.वाई.एल. कैनाल नहर न बने तब तक हांसी बुटाना नहर के पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंसैप्ट के तहत डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और इसके बारे में जो विजनरी डाक्यूमैंट है उसमें सरफेस मैंशन है। हांसी बुटाना नहर और एस.वाई.एल. नहर के ऊपर बहुत सी सरकारें बनी और गिरीं। एस.वाई.एल. नहर के बारे में हम कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है।

श्री बलबंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब ने बात कही कि अक्टूबर में जीरी का रेट कम हुआ और हांसी बुटाना नहर का पैरलल पानी देने की बात इन्होंने की। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि 10 साल इनकी सरकार रही और जिस समय जीरी पिटी उस समय इनकी सरकार थी। (विघ्न) हांसी बुटाना नहर के निर्माण पर जो खर्च हुआ उसका मुआवजा कौन देगा क्योंकि आज तक उसमें एक बूंद पानी भी नहीं आया और वह लोगों को डूबोने के लिए काम कर रही है। मेरा निवेदन है कि सारी कार्यवाही निकलवा कर देखा जाए कि इसके निर्माण पर कितना खर्च हुआ। अध्यक्ष महोदय, हांसी बुटाना नहर को जब बनवाना शुरू किया गया उसको उस समय सिरे से बनवाना शुरू करवाना चाहिए था। हांसी बुटाना नहर को बनवा तो दिया गया और प्रदेश का हजारों करोड़ों रुपये खर्च भी हो गया परंतु आज तक उसमें एक बूंद पानी की नहीं आई और जमींदार हाय हाय, कर रहा है इसलिए ये इस बारे में जरूर बताएं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्य को यह भी बता दें कि हांसी-बुटाना लिंक नहर का कार्य करवाने बारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी जिक्र किया हुआ है। (विघ्न)

श्री बलबंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार तो यह कार्य जरूर करवायेगी लेकिन इनके समय में इस पर क्या कार्यवाही की गई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। (विघ्न)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश को एस.वाई.एल. कैनाल का पानी मिले उसके लिए बड़े-बड़े संघर्ष और बड़ी-बड़ी लड़ाईयां लड़ी गई हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल का पानी न मिलने से हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। मेरा सदन से और विपक्ष के साथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि एस.वाई.एल. कैनाल के निमार्ण के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को स्पष्ट आदेश

[श्री अभय सिंह यादव]

दे दिए थे (विघ्न) लेकिन बाद में पंजाब ने रीवर वाटर एक्ट को निरस्त कर दिया था। उसके बाद 5-6 साल पहले भारत सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल-143 रैफरैंस भिजवाया। वह रैफरैंस तब से as it is पैंडिंग पड़ा है। इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में क्या कोई अरली हीयरिंग की एप्लीकेशन इस रैफरैंस को लेकर लगाई गई ? मुझे केवल यही जानकारी चाहिए।

विद्यार्थियों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को सूचित करना चाहूंगा कि Institution of Mas Communication & Media Technology, Kurukshetra University के छात्र और अध्यापक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। मैं उनका पूरे सदन की तरफ से स्वागत करता हूँ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल पर चर्चा चल रही थी। मैं पूरे सदन से प्रार्थना करूंगा कि एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में न जाकर पूरा सदन एक सांझा प्रयास करे ताकि एस.वाई.एल. कैनाल का पानी प्रदेश के किसानों को मिल सके। हमने पहले भी इस तरह की बात कही थी और प्रयास भी किया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तथा राष्ट्रपति महोदय का रैफरैंडम भी दिया था। ये सारे के सारे पैंडिंग हैं, एक्चूवल कंडीशन का मुझे नहीं पता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, भाई अभय सिंह जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अभी रैफरैंस बाकी है। यह एक ऐसा रैफरैंस है जो इतने लम्बे समय से पैंडिंग है। इसकी अरली हीयरिंग के लिए हमारे समय में भी एप्लीकेशन दी गई थी और मुझे विश्वास है कि मौजूदा सरकार भी इसके लिए पूरी कोशिश करेगी।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार एस.वाई.एल. कैनाल को कम्पलीट करवाने के लिए प्रयत्न करे और हांसी-बुटाना लिंक नहर में पानी लाने के लिए भाखड़ा कैनाल में पैंक्चर हो उसके लिए भी प्रयत्न किए जायें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं लैंड एक्वीजिशन एक्ट पर बोलना चाहूंगा कि लैंड एक्वीजिशन बिल क्या है, क्या नहीं है। इसके बारे में किसान को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन देश में और प्रदेश में एटमोशफियर ऐसा बन गया है कि बहुत बड़ी तलवार आज किसानों की गर्दन पर टिकी हुई है। हम चाहते हैं कि कम से कम जो भूमि अधिग्रहण बिल हरियाणा में आज के दिन प्रीवेल कर रहा है वह यहां रखा जाये ताकि हमारे प्रदेश का किसान उस भय की तलवार से मुक्त हो जाये। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों को सिंचाई के लिए दिन में लगातार 8 घंटे बिजली दी जाये ताकि किसान महसूस करे

कि उसका भी कोई रखवाला है। आज यूरिया के लिए किसान भाग रहा है। खरपतवार, कीड़े, बीमारी आदि किसान के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसी तरह से बेमौसमी बरसात तथा ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी किसान की दुश्मन हैं। **** आज प्रदेश में किसान की बहुत दयनीय हालत है। ऐसे समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना बहुत जरूरी है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बारे में हमारे कृषि मंत्री ने कहा कि मैं तो बेचारा मंत्री हूं, यह नैशनल इशू है इसलिए मैं इसको स्टेट लैवल पर लागू नहीं कर सकता। (विघ्न)

एक आवाज : सर, उन्होंने बेचारा शब्द यूज नहीं किया।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनी थी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। इसका मतलब ये भी बेचारे थे।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब ने आढ़तियों और किसानों के बारे में जो बात की है वह गलत बात है। इन्होंने एक समुदाय का अपमान किया है। हम माननीय सदस्य से इस तरह की उम्मीद नहीं रखते। आढ़ती और किसान का तो बहुत गहरा संबंध होता है और ये एक दूसरे के सुख-दुख के साथी हैं। इसलिए इस बात को सदन की कार्यवाही से निकलवाया जाये और कादियान साहब इसके लिए सदन से माफी मांगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यह बात सदन की कार्यवाही से निकाल दी जाये। (विघ्न)

श्री रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरे कहने का यह आशय हरगिज़ नहीं था कि आढ़ती किसान का दुश्मन है मेरे कहने का मतलब यह था कि हमारा किसान मनीलैंडर के शिकंजे में फंसा हुआ है। He is under the clutches of money-lender.

श्री विपुल गोयल : स्पीकर सर, हमारे प्रदेश में आढ़ती और किसान के बीच में बहुत ही अच्छे और सौहार्दपूर्ण सम्बंध हैं।

श्री अध्यक्ष : विपुल जी, आपकी बात बिलकुल सही है। मैं इस बारे में सबकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आढ़त का सिस्टम नहीं है जिस कारण वहां पर किसानों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। मेरा इलाका उत्तर प्रदेश के साथ लगता है इसलिए मैं यह जानता हूं कि हरियाणा की सीमा से 100-100 किलोमीटर दूर तक के किसान अपनी फसल को हरियाणा में बेचने के लिए आते हैं। इसलिए मैं यह बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो यह आढ़त का सिस्टम है यह बुरा सिस्टम नहीं है यह एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, हमारे प्रदेश में आढ़ती और किसान का तो चोली-दामन का सम्बंध है।

भी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आढ़तियों के बारे में जो बात आपने हाऊस की कार्यवाही से निकलवाया है यह आपने बहुत अच्छा किया है। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि आढ़ती तो किसान के लिए ए.टी.एम. है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि जो मनी-लैंडर हैं वे बड़ी बेरहमी से किसान को निरंतर चूस रहे हैं। इसके अलावा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है क्या वह स्टेट लैवल पर लागू हो सकती है? अगर यह रिपोर्ट स्टेट लैवल पर लागू हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर स्टेट लैवल पर यह रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती तो उस स्थिति में इस हाऊस से एक प्रस्ताव पास होकर भारत सरकार के पास जाना चाहिए कि जो एम.एस.पी. अर्थात जो Minimum Sports Price है उसको हर फसल की इनफलेशन के साथ जोड़ दिया जाये अर्थात जो महंगाई की दर है अगर उसके साथ इसको जोड़ देंगे तो उससे किसान कम्पनशेट हो जायेगा। इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन यहां से जाना चाहिए।

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। जैसा कि यहां पर माननीय सदस्य श्री कादियान द्वारा हरियाणा प्रदेश में खाद की कमी का जिक्र किया गया है जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री कादियान जी से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस सदन में इस बात की भी जानकारी दें कि हमारी सरकार आने से पहले उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार खाद का कितना स्टॉक छोड़कर गई थी और इसके साथ ही साथ ये यह भी बतायें कि अक्तूबर, 2014 के लिए कितने खाद की सप्लाई के आदेश सम्बंधित एजेंसियों को देकर गई थी।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री सुभाष बराला जी को कहना चाहता हूं कि वे भी किसान के बेटे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, इनका कहने का मतलब यह है कि पहले वाली सरकार को आने वाली फसल के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए थी।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं श्री सुभाष बराला जी को एक बात बताना चाहता हूं कि फसल की बिजाई के समय डी.ए.पी. की आवश्यकता होती है न कि यूरिया खाद की।

श्री सुभाष बराला : स्पीकर सर, मैं इनको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब किसान को खाद की ज़रूरत नहीं थी तो फिर खाद के लिए किसानों को धक्के क्यों खाने पड़े। बिजाई के बाद जब गेहूं की फसल में पानी दिया जाता है उस समय तो यूरिया खाद की ही आवश्यकता होती है इसलिए कांग्रेस की सरकार को इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए थी क्योंकि इसके लिए खाद एजेंसियों को पहले आदेश देने ज़रूरी होते हैं।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मौजूदा सरकार के लोग कह रहे हैं कि पिछले वाली सरकार को खाद की पर्याप्त व्यवस्था करके जानी चाहिए थी जो कि वह करके नहीं गई और पहले वाली सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इस सरकार को खाद को बांटने का तरीका नहीं आया इसलिए यह समस्या पैदा हुई। माननीय दांगी साहब कह रहे हैं कि बिजाई के समय सिर्फ डी.ए.पी. की आवश्यकता होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजाई के 20 दिन बाद जब गेहूं की फसल में पानी दिया जाता है तो उस समय यूरिया खाद की आवश्यता होती है। इसलिए पहली सरकार के नुमाइंदे इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से न भागें क्योंकि आने वाली फसल के लिए यूरिया खाद के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करना पूर्व सरकार की जिम्मेदारी थी और उसका सही ढंग से वितरण करने की जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की भी थी।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैंने यह कहा था कि बिजाई के समय यूरिया खाद की बजाय डी.ए.पी. की आवश्यकता होती है और उसके बाद जब 20-25-30 दिन के पश्चात् पानी दिया जाता है उस समय ही यूरिया खाद की आवश्यकता होती है। उस समय यूरिया खाद किसी को नहीं मिली हम यही कहना चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य रघुवीर सिंह कादियान जी बोल रहे हैं और दांगी जी भी उनके समय में से समय लेकर बोल रहे हैं मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये सारे किताबों में पढ़कर ही खेती करना जानते हैं। इस पूरे सदन में मेरे से ज्यादा हाली और पाली का दर्द कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने स्वयं 20 साल तक हल चलाया है। मैंने ऊंट के हल को भी चलाया है और बैलों के हल को भी चलाया है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, ऐसी बात नहीं है कि यह काम सिर्फ रामबिलास शर्मा जी ने ही किया है। हमने भी हल चलाया है और ट्रैक्टर से भी खेतों की जुताई की है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने एक ऐसी बात कही है कि जिसका जवाब देना जरूरी है। यहाँ पर ज्यादातर गांवों में रहने वाले सदस्य बैठे हुये हैं। मैंने भी खेती की है और मैं जानता हूँ कि माघ-पोष की सर्दी में खेतों में जब पानी लगाते हैं तो क्या हालत होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य ने खेती की है तो ये कैसे कह सकते हैं कि गेहूँ की बुआई से पहले नाईट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती जबकि गेहूँ की बुआई से पहले नाईट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बुआई के समय नाईट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि बुआई के समय डी.ए.पी. खाद की जरूरत पड़ती है। मैंने 17 साल तक खेती की है मुझे सभी बातों का पता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, बुआई के समय नाईट्रोजन खाद की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि 25-35 दिन के बाद जब पहला पानी गेहूं में लगाया जाता है तब नाईट्रोजन खाद की जरूरत पड़ती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छी परम्परा शुरू की, कि आपने 90 विधायकों का ट्रेनिंग कैम्प हरियाणा निवास में लगाया। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि एक हलाई घालण का तथा हल में कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, हाल कहाँ होती है, कागा कहाँ होता है, घूसवा कहाँ होला है, कात कहाँ होती है और कुश कहाँ पर होती है तथा अकराल और सेवा में क्या फर्क होता है, आदि का भी एक कम्पीटीशन आप रखवा दो। (हंसी)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को बताना चाहता हूँ कि हमने भी खेती की है। आप हल के जिन पार्ट्स की बात कर रहे हैं उनके एरियावाईज नाम अलग हो सकते हैं लेकिन हम सबको भी उनके नाम पता हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस लैजिस्लेचर के लिए है न कि हल चलाना सीखने के लिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी दांगी साहब ने कहा कि हमने डंगर भी चराये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश का जो भगवान है वह भी डंगर चराने वाला है और इस देश का जो सबसे बड़ा पोल्टीशियन है वह भी डंगर चराने वाला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस देश के सबसे बड़े पोल्टीशियन तो चाय बेचने वाले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस देश में जिसको सबसे बड़ा पोल्टीशियन माना जाता है, वे भगवान श्री कृष्ण है। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ जो कि स्वयं गांय चराने वाले हैं जिनको हम 16 कला-सम्पूर्ण भगवान मानते हैं, वे भी गाय चराने वाले थे। इसलिए डंगर चराने वाला भी छोटा नहीं होता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, यह इस देश के लिए गर्व की बात है कि एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। इससे बड़ी बात देश के लिए और क्या हो सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की बात की गई है। जब वे लोकसभा के चुनाव के दौरान जगह-जगह सारे देश में जा कर वोट मांग रहे थे तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि यह एक गरीब परिवार से है और यह तो चाय बेचने वाला है। लेकिन भाई नरेन्द्र मोदी ने 125 करोड़ जनता के सामने यह कहा था कि मैं सच में एक गरीब माँ का बेटा हूँ और एक चाय बेचने वाले पिता का बेटा हूँ लेकिन मैं 125 करोड़ जनता के खून-पसीने की कमाई नहीं खाता, मैंने मेहनत की हुई है मैं यह कहना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, चाय बेचने वाले अब 10-10 लाख रुपये के शूट भी पहनने लग गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री घनश्याम दास : अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य खेती और खाद के बारे में कह रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने किसानों के हितों का कितना ध्यान रखा ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्रियों की समिति के अध्यक्ष थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिये थे वे जब सरकार ने नहीं माने तो इन्होंने क्या किया ? तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इस सदन में, डिबेट में या टेलीविजन पर जो भी सदस्य कृषि पर चर्चा करना चाहे तो मैं उसके लिए ऑफर करता हूँ कि मैं उसके लिए तैयार हूँ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मेरी कमेटी का सवाल किया है जो मेरे नेतृत्व में है। हम इनको बताने चाहते हैं कि हमने क्या किया है। मैं इनके नॉलिज के लिए बताना चाहता हूं कि जो कमेटी बनी थी अर्थात जो हमारा वर्किंग ग्रुप बना था, उसमें बहुत सारी सिफारिशें थी। एक सिफारिश उनमें ये भी थी जिसकी वह चर्चा करते हैं। ये समझते हैं कि स्वामी-नाथन की चर्चा आम तौर पर एक ही रिकमैंडेशन थी। उसमें यह था कि किसान की जितनी इन्वेस्टमैंट लगे उसका 50 प्रतिशत मुनाफा। उसके अलावा और भी थी वह भी हमारी रिकमैंडेशन थी। इसके अलावा भी बहुत सारी रिकमैंडेशन थी। आपको पता होगा कि पहले यहां पर शॉर्ट टर्म में

बैंक किसान को 11 प्रतिशत दर पर लोन देते थे और आज पूरा प्रदेश में 4 प्रतिशत दर पर ज्यादा टर्म में लोन ले सकते हैं। वह भी हमारी ही रिक्यूमैंडेशन थी वर्किंग कमेटी की रिक्यूमैंडेशन थी। ऐसी बहुत सारी सिफारिशें हमने की हैं। डायरैक्ट सब्सिडी की बात करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में यह हमारी रिक्यूमैंडेशन के बाद हुआ है पहले इसकी दर 11 प्रतिशत थी। इसी प्रकार से आधार कार्ड पर जो डायरैक्ट सब्सिडी देने की बात है वह भी हमारी ही रिक्यूमैंडेशन हैं ऐसी बहुत सारी रिक्यूमैंडेशन हैं जिनके लिए हमने प्रयास किए हैं। स्वामी नाथन रिपोर्ट के लिए भी हमने प्रयास किए हैं और करते रहेंगे क्योंकि यह किसान का हक है। सबको मुनाफा मिलता है किसान को भी मुनाफा मिलना चाहिए। स्वामी नाथन और हमारी वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए सरकार चाहे किसी की भी हो।

श्री नायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, 50 साल से लगातार 18 प्रतिशत दर पर फसली ऋण किसानों को देते थे। जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली थी उन्होंने किसान ऋण को 11 प्रतिशत दर किया था। यह जो हरियाणा में 4 प्रतिशत दर की बात कर रहे हैं इनसे पहले मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चली उन्होंने 0 प्रतिशत दर पर किसानों को फसली ऋण दिया था। जहां तक हरियाणा की बात है जो किसान पिछले 10 साल में ऋण ले रहे हैं उनसे 7 प्रतिशत ब्याज लेते थे और यह कहते थे कि 3 प्रतिशत ब्याज का आगे केस बनकर जाएगा तब आपका 3 प्रतिशत ब्याज वापिस होगा। लोगों को 10 साल हो गए और वह हर फसल पर यह पूछते हैं कि हमारा 3 प्रतिशत ब्याज वापिस आ गया या नहीं। इनका जवाब यह होता था कि अभी केस बनकर वापिस नहीं आया है। ये इन्होंने किसानों का हित किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, रैफरैंस क्या है और ये बात क्या कह रहे हैं जो हमारी वर्किंग कमेटी की रिपोर्ट थी वह किसी एक स्टेट की बात नहीं है पूरे देश में 4 प्रतिशत दर लागू हुआ है।

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान हैं बड़े एक्सपीरियंस हैंड हैं और हमारे साथी भी रहे हैं। मैं इनकी नॉलिज के लिए यह बताना चाहता हूं कि मैं उस किसान का बेटा हूं जो 14 साल की उम्र में हाली लग गया था। उसका बेटा युनिवर्सिटी में गया एम.एस.सी. और पी.एच.डी. करी और उसी कृषि विश्वविद्यालय में 17 साल प्रोफेसर रहा और फिर राजनीति में आया। शर्मा जी, जहां तक किताबों की और जरनल नॉलिज की बात है आप ज्यादा जान सकते हो और हम कम जान सकते हैं वह तो कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। लेकिन हम भी उस दर्द को समझ सकते हैं। जब किसान को कांटा लगता है, गवार की फांक उसको लगती है, गेहूं की बाली और जेठ मास की धूप उसको लगती है, माह पोष मास की सर्दी उसको लगती है। यह सारी बातें हम जानते हैं और समझते हैं। स्पीकर सर, मैं एक बात कह रहा था उसको इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात डायवर्सिटीकेशन की आई। आपने विजनरी डॉकोमैंट में दिया है उसमें जो रोटेशन है चावल व कपास का लेकिन किसान किसी की नहीं मानता किसान केवल ये देखता है कि उसको फायदा किस फसल से होगा। वह अपने हिसाब से चलता है या तो पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि दलहन और कपास का इतना भाव हो जाए कि उसको 50 हजार रूपये पर एकड़ का मुनाफा हो जाए तो वह उसकी बिजाई कर देगा। वह इस बात से नहीं चलेगा कि वह रोटेशन बदलेगा। लेकिन डायवर्सिफिकेशन का एक तो रोटेशन और दूसरा रोटेशन का असली मकसद है

[डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान]

डायवर्सिफिकेशन। स्पीकर सर, वर्ल्ड का ग्लोबल फिनोमिना का जहां एग्रीकल्चर पर बर्डन है जापान, अमेरिका, रूस, जैसी कन्ट्री में 6%,5%,4%, किसान डायरैक्ट और इनडायरैक्ट तौर से एग्रीकल्चर पर निर्भर है। 4% लोग इस देश के सारे सौदा पैदा करते हैं तेल भी पैदा करते हैं, गेहूं भी पैदा करते हैं, कपास भी पैदा करते हैं, मक्की भी पैदा करते हैं। क्योंकि दुर्भाग्य इस प्रदेश का और देश का यह है कि जितनी प्रतिशत पॉपुलेशन अर्थात जब देश की 10 करोड़ पॉपुलेशन थी तब भी 70-75% किसान कृषि पर डिपैंड थे। 100 करोड़ की पोपुलेशन थी तब भी 70 प्रतिशत किसान एग्रीकल्चर पर डिपैंड था। अध्यक्ष महोदय, जो परसैंटेज है वह एग्रीकल्चर से डायवर्सीफाई नहीं हुई। उसका डायवर्सीफिकेशन का कैसे हो? उसमें लिखा जाता है कि कृषि जोत की भूमि छोटी हो गई है और पैदावार की कीमत बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, डायवर्सीफिकेशन का मतलब यह है कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज, कॉटेज इन्डस्ट्रीज और एग्रो इन्डस्ट्रीज इत्यादि इस तरह के ग्रुप बने जिसमें किसान को एक छत के नीचे लोन मिले, एक छत के नीचे वही प्रोडक्ट मिले और एक छत के नीचे उसकी मार्केटिंग हो जिसमें उसकी सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो। अध्यक्ष महोदय, अगर यह डायवर्ट होगा तो किसान बच जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्हें बोलने दीजिए। कादियान जी अच्छे सुझाव दे रहे हैं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं अब बुढापा पैंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक बड़ा लम्बा-चौड़ा इश्यू है। डायवर्सीफिकेशन पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, डॉक्टर बारलोग जब अमेरिका से यहाँ आये थे तो उन्होंने कहा कि डायवर्सीफिकेशन अगर नहीं हुई तो यहाँ का किसान नहीं बचेगा। अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब भी छपी हुई है परन्तु मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में बुढ़ापा पैंशन बैंकों के माध्यम से देने के बारे में कहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बहुत से बूढ़े लोग आपके पास आते होंगे कि बूढ़े लोग काफी दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय, बूढ़ा वर्ग के संस्कारों के ऊपर यह देश और प्रदेश खड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चाहे वह आधार कार्ड बनावने में दुखी हुआ या आधार कार्ड लेकर आने में दुखी हुआ हो। अध्यक्ष महोदय, कई गाँवों में 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी तक बैंक नहीं होते हैं इसलिए वह अपने लड़के को साथ लेकर पैंशन लेने के लिए जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर गाड़ियों के द्वारा पैंशन लेने के लिए जायेगा तो 400 रुपये का पैट्रोल लगेगा और भीड़ के कारण उनकी जेब भी कट सकती है। इसलिए बूढ़ों के साथ कुछ भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, छोटे से गाँव में 15-20 बूढ़े और बड़े गाँव में 100 बूढ़े जिनकी पैंशन आज चारपाई पर बांटी जाती है। अध्यक्ष महोदय, उन बूढ़ों के लिए मेरा सुझाव है कि बैंक का कर्मचारी पैंशन बांटने के लिए डेट फिक्स करके जायें, जिससे गाँवों के बूढ़ों को यह पता लग जाये कि उन्हें पैंशन किस डेट को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अब के.एम.पी. के बारे में बताना चाहता हूँ। यह हरियाणा में एक लाईफ लाईन है यह पीछे किसी कानूनी दांव पेच में फंस गई। यह एक अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हरियाणा प्रदेश में के.एम.पी. पूरा हो गया तो कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो डिवैल्पमैंट होगी क्योंकि उसके साथ-साथ मेट्रो कोरीडोर भी है। मेट्रो कोरीडोर और के.एम.पी. एक्सप्रैस वे जिस दिन बन गया तो हरियाणा दुनिया के नक्शे में मजबूत और शक्तिशाली प्रदेश के रूप में उभरकर आयेगा यह मेरा सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं

पैंशनभोगियों के बारे में कहना चाहता हूँ कि वर्तमान हरियाणा सरकार ने पैंशन 1200 रुपये प्रति माह की गई है लेकिन लाखों बूढ़ी आँखें टक-टकी लगाए और पड़ी हुई झुर्रियों से अपनी झोंपड़ियों से विधान सभा के पिछले सत्र की तरफ देख रही थी कि मेरी पैंशन 1500 रुपये प्रति माह होगी। (हंसी) यह कोई भावुकता की बात नहीं है।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कादियान जी को तो कविता लिखनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कादियान जी ने सदन में बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं फसलों का डायवर्सीफिकेशन हो परन्तु मुझे लगता है कि इन्होंने मुंशी प्रेमचन्द पर डॉक्टरेट किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी झुर्रियों वाली बात सदन में कही। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा के लोग उस बात से गौरवान्वित थे और हुड्डा साहब उस कमेटी के चेयरमैन भी थे परन्तु हुड्डा साहब बेचारे क्या करते? अध्यक्ष महोदय, इनकी चेयरमैनशिप कमेटी की रिकमेंडेशन थी परन्तु उसे ये लागू नहीं करवा सके। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उसमें श्री राजनाथ सिंह जी कृषि मंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि किसान के ब्याज की दर मध्यप्रदेश में जीरो रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में भी जीरो रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है।

श्री रामबिलास शर्मा : चौधरी साहब मैं आपकी ताईद कर रहा हूँ। आपने प्रयास तो किये परंतु उसको लागू नहीं करवा सके। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, 6 साल देश के प्रधान मंत्री रहे तो आज गुजरात में किसान का ज़ीरो प्रतिशत रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है, मध्यप्रदेश में भी ज़ीरो प्रतिशत रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है और छत्तीसगढ़ में भी ज़ीरो प्रतिशत रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है। अध्यक्ष महोदय, यह बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में कहा, मध्यप्रदेश के बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और हरियाणा में भी वही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, हमने सहकारी बैंकों के ऊपर ज़ीरो परसेंट शार्ट टर्म लोन किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि सवाल देश के लिये है और रिकमेंडेशन देश के लिए होती है न कि अकेले शक्कर के लिये। अध्यक्ष महोदय, नैशनलाईज़ड बैंक केन्द्र सरकार के अधीन आते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनमें ज़ीरो रेट ऑफ इन्ट्रस्ट करवाएं। हरियाणा प्रदेश में तो ऑलरेडी ज़ीरो रेट ऑफ इन्ट्रस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष महोदय : डॉ. साहब आप प्लीज़ एक मिनट में वाईंड अप कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के समान कर्मचारियों को पे-स्केल मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्यों की बोलने की तैयारी नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे, श्री करण दलाल, श्री आनन्द सिंह दांगी, डॉ0 कादियान और श्रीमती शुकन्तला खटक को 'क' अक्षर वालों को किसी साजिश के तहत बोलने नहीं दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी तो बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ तो आपका विशेष लगाव है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप 'क' अक्षर वाले चिन्ता मत करो। यहां पर भी 'क' अक्षर वाला बैठा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप 'क' अक्षर के साथ-साथ स्पीकर भी है और स्पीकर कभी नहीं बोलता।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, जहां तक गुड गर्वनेंस की बात है, जिस प्रदेश के कर्मचारी के मन में यह बात नहीं होगी कि मैं सुरक्षित हूँ और उसका जीवन निर्वाह का साधन पूरी तरह से सीट आउट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यही अर्ज है कि पंजाब के समान ही हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में बैठे हुए सम्मानित सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि किसी प्रदेश का नेतृत्व कहां से होता है? आज नेतृत्व की नर्सरी कहाँ हैं? और कहाँ से लीडरशिप निकलती है? इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ क्योंकि मैं स्वयं यूनिवर्सिटी के अंदर 3 साल प्रधान रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो नेतृत्व निकलता है वह छात्र संघ के चुनाव से ही निकलता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसमें लिंगदोह कमेटी की रिकमेंडेशन की जो रिपोर्ट है वह लागू होनी चाहिए और उस हिसाब से ही छात्र संघ के चुनाव हों। छात्र संघ चुनाव के दो मायने निकलते हैं, एक जो छात्र दबा हुआ है, वह यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात अच्छी तरह से रख सकता है, अपने इन्ट्रस्ट का बचाव कर सकता है और अपने कैरियर की दिशा और दशा तय कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा इसमें यह है कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी आयेगी जो देश और प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी हिस्सेदारी होगी। अध्यक्ष जी, मैं एक दूसरे मुद्दे पर भी बोलना चाहता हूं। कमेटी मीटिंग्स में मेरी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी बात होती है। उनकी भी यही भावना है कि सभी विधायकों को लोकसभा सदस्यों की भांति लोकल एरिया डिवैल्पमेंट फंड दिया जाए ताकि वह अपने हल्के में जो जरूरी काम हैं उन्हें अपने तरीके से करवा सकें। विधायकों का डिस्क्रिशनरी कोटा इन्करर्ड होना चाहिए फिर चाहे यह 5 करोड़ हो, 6 करोड़ हो क्योंकि हर विधायक को अपने हल्के के बारे में पता होता है कि कहां क्या कार्य करवाना होता है जैसे किस गली को पक्का करवाना है, कहां कीचड़ पड़ा हुआ है, हरिजनों की चौपाल पर कितनी ग्रांट लगनी है, उसको पता होता है कि यहां लीकेज है और यहां नाली बननी है। प्रोपरली पूरे प्रदेश का बजट डिस्ट्रिब्यूशन और एक्सपैंडीचर इन्कर्ड होना चाहिए। स्पीकर साहब, आप सारी बातों को हंसकर टाल देते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि यह मुद्दा पिछले 15-20 सालों से उठता आ रहा है। जब मैं विधायक था तब भी यह मुद्दा उठता था तब मैं भी यही कहता था लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

Dr. Raghuvir Singh Kadian : Speaker Sir, I want your protection. (Interuption)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाहता हूं। कादियान साहब को आज डिस्क्रिशनरी कोटे की याद आ गई है। मैं 20 साल तक विपक्ष में बैठकर चिल्लाता रहा कि हमें ग्रांट दी जाए लेकिन कांग्रेस ने मेरी बात नहीं सुनी। अब आप डिस्क्रिशनरी कोटे की बात करते हैं। (विघ्न)

श्री महिपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे माननीय सदस्य ने सदन को एक अच्छा सुझाव दिया है लेकिन जब ये सरकार में थे तब तो इन्होंने यह काम किया नहीं लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इनके सुझाव बहुत अच्छे हैं मगर हमें खुशी तब होती जब ये अपने शासन काल में भी इस तरह के मुद्दे उठाते।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य डॉ. कादियान ने चाइना और अमेरिका की कृषि का मुद्दा उठाया है और बताया है कि यहां पर 6 प्रतिशत लोग कृषि करते हैं लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि वहां पर खेत नहीं बंटते हैं। वहां खेत बड़े लड़के को ही मिलता है। हमारे देश में कृषि योग्य भूमि चाइना से डेढ़ गुना और अमेरिका से दो गुना ज्यादा है। हमारे देश में कृषि आर्थिक आधार है लेकिन वहां पर कृषि उनका आर्थिक आधार नहीं है। यहां पर 70 प्रतिशत लोग खेती से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि यहां की जमीन बहुत उपजाऊ है और हमारी बेरोजगारी केवल कृषि से ही दूर हो सकती है। हमारे देश की आजादी के बाद यदि स्वर्गीय सरदार पटेल जी देश के प्रधानमंत्री बन जाते तो खेती की स्थिति सुधर सकती थी। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात् खेती को कमतर आंका गया और हम यूरोप की तरफ ही देखते रहें लेकिन हमने अपनी नीति के आधार पर कृषि को डिवैल्प नहीं किया। इसलिए आज जो कांग्रेस के सदस्य स्वयं को किसानों के हितैषी कहते हैं उन्होंने 60 साल से खेती को बर्बाद किया है, कृषि की वैल्यु को बहुत कम कर दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री श्याम सिंह राणा जी, आप बैठिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि जब विपक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं तो उनको भी सुना जाना चाहिए।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, पण्डित जी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि face the facts squarely otherwise, the facts will stab you in the back. माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी इस बात को समझते हैं। मैं जो बात बता रहा था वह तो थोड़ी सी डिस्कशन थी छोटा सा रिप्रेजेंटेशन था और जिस तरीके से यहां पर माहौल बनाया जा रहा है इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि

"तेरी बर्बादी के सलाह मश्विरे हो रहे हैं आसमानों पर,
अगर नहीं समझोगे ऐ किसानों,
तो तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी, दास्तों में"

[डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान]

यह बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। यह कोई छोटी बात नहीं थी। सलाह मश्विरा और सजैशन थे कोई ऐसी लम्बी चौड़ी बात नहीं थी। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह कहना चाहूंगा -

"ऐ मुसाफिर तू तैयार रहना मुसीबत आने वाली है,
तेरी बर्बादियों के मकबरे हैं आसमानों में,
ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दुस्तां वालो,
तुम्हारी दास्ताँ भी नहीं होगी, दास्तां में"

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, ठीक है, आप दो मिनट में कन्क्लूड कीजिए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बेरी में राउंड एबाऊट बनने हैं, पोलिटैक्निक वुमन कालेज का फाउंडेशन तैयार होना चाहिए, बेरी का बस स्टैण्ड मिनी सचिवालय के पास बनना चाहिए, बेरी में हरियाणा रोड़वेज का सब-डिपो बनना चाहिए, हुडा का सैक्टर बनना चाहिए, बेरी के छाजान पाना में हर्बल पार्क बनना चाहिए और बेरी का कम्यूनिटी सैंटर बनना चाहिए। इसी प्रकार इरीगेशन विभाग के बारे में कुछ मांगे रखना चाहता हूं। भाकरा माईनर की रिमॉडलिंग का कार्य पिछले छः महीने से बन्द पड़ा है इसलिए किसानों को पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। इसी प्रकार रेवाड़ीखेड़ा माईनर जिसकी एक्सटेंशन कबलाना गाँव तक होनी थी वह नहीं हुई है, इसी प्रकार से खरमान, चुडानी ड्रेन, बिशन माईनर, भम्बेया माईनर, दिभाना चुलियाना ड्रेनेज का काम जल्दी से पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार से धौड़ गांव की 250 एकड़ भूमि पर ड्रेनेज बनना चाहिए। इसी प्रकार से के.सी.बी. ड्रेन भापड़ौदा गाँव के पास ब्रिज बनना चाहिए। रेवाड़ीखेड़ा माईनर को कबलाना गाँव तक एक्स्टैंड करना चाहिए जिसके कारण पिछले दस सालों से वहां की वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। धकोरा गाँव की वाटर वर्क्स के लिए एन.सी.आर. कैनाल में मोगा होना चाहिए ताकि इस गाँव को पानी मिल सके। इसी प्रकार से जसराना माईनर की रिमॉडलिंग होनी चाहिए। इसी प्रकार से 33 के.वी. का स्टेशन मिल्कपुर, सैफीपुर, गोदड़ी, बरहाणा और आधेज गॉवों के लिये बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप ऐसा करें कि इन सब के बारे में लिखकर मंत्री जी के पास भेज दें तो इन सारी बातों को आपके भाषण में शामिल कर लिया जायेगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ये सब मैं मंत्री जी के पास लिखकर भिजवा देता हूं।

(इस समय लिखित सामग्री की एक प्रति मंत्री जी के पास भेजी गई।)

श्री अध्यक्ष : ठीकहै जी, अब आप बैठ जाईये।

(इस समय सभापति महोदय पदासीन हुए)

श्री असीम गोयल : सभापति जी, मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों को नमन करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कुछ बातें कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सदन में

उपस्थित उन पुराने व अनुभवी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक वे इस सदन में आने वाले नये सदस्यों के ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ेंगे तब तक हम नये सदस्य भी कुछ सीख नहीं पायेंगे। जो आप लोग हमें सिखायेंगे, वही हम सीख पायेंगे। इसलिए उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया इस महान सदन की परम्पराओं को ध्यान में रखकर अच्छा आचरण करते हुए हमें सिखाने का काम अवश्य करें। सभापति जी, आज मैं अपने आपको बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस मौके पर मुझे हमारे देश के महान् नेता भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ उदगार याद आ रहे हैं जो उन्होंने कन्याकुमारी के तट पर खड़े होकर कहे थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ***अंधेरा हटेगा, सूरज चमकेगा और कमल खिलेगा।*** आज हम उनके उदगारों को केन्द्र में तथा हरियाणा प्रदेश में सरकार के रूप में चरितार्थ हुए देख रहे हैं। पिछली सरकारों ने प्रदेश के अंदर जो भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा था, इस सरकार ने आकर उस भय, भूख और भ्रष्टाचार के युग का अंत कर दिया है। इस प्रदेश के अंदर एक परम्परा चल पड़ी थी कि ***नजराना, जबराना और शुक्राना*** जो पूर्व सरकारों ने चलाई थीं, हमारी भाजपा जनसेवा वाली सरकार ने इस ***नजराना, जबराना और शुक्राना*** युग का भी अंत कर दिया है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बातें रखीं हैं आज ***सदाचार, सुविचार और शिष्टाचार तथा एक विश्वास, आस और विकास*** वाली हमारी सरकार का हरियाणा में सूत्रपात हुआ है तथा प्रदेशवासियों को इस सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। यह सरकार अमीर और गरीब दोनों की सरकार है। मैं बताना चाहता हूं कि भूख और भ्रष्टाचार का कोई विशेष धर्म, जाति, वर्ग और वर्ण नहीं होता। इन सब चीजों का समूल नाश करना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। (थंपिंग) इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने तहसीलों में E-Registration करने का कदम उठाया तथा तहसीलों में जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे और जो भ्रष्टाचार का वातावरण 6 महीने पहले बना हुआ था उसका अंत किया। रजिस्ट्री कराने के लिए लोग दूरस्थ गाँवों से जब तहसील में जाते थे तो वे जमीन विक्रेता से तो पैसे की उधार कर लेते थे लेकिन जो बाबू या अधिकारी रजिस्ट्री की खिड़की पर बैठा होता है जब तक उसको नजराना व शुक्राना नहीं देंगे तब तक वह जमीन की रजिस्ट्री नहीं करता था। अपनी खुद की चाय के लिए तो वे लोग पैसे लेकर नहीं आते थे लेकिन रजिस्ट्री बाबू व अधिकारी की चाय के पैसे उनको जरूर लेकर जाने पड़ते थे। इसलिए हमारी सरकार ने E-Registration के माध्यम से इस भ्रष्टाचार की प्रथा का अंत कर दिया है। इसके साथ ही साथ सी.एम. विण्डो के माध्यम से हमारी सरकार ने प्रदेश की पूरी जनता के हित के लिए एक नई सुविधा की शुरूआत की है। (विघ्न)

प्रो0 रविन्द्र बलियाला : सभापति जी, कुछ ऐसे केसिज़ भी नोटिस में आये हैं कि आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे लिये जा रहे हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : प्रो.रविन्द्र जी, जब आपके बोलने का समय आयेगा, उस समय आप अपनी बात कह लेना।

श्री असीम गोयल : सभापति जी, मैं कह रहा था कि हमारी सरकार ने C.M.Web Portal के नाम से C.M. Window इसलिए लॉंच की है ताकि हरियाणा प्रदेश के दूरदराज के लोगों को चण्डीगढ़ में बार-बार मुख्यमंत्री महोदय के आवास के चक्कर न काटने पड़ें। आम जनता की सरकार जो हरियाणा राज्य में बनी है और आम जनता का विश्वास जो इस सरकार में परिलक्षित हुआ है उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। अन्तोदय योजना के बारे में

[श्री असीम गोयल]

मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जननायक श्री दीन दयाल उपाध्याय जी थे। जिनका यह सपना था 'अंत का उदय'। इस समाज की लाइन में जो अंतिम लाइन में एक आदमी बैठा है जिसके पास तन ढांपने को कपड़ा नहीं है, जिसके पैरों में बिवाई पड़ी हुई है, जिसके पास खाने के लिए रोटी का प्रबंध नहीं है जब तक लाइन में बैठे उस अंतिम व्यक्ति को हमारे सरकार के कार्यों का प्रभाव नहीं पहुंचता, हमारी सरकार के कार्यों की छाया नहीं पहुंचती, जब तक उस अंतिम व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा, पढ़ाई और लिखाई का प्रबंध न कर लें, जब तक सरकार के नेक इरादे उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचते तब तक हमारी सरकार पूरे प्रयत्न से और पूरे मन से ये सारी सुविधाएं पहुंचाने में लगी रहेगी। (विघ्न) सभापति महोदय, मैं हमारी सरकार के जो भाव हैं वह बताना चाहता हूं। (विघ्न) सभापति महोदय, जहां तक कृषि और व्यापारियों की बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि है वह पूरे देश की भूमि की 1.4 परसैंट है लेकिन उत्पादन में हमारा जो प्रतिशत है वह 16 है और हम इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार नई नई टैक्नीक डिवैल्प करके कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बनाना चाहती है। व्यापारियों को हम भय और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देना चाहते हैं। पिछली सरकारों में जो बड़े-बड़े उद्योग हरियाणा से पलायन कर गए थे हम उनको यहां वापिस लाना चाहते हैं। हम बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां यहां स्थापित करना चाहते हैं। हमारी सरकार नई उद्योग नीति को जल्दी ही लांच करने जा रही है। गांवों के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। हम गांवों के उत्थान के लिए एक आदर्श ग्राम योजना शुरू करने जा रहे हैं जिस पर यहां चर्चा भी हुई। इस स्कीम के तहत प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक और सभी क्लास वन अधिकारियों को सरकार की तरफ से एक पत्र गया है जिसमें लिखा गया है कि आपको एक-एक गांव गोद लेकर उसको आदर्श गांव बनाना है। उस गांव को आपको विकसित करना है और उसके भूलभूत ढांचे को आपको विकास के रास्ते पर लेकर चलना है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम सभाओं की बैठकें कम से कम हर 3 महीने में एक बार जरूर हों और साल में ग्राम सभाओं की चार बैठकें जरूर होनी चाहिएं ताकि पंचायतें अलग से सशक्त यूनिट बन सकें। ग्राम सचिवालय की स्थापना की योजना हमारी सरकार ने चलाई है जिसके तहत बड़े गांव में ग्राम सचिवालय की स्थापना तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए ताकि जो भी अधिकारी दौरा करने जाते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमारी सरकार ने जो स्वच्छ भारत और स्वच्छ हरियाणा का मिशन अपने हाथ में लिया है इसके लिए हमारी सरकार ने सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट लगाने का प्रपोजल दी है जिसके ऊपर हमारी सरकार जल्दी ही काम शुरू करेगी। सभापति महोदय, मैं खेल नीति के बारे में एक बात जरूर कहना चाहता हूं जिसके बारे में कल भी बहुत चर्चा हुई है। हमारी सरकार समझती है कि हमारे युवा बेरोजगारी के कारण में नशे की ओर जा रहे हैं। पूर्व की सरकारों ने एक काम किया था। लड़की और लड़के के भेदभाव को खत्म कर दिया। यह भेदभाव कैसे खत्म किया गया है, इसको मैं बताना चाहता हूं। पहले घर में बेटी होती थी तो मां बाप को चिंता हो जाती थी कि बेटी हुई है, इसको पालना है और इसकी शादी करनी है और उसके दहेज की चिंता उनको शुरू हो जाती थी लेकिन आज जब घर में लड़का होता है तो मां बाप को उतनी ही चिंता हो जाती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा। 18-20 वर्ष की आयु आने तक अगर मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली तो कहीं वह गलत संगत में न पड़ जाये। गलत संगत में पड़कर कहीं अपराध या नशे की तरफ आकर्षित न हो जाय। इस तरह से पिछली सरकार के समय में लड़के और लड़कियों में भेद करने की कोशिश की गई लेकिन हमारी सरकार आने के बाद इसमें

सुधार करते हुए फैसला लिया कि प्रदेश में लगभग जो 6700 गांव हैं उन सभी में एक-एक एकड़ में व्यायाम और योगशालाएं खोली जायेंगी ताकि हमारे प्रदेश के युवा तंदुरूस्त रहें और नशे की तरफ आकर्षित न हो पायें।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान एक गंभीर विषय की तरफ दिलाना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" योजना शुरू की है। मुझे इस विषय पर बात करते हुए दुख और हर्ष दोनों की अनुभूति हो रही है। सभापति महोदय, मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में 100 जिले चुने गये जिनमें लिंगानुपात में काफी अंतर है यानि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की काफी कमी है। इन 100 जिलों में 12 जिले हरियाणा प्रदेश के हैं जहां कोख में ही बच्चियों को मार देने का काम किया जाता रहा है जिसके कारण हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल हुई है। इसके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मुझे हर्ष इसलिए है क्योंकि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने अपने इस भाव की हरियाणा प्रदेश के पानीपत जिले से 22 जनवरी को "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम की शुरूआत की है। यह बड़ा गंभीर विषय है और मेरा सबसे निवेदन है कि इस विषय के बीच में टोका टिप्पणी करने से पहले हर आदमी यह सोचे की वह भी किसी बेटी का बाप, ताऊ, चाचा, मामा या भाई है और बेटी के रूप में मां, बहन, पत्नी भी होती है। हम सब समाज के रिश्तों की डोर से बंधे हुए हैं। कृपा इस विषय में कोई भी माननीय सदस्य टोका-टिप्पणी न करे क्योंकि यह सामाजिकता से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर हम सभी को राजनैतिक भावना से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि यह राजनैतिक विषय नहीं है, यह समाज से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय सदस्यगण, मेरे मन में कुछ उद्गार हैं जो मुझे लगता है इस विषय पर अवश्य रखने चाहिए। जब सृष्टि का शुभारंभ ब्रह्मा जी ने किया तब से हमारे जीवन की तीन जरूरी चीजें औरत रूपी देवियों के हाथ में सौंप दी गई थी। पैसा लक्ष्मी जी के हाथों में, ज्ञान और शिक्षा सरस्वती जी के हाथों में सौंप दिया गया जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते तथा रक्षा का कार्य दुर्गा माता तथा महाकाली जी के हाथों में सौंप दिया गया था। ये तीनों कार्य औरत रूपी शक्तियों के हाथों में दिए गए हैं। इस तरह हम किस प्रकार से सृष्टि की जरूरी चीजें अपने हाथ में रखनी वाली बच्चियों को कोख में ही मारने का काम कर सकते हैं। मेरा पूरे सदन से निवेदन है कि इसको कार्यक्रम के रूप में न लेकर एक भाव रूप में लें ताकि प्रदेश में लिंगानुपात की स्थिति में सुधार हो सके। सभापति महोदय, आज यह बड़े दुख और विडम्बना की बात है कि हम 400-500 कि.मी. दूर पहाड़ियों में माता वैष्णों देवी के दरबार में जाते हैं और सभी बेटा मांगते हैं, बेटी कोई नहीं मांगता है। यह भाव पूरे समाज में एक महामारी के रूप में व्याप्त हो गया है और हमारी सरकार इसको मिटाने का पूरा प्रयास कर रही है जिसके लिए हमें विपक्ष के साथियों के सहयोग की भी जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे जाते हुए मैं एक बात यह भी जोड़ना चाहता हूं कि हमारी मां भी किसी की बेटी रही होगी। यदि हमारे नाना-नानी उसको कोख में ही मारकर पाप कर देते तो हम इस संसार में और इस महान सदन में आज नहीं बैठे होते। मेरा पुनः सदन से निवेदन है कि "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम को राजनीति से ऊपर उठकर एक भाव रूप में लेना चाहिए। मुझे गर्व है कि मैं भी एक बेटी का पिता हूं। मैंने इस गर्व की भावना को "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं" के स्लोगन के रूप में जब 22 जनवरी, 2015 से प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश से आरम्भ हुआ तभी से अपने सीने पर इसलिए लगाया हुआ है कि हो सकता है कि मैं पूरे समाज को न बदल पाऊं, हो सकता है कि मैं पूरे देश को न बदल पाऊं, हो सकता है कि मैं पूरे प्रदेश को न बदल पाऊं, हो सकता

[श्री असीम गोयल]

है कि मैं अपने पूरे जिले को भी न बदल पाऊं, हो सकता है कि मैं अपनी तहसील को भी न बदल पाऊं, हो सकता है कि मैं लड़कियों के बारे अपने शहर को भी न बदल पाऊं, यह भी हो सकता है कि मैं अपने परिवार को भी न बदल पाऊं लेकिन अगर अपने इस प्रयास से मैं किसी एक व्यक्ति की सोच और भावना को भी बदल पाया तो मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मैंने प्रण लिया है कि जब तक मेरे जिले में लिंगानुपात बराबर नहीं होता तब तक मैं इस बैज को अपने सीने से अलग नहीं करूंगा। मैं आप सभी महान सदस्यों की अनुमति से अपनी बेटी के ऊपर लिखी हुई चंद लाईनों को मैं यहां पर बोलना चाहता हूं :-

जीवन के इस दरिया में नाव है मेरी बेटी,
जिस कारण ज़मीन पर टिके वह सहारा वह पांव है मेरी बेटी,
मेरी बेटी मेरे जीवन का रंगीन अहसास है मेरी बेटी,
मेरी रगों में दौड़ता हुआ विश्वास है मेरी बेटी,
मेरी बेटी न होती तो जीवन इतना सुंदर न होता,
मैं इंसानियत का पुजारी और मेरा मन मंदिर न होता,
घुमड़-घुमड़कर जब दुखों का साया जब घिरकर आया,
मैंने अपनी बेटी को अपने साथ खड़ा पाया,
मानो कह रही थी मत रूको मत थको,
मेरे लिए इस जीवन से संघर्ष करो,
मेरी बेटी के भरोसे और विश्वास पर ही कुछ कर पाया हूं,
आज जीवन में जो कुछ भी हूं अपनी बेटी की वजह से ही बन पाया हूं।

हमारी सरकार ने इसी भाव को लेकर एक विशेष सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की है कि 10 साल से कम उम्र की जिस बेटी का बैंक में अकाऊंट है उसके अकाऊंट में हम 100 रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की राशि जमा करवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से उसको maximum rate of interest मिलेगा, इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगी। इसी प्रकार से बी.पी.एल. और अनुसूचित जाति के परिवार में जो पहली और दूसरी बेटी पैदा होगी उसके जन्म पर हमारी सरकार की तरफ से 21 हज़ार रुपये की राशि अनुदान के रूप में उस परिवार को दी जायेगी। स्पीकर सर, मैं एक बात और आपके माध्यम से पूरे सदन के और सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के कुशासन के दौरान हमारे अम्बाला के ऊपर जो कहर टूटा और किसानों को इन दस सालों में जिस प्रकार से लूटा गया वह कांग्रेस पार्टी के एक तत्कालीन ताकतवर नेता के कारण हुआ जो कि अपने आपको सुपर सी.एम. कहते थे। वे यह कहते थे कि मेरे ही इशारे के ऊपर पूरी सरकार चलती है अगर कोई इस प्रदेश का सी.एम. है तो मैं सुपर सी.एम. हूं। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसानों से उनकी बहुमूल्य सैकड़ों एकड़ ज़मीन को वाटिका सिटी के नाम पर कौड़ियों के भाव ले लिया और उस पर किस प्रकार से उन्होंने कालोनी काटी यह सभी जानते हैं। उन्होंने अम्बाला में पिछले 9 साल से सारी रजिस्ट्रियों को बंद करवाकर सिर्फ इस कालोनी की रजिस्ट्रियों को ही मंजूरी दी। आज वे सैंकड़ों इनवैस्टर जिन्होंने इस कालोनी

में प्लॉट लिये हैं वे आज रजिस्ट्रियां करवाने के लिए और कब्ज़ा लेने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन ये महाशय अब मलाई खाकर अम्बाला छोड़कर चले गये और आज वे किसान सड़कों के ऊपर आंदोलन करने के लिए मज़बूर हैं। स्पीकर सर, यह बात मैं आपको बड़े दुख के साथ बताना चाहता हूं कि जितने भी पूरे देश में जिले हैं उनमें से अम्बाला शहर पूरे देश का अकेला ऐसा जिला मुख्यालय होगा जिसका अपना बस स्टैण्ड नहीं है। कुछ समय पहले अम्बाला बहुत बड़ा जिला होता था और उसका बस स्टैण्ड भी बहुत भव्य होता था और तब अम्बाला जिले का बस डिपो भी बहुत बड़ा होता था लेकिन आज इस प्राचीनतम जिले में बस स्टैण्ड का कोई नामोनिशान तक नहीं है। अब मैं अम्बाला के ड्रेनेज के बारे में बात करना चाहूंगा। पूर्व सरकार के लोगों को अम्बाला शहर की समस्याओं से कितना सरोकार है मैं यहां पर उसकी एक बानगी देना चाहता हूं। यह सरकार कितना लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और लोगों की समस्याओं के साथ उनका कितना कंसर्न था यह इससे स्पष्ट हो जायेगा। अम्बाला ड्रेन के नाम से ड्रेनेज की एक योजना बनी। इस योजना को बने हुए नौ साल हो गये हैं लेकिन अभी तक यह योजना कागज़ों तक ही सीमित है उससे आगे नहीं बढ़ सकी। उस योजना की प्रपोज़ल उस समय तैयार हो गई थी इस योजना की उस समय लागत राशि केवल 10 करोड़ रुपये ही थी। आज जब मैंने देखा कि हल्की सी बरसात हो जाने पर भी सारा अम्बाला शहर डूब जाता है इसलिए जब मैंने अधिकारियों से इस योजना के बारे में पूछा तो आपको यह जानकार आश्चर्य होगा मैं आपके माध्यम से यह जानकारी इस पूरे महान सदन को देना चाहता हूं कि अब यह योजना ओवर बजट हो चुकी है और इस समय इस योजना की लागत राशि 10 करोड़ रूपये से बढ़कर 60 करोड़ रुपये हो गई है।

श्री सभापति : असीम जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप जल्दी वाईंड-अप करें।

श्री असीम गोयल : सभापति महोदय, इसी तरह से अगर सीवरेज की बात की जाये तो सीवरेज के नाम पर जो करोड़ों रूपये का घोटाला अम्बाला शहर में हुआ है उसको सारा शहर जानता है क्योंकि सारे शहर को खोद दिया गया है। अम्बाला शहर ऐसा पहला शहर होगा जिसमें सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। सड़कें और बस-स्टैंड अम्बाला शहर से गायब हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं भी अम्बाला शहर में बदहाली में थी लेकिन यह तो हमारी सरकार आने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भला हो जिन्होंने उस 200 बैड के हॉस्पीटल को 300 बैड में अपग्रेड करने के लिए फाईल चलाई है उसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री और सरकार का धन्यवाद करता हूँ।

श्री सभापति : गोयल जी आप वाईंड अप कीजिए।

श्री असीम गोयल : सभापति महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिन लोगों ने सोचा था कि यह सत्ता केवल हमारी जेब में है, हरियाणा की जनता ने हमें जीवनभर का पट्टा लिख कर दे दिया है, जनादेश दे दिया है मैं उनके लिए केवल एक लाईन कहना चाहता हूँ कि :-

समय के एक तमाचे की देर है प्यारे,
फिर तेरी बादशाही क्या, फिर मेरी फकीरी क्या ?

[श्री असीम गोयल]

हमारी सरकार का और हमारा केवल एक ध्येय है, एक मंत्र है कि "सबका साथ, सबका विकास"। मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर एक विकसित और संगठित हरियाणा का निर्माण करें। धन्यवाद।

श्रीमती प्रेमलता (उचाना कलां) : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस गरिमामयी सदन में मुझे बोलने के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे उचाना कलां से टिकट दिया तथा उचाना वासियों का सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे जिता कर यहाँ बैठने का मौका दिया है। मैं इस आशय से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि प्रजातंत्र में विचारों की अनुभूति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मनुष्य को समाज में समान अवसर प्रदान करती है। यह सब प्रजातंत्र में ही सम्भव है। सभापति महोदय, मेरी पृष्ठभूमि सैनिक परिवार से है। मेरे पिता जी फौज में कर्नल थे। इसलिए अनुशासन, संयम और लक्ष्य की प्राप्ति का जो जज्बा पैदा होते ही मिलता है वह आज भी मेरे खून में है। मैंने पिछले 4 दशकों से हरियाणा की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है वह बात अलग है कि स्वयं यहाँ पर पहली बार चुन कर आई हूँ। जब आदमी खुद चुन कर आता है तभी पता चलता है कि हकीकत क्या है। 40 साल से भी ज्यादा समय से मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई हूँ। जब आदमी गाड़ी में बैठता है और ड्राईवर कोई और हो तब उसको रास्तों का पता नहीं चलता लेकिन जब आदमी खुद गाड़ी चलाता है तो पता चलता है कि रास्ता कैसा है और उसमें दिक्कतें क्या हैं? सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही अपनी बात केन्द्रित रखना चाहती हूँ। आज हरियाणा को एक प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है, चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, चाहे वह सेना में युवाओं के बलिदान की वीरगाथाएं हो, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न से लड़ने का प्रयास हो। मुझे लगता है कि अलग पंजाबी सूबे की मांग उठने के बाद ही हरियाणा अस्तित्व में आया है। अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग हरियाणा के लोगों की नहीं थी बल्कि अकालियों के आन्दोलन की वजह से हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया और हरियाणा को अस्तित्व में आये आज 48 साल हो गये हैं। जो राजनैतिक पंडित और अर्थशास्त्री थे वे यहाँ तक कहते थे कि हरियाणा के पास तो अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं होगी लेकिन मैं यह बात गर्व से कह सकती हूँ कि हरियाणा प्रदेश की गिनती आज समृद्ध, प्रगतिशील और विकासशील प्रदेशों में की जाती है। इसका श्रेय मैं किसी राजनेतिक दल या किसी एक नेता को नहीं देना चाहती क्योंकि हरियाणा की बहादुर जनता ने मेहनत की है जिन्होंने अपनी कड़ी लगन व मेहनत से ये सब हासिल किया है। जो राजनेताओं व राजनैतिक दल है यह तो सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए हैं। लोगों को आधारहीन और खोखले नारे दिए उनसे लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ नेताओं की स्वार्थपूर्ति जरूर पूरी हुई है। चाहे वह किसी भी दल के नेता हों। 48 साल हरियाणा की राजनीति नकारात्मक सोच के लोगो को पहुंचाने में रही। इसका दोष अगर किसी एक को जाता है तो वह नेताओं की संकीर्ण सोच को जाता है। इनेलो कांग्रेस को दोषारोपण करे तो इनेलो सत्ता में आ जाती है लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा है। हरियाणा की जनता के सामने अपने आप को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करके यह संभव किया कि आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के मतदताओं ने एक निर्णायक की भूमिका निभाई और बी.जे.पी. को स्पष्ट बहुमत देकर राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। स्पष्ट तौर पर इस क्षेत्रवाद, स्वार्थवाद, परिवारवाद की राजनिति को दरकिनार किया है। आजकल का युवा वर्ग यह कतई नहीं चाहता कि

इस ओछी और घटिया राजनीति को बर्दास्त करे। इसलिए स्वार्थी नेताओं की स्वार्थ सिद्धि प्राप्त हो उसे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां से समान अधिकार मिले। उसके प्रतिभा की पहचान हो और उसके गुणों की कदर हो। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इन सारी विशेषताओं के साथ, एक नई सोच के साथ, एक स्थिर सरकार देने के लिए आगे बढ़ी है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में "सबका साथ, सबका विकास" करने के लिए योजनाएं पटल पर रखी हैं। इसके बाद मैं खेलों के बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी कि हमारे जो खेल मंत्री हैं उन्होंने जो कॉम्प्रीहैन्सन स्पोर्ट्स पॉलिसी अडॉप्ट की है फोक्स सिर्फ इस बात पर नहीं है कि विजेताओं को हमने कितनी धन राशि दी। जैसे कि पिछली सरकार का स्लोगन था कि पदक लाओ और पद पाओ या पदक लाओ और ईनाम पाओ लेकिन हमारे खेलमंत्री ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हमारे खिलाड़ियों को कैसे तैयार किया जाए। लेकिन उस बात के लिए मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इण्डिया ने तीन जिले चुने हैं अम्बाला, सोनीपत और रोहतक लेकिन मैं किरण जी की बात का समर्थन करती हूं कि भिवानी और जीन्द में भिवानी ने तो बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए हैं लेकिन जीन्द इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां पर कोई स्टेडियम नहीं है। आज भी रोहतक को सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि रोहतक का स्टेडियम अच्छा है तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि जीन्द को भी इस लायक समझा जाए और यहां पर भी एक अच्छा स्टेडियम बने ताकि यहां के बच्चे भी अपने आपको खेल जगत में आगे ला सकें। जीन्द और भिवानी में भी इतने अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकते हैं लेकिन यहां अभी भी अनदेखी की गई है। इसलिए मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि जीन्द में भी एक स्पोर्टस अकादमी होनी चाहिए क्योंकि अम्बाला सोनीपत में तो बहुत पहले से चल रही है और रोहतक में अभी नई-नई इन्ट्रोड्यूस हुई है। जहां तक महिलाओं की बात है मैं चाहती हूं कि महिलाओं को उभारने के लिए अगर अलग से स्टेडियम नहीं दे सकते तो उस स्टेडियम में कुछ हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि जहां पर लड़कियां प्रैक्टिस कर सकें। मैं चाहूंगी की उनके जो कोच हों वह भी महिलाएं ही हों क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पुरूष कोच होते हैं हमें कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। लड़कियों का शोषण किया गया, उनको आगे करने के लिए उनसे कुछ कंडीशंज मनवाई गई। इसलिए महिलाएं अगर कोच होंगी तो लड़कियों का भय खुलेगा और वह स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस कर सकती हैं जिसके लिए कई बार कपड़े भी आदमी के पहनने पड़ते हैं जैसे स्वीमिंग है या कुश्ती है। ऐसे में अगर महिला कोच होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज की महिला घर के काम के साथ-साथ ऑफिस में भी काम करना चाहती है। मैंने एक बार सभी सरपंचों की मीटिंग ली थी। इस बारे में मैं एक बार केरल भी गई थी। मैंने सरपंचों की मीटिंग में सरपंचों के नाम बोलने शुरू किए जैसे मैंने कहा कि गीता, तो एक आदमी खड़ा हो गया जो कि उसका पति था जब मैंने उससे पूछा कि गीता कहाँ है तो वह कहने लगा कि वह तो घर पर है। फिर उसके बाद मैंने सुमन सरपंच का नाम लिया तब भी आदमी खड़ा हुआ और बोला कि मैं ही हूँ सुमन। सभापति महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में यह एक प्रथा चली आ रही है कि औरत को हमेशा ही पीछे रखा जाता है जैसे उसके सरपंच बनने पर उसका आदमी ही सरपंच कहलाता है। सभापति महोदय, यह प्रथा भी खत्म होनी चाहिए क्योंकि आज शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, वह लड़कियों के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए है। सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आते हैं तब लड़कियाँ ही सबसे ज्यादा नम्बर लेकर पास होती हैं। सभापति महोदय, जब नौकरियों की बात आती है तो लड़कों को ही सबसे अधिक मौका मिलता है। मैं चाहूँगी कि चाहे महिला शादी-शुदा हो चाहे वह स्कूल या कॉलेज में

[श्रीमती प्रेमलता]

पढ़ती हो उनकी प्रतिभा को पहचाना जाना चाहिए ताकि वह अपने आप को आगे ला सके। सभापति महोदय, मैंने शिक्षा मंत्री जी के सामने इस बारे में बात भी की थी। "बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ " अभियान को सुदृढ़ करने के लिए हम लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोलें। सभापति महोदय, लड़कियों के लिए बसों का भी इंतजाम करें जैसे दिल्ली में यूनिवर्सिटी के लिए स्पैशल बस चलती है उसी तर्ज पर हरियाणा प्रदेश में भी लड़कियों के लिए बसें चलाई जायें। सभापति महोदय, लड़कियों के पढ़ने के लिए चार-पांच गाँवों को मिलाकर अलग बसें चला दी जायें। उससे जो लड़कियों के माँ-बाप है उनमें भावना पैदा होगी कि मेरी लड़की सुरक्षित कॉलेज में पढ़ने जायेगी और सुरक्षित ही घर वापिस आयेगी। सभापति महोदय, जब लड़का और लड़की इक्ट्ठे कॉलेज जाते हैं। जब जवान लड़का किसी लड़की को छेड़ देता है तो यह बात लड़की के माँ-बाप को पता लगती है तो लड़की को कह दिया जाता है कि अब घर बैठ जाओ, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है इसलिए महिलाएँ आगे नहीं बढ़ पाती। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में लड़कियों के लिए दोबारा से इस पर गौर करें कि उनके लिए कॉलेज में जाने के लिए स्पैशल बसें चलाई जायें। सभापति महोदय, जहाँ तक स्किल डिवैल्पमैंट की बात है तो उसमें 70 प्रतिशत एश्योर्ड नौकरी है और स्किल डिवैल्पमैंट का मतलब यह नहीं है कि आई.टी.आई. से कोर्स करके नौकरी के लिए भटकते फिरें। स्किल डिवैल्पमैंट को तो शिक्षा पद्धति में ही शामिल कर दिया जाना चाहिए चाहे वह बढ़ई का काम हो, चाहे वह सिलाई का काम हो या चाहे मेकअप वगैरह का काम हो। आजकल स्किल डिवैल्पमैंट से जो डिग्रियाँ हासिल होती हैं उससे 77 प्रतिशत एश्योर्ड जॉब होती है। सभापति महोदय, मैं अब स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहती हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर गाँव में नहीं जाना चाहता है तनख्वाह तो गाँव से ही लेंगे और डेपूटेशन करवाकर बड़े-बड़े शहरों में अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में चले जाते हैं अगर हम पैमाना तय कर दें कि आपको डॉक्टर बनने के बाद 3 साल या 5 साल तक गाँव में ही गुजारने पड़ेंगे तो उसका मांईड उसी तरह से तैयार हो जायेगा कि मुझे पहले पांच साल गाँव में ही नौकरी करनी पड़ेगी। सभापति महोदय, यदि वह इन सब बातों का शुरू से ही अनुसरण कर लेता है तो ठीक हो जायेगा। सभापति महोदय, जब वह शुरू-शुरू में डॉक्टर बनता है तो उनके बच्चे छोटे होते हैं वह पढ़ने लायक नहीं होते हैं क्योंकि उनकी उम्र छोटी होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि डॉक्टरों के लिए दो अलग-अलग काडर बना दिए जायें एक रूरल काडर और दूसरा अर्बन काडर। क्योंकि कई बार आपने भी देखा होगा कि जो गाँव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं जिनको क्वैक भी कह देते हैं। ये लोगों की जिंदगियाँ ही खत्म कर देते हैं क्योंकि वह अनपढ़ लोग होते हैं उनको यह नहीं पता होता कि हमें जो दवाई दी जा रही है, उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। उनको यह भी नहीं पता होता कि दवाईयाँ जो दी जा रही है हमें कितना फायदा करेगी? 20-25 दिन लगातार बीमार रहने से लोगों का काफी पैसा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वह अपने नजदीकी अस्पताल जैसे हिसार, रोहतक या पटियाला आदि में मरीज को ले जाते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु तक हो जाती है। इस तरह से झोला छाप डॉक्टर तभी बंद होंगे जब डॉक्टरों की ड्यूटी गाँव में लगेगी। सभापति महोदय, मैं अब किसानों के बारे में कहना चाहती हूँ। जहाँ तक किसान की बात आती है तो चाहे मेरे पिता जी फौज में रहें हों लेकिन हमारी पृष्ठभूमि किसान की है। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान देश के लोगों का पेट भरता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था। देश में 70 प्रतिशत अन्न भंडारण खासकर हरियाणा, पंजाब और

पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान करते हैं। सभापति महोदय, इसके बावजूद भी किसान का पेट खाली और जेब भी खाली ही रहती है क्योंकि किसान को फसल के अच्छे भाव नहीं मिलते हैं। सभापति महोदय, यदि किसी तरह की आपदा वगैरह आ जाती है तो किसान बेचारा वैसे ही मर जाता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने किसानों की भूमि की सी.एल.यू. की है और बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उनकी जमीन दी है। वे आज किसानों की बात करते हैं। सभापति महोदय, पिछली सरकार की यह बात बहुत बार आ चुकी है कि किसानों को 2 रुपये, 3 रुपये और 50 रुपये तक का मुआवजा दिया गया। सभापति महोदय, इस तरह से किसानों का मज़ाक उड़ाया गया। सभापति महोदय, जब देश की सीमाओं पर जवान भेजे जाते हैं, तब तो किसान याद आते हैं। जब किसानों को लाभ देने की बात आती है तो उद्योगपति दिखाई देते हैं। यह जो सी.एल.यू. के नाम पर चक्रव्यूह चल रहा है, चाहे वह फरीदाबाद की बात हो, गुड़गांव की बात हो या फिर सोनीपत की बात हो, इन इलाकों में जो भेदभाव किया गया है, वह समाप्त होना चाहिए।

श्री सभापति : मैडम जी, थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात को वाईंड अप कीजिए।

श्रीमती प्रेम लता : सभापति महोदय, अब मैं अपने जीन्द जिले की बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं जीन्द जिले से अकेली विधायक नहीं हूँ। मेरे साथ जुलाना हल्के से माननीय सदस्य श्री परमिन्दर सिंह ढुल, जीन्द हल्के से डॉ. हरिचन्द मिढ़ा और एक आजाद उम्मीदवार भी हैं। सभापति महोदय, पिछले 15 सालों से जितना भेदभाव जीन्द जिले से किया गया है, शायद ही किसी और जिले से किया गया हो। सभापति महोदय,15 साल में चौटाला साहब की इनैलो पार्टी की भी सरकार आ गई, जो स्वयं चौटाला साहब, नरवाना हल्के से मुख्यमंत्री थे और 10 साल के अन्दर हुडा साहब की कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आ गई। सभापति महोदय, इनैलो पार्टी व कांग्रेस पार्टी की सरकारों द्वारा जीन्द जिले से जितना भेदभाव किया गया शायद उतना भेदभाव किसी और से नहीं किया गया।

श्री नसीम अहमद : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहता हूँ कि मैडम प्रेम लता जी भी पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी के राज में शामिल थी। मैडम आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी में आये हैं, पहले तो आप भी कांग्रेस पार्टी की गाड़ी चला रहे थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्दर सिंह संधू : सभापति महोदय, मैडम पिछले 10 सालों से आप खुद कांग्रेस पार्टी में शामिल थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती प्रेम लता : सभापति महोदय, मैं अपना खुद का एक अनुभव सुनाती हूँ। पिछले रविवार को जब मैं दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग के लिये चली, जब मैं रोहतक पहुँची तो वहां पर पुलिस खड़ी मिली। पुलिस ने मुझसे कहा कि मैडम आप यहां से मत जाईये, या तो गोहाना होकर के जाईये या हिसार रोड से निकलकर जाईये क्योंकि आगे टिटोली गांव में किसानों ने जाम लगा रखा है। सभापति महोदय, मैंने कहा कि मैं कोई भी बहाना बना लूंगी, आप मुझे जाने दीजिए। पुलिस ने आग्रह किया कि मैडम आपकी गाड़ी पर तो भारतीय जनता पार्टी की झंडी लगी

[श्रीमती प्रेम लता]

हुई है, आपको तो वहीं बिठा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सभापति महोदय, मैं फिर बहु अकबरपुर की तरफ से हिसार रोड़ पर आई, रास्ते में मुझे आगे चलकर 2-3 गांवों में से गुजरने पर किसी ने कहा कि आप बाईपास से जाईये। सभापति महोदय, यह सुनने की बात है। तीन दिन से लगातार बारिश हो रही थी और जब मैं लाखनमाजरा पहुँची मेरी गाड़ी ने सड़कों की दुदर्शा और स्पीड ब्रेकरों के कारण इतनी जोर-जोर से झटके खाए। जब मैं नरवाना पहुँची तो मुझे पता चला कि खराब सड़क और स्पीड ब्रेकरों से टकराने के कारण मेरी गाड़ी की टंकी से तेल निकल रहा था। सभापति महोदय, इस प्रकार से विकास के नाम से यह भेदभाव 15 सालों से जीन्द क्षेत्र से किया जा रहा है। कोई भी डिवेलपमैंट नहीं हुई है। एक बाईपास मंजूर हुआ था। उस बाईपास पर आज टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, पटियाला चौंक पर उस रास्ते से जो लोग अपनी कार से गुजरते थे, अब उस रास्ते से उनका भी जाना मुश्किल हो गया है। सभापति महोदय, भेदभाव के कारण ही हम पिछड़े हुए हैं। वहां पर न तो कोई कॉलेज है, न कोई इन्स्टीट्यूशन है, न ही कोई मेडिकल कॉलेज, न ही कोई इंडस्ट्री लगी हुई है और न ही कोई सड़क बनाई गई है। इस तरह से जीन्द जिले में विकास का कोई भी काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अब अस्तित्व में आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह जीन्द में विकास करवायेगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इसमें जीन्द जिले के सभी विधायक विकास कार्यों के लिये सहयोग करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : सभापति महोदय, अभी हमारी बहन प्रेम लता जी इतना बढ़िया बोली है। माननीय सदस्य श्री जसविन्द्र सिंह संधू और नसीम अहमद ने कहा कि आप भी पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी के राज में थी। यह बात तो हमारी बहन श्रीमती किरण चौधरी अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि सरकार में तो वो भी थी। (विघ्न) सभापति महोदय, 10 साल का दर्द बड़ा भंयकर है हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारी बहन श्रीमती प्रेम लता उस सरकार में थी यह तो चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने जिस दिन भारत सरकार के मंत्री के नाते ओथ ली उस दिन कहा कि मेरे साथ 40 साल तक कांग्रेस सरकार में कॉमेडी हुई है और मैं 40 साल तक इस पार्टी का ऑल इण्डिया लीडर रहा हूँ। सभापति महोदय, जो व्यक्ति 40 साल से किसी पार्टी का ऑल इण्डिया लीडर रहा हो, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने केवल 40 दिन के अन्दर ही भारत सरकार के मंत्री के रुप में ओथ दिलाकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है।

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मेरे से जबर्दस्त लगाव रहा है क्योंकि माननीय मंत्री हमारे इलाके से संबंध रखते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का दरवाजा उनके लिये हमेशा के लिये खुला हुआ है, वे कभी भी आ सकते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : सर्वशक्तिमान एको, सत्यम् एको विप्रा बहुधा वदन्ति। अब तो सारे रास्ते श्री नरेन्द्र मोदी की तरफ जा रहे हैं, आप भी इस पर विचार करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : शर्मा जी, दिल्ली ने तो आपको रास्ता दिखा दिया है और अब बिहार भी दिखा देगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : सभापति महोदय ***

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति महोदय ***

श्री सभापति : अब कुलदीप शर्मा और मैडम किरण चौधरी जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री रामविलास शर्मा : मैडम किरण चौधरी जी, You are zero in Delhi. You are talking about Delhi.(interruption) पूरे ब्रहमांड में नरेन्द्र मोदी जिन्दाबाद होंगे। जो पिंड में होता है वही ब्रहमांड में होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह : आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर शुरू हुई चर्चा विभिन्न चरणों से होती हुई, विभिन्न आयामों को छूती हुई मुझ तक पहुंची है। जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में कहा था कि बजट सत्र लम्बा चलेगा और वरिष्ठ सदस्यों के साथ-साथ नये चुन कर आये सदस्यों को भी अपनी बात कहने का भरपूर मौका दिया जायेगा और आपने मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण मैंने पूरे गौर से सुना है तथा पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि नई सरकार इस अभिभाषण में विकास के लिए कोई रोड मैप तैयार करेगी। मुझे यह भी आशा थी कि आजकल के ज्वलन्त मुद्दों के बारे में सरकार कुछ आशावादी घोषणाएं भी करेगी लेकिन सभापति महोदय आप देख रहे हैं कि अभिभाषण की दिशा किस ओर जा रही है। जब डॉ. रघुवीर सिंह कादियान किसानों के लिए मुआवजे के लिए बोल रहे थे तो सरकार की तरफ से टीका-टिप्पणी की जा रही थी कि आपने क्या किया था, आपने क्या किया था? ये सब बातें सुन कर मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा था कि पितामह सफल शासन के सूत्र बताईये तो भीष्म पितामह ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर कभी भी अतीत को कोसते हुये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त मत होना। अगर अतीत ही सुन्दर होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों। दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि गलतियों से सबक लेते हुये, उनमें सुधार करते हुये उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली की दिशा दर्शाता है। इस अभिभाषण को पढ़ कर यह नहीं लगता कि इन्होंने पितामह भीष्म की कही हुई बातों पर अमल किया है। विधान सभा चुनाव के दौरान हम देख रहे थे कि जनता में भारी आक्रोश था। मैंने जनता के आक्रोश को देखते हुये कुछ मुद्दे चिह्नित किये कि जनता में इतना आक्रोश क्यों था। जो समस्याएं थी उन समस्याओं का निवारण करने के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता को शायद भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ज्यादा अच्छा लगा होगा। इसलिए हरियाणा की जनता ने इनके मैनिफैस्टो पर मुहर लगाते हुये इनको सत्ता सौंपने का काम किया। वे मुद्दे थे महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों की भरमार, किसानों का हाहाकार, मंद व्यापार, बंद कारोबार, युवा बेरोजगार, महिलाओं पर अत्याचार, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ, क्षेत्रवाद तथा कानून व्यवस्था। सभापति महोदय, मैं इन सभी बिन्दुओं पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। हालाँकि किसी भी सरकार की 4 महीने के कार्यकाल से उसकी कार्यप्रणाली की पूरी तरह से विवेचना नहीं की जा सकती लेकिन उसका मूल्यांकन किया जा सकता

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री बलवान सिंह]

है कि सरकार की दिशा किस ओर है। जहां तक महंगाई की बात हैं । पिछले चार महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है । भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि महंगाई घटाने के लिए एक अलग से कोष की व्यवस्था करेंगे। कोष की व्यवस्था करनी तो दूर की बात है जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजर में क्रूड ऑयल की कीमतों में 50 प्रतिशत की गिरावट आ गई तब भी वर्तमान सरकार ने डीजल और पैट्रोल पर वैट लगाकर आम जनता की महंगाई से कमर तोड़ने का काम किया है। भ्रष्टाचार के घोटालों के बारे में पिछली सरकार की दस साल की कार्यप्रणाली के बारे में एक चार्जशीट हमारी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने का काम किया था और उस समय सदन के नेता ने हमें आश्वस्त किया था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर करेंगे लेकिन पता नहीं क्या बात हुई है उस चार्जशीट पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा में अधिकांश जनता की आजीविका का स्त्रोत खेती है और पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हताशा और निराशा के कारण आज किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि हरियाणा में एक पुरानी कहावत होती थी कि उत्तम खेती और मध्यम व्यापार। आज खेती लाभ का धन्धा नही रही है इसलिए किसान खेती से पलायन कर रहे हैं और हरियाणा के लोग आज क्रॉप होलीडे की घोषणा कर रहे हैं क्योंकि जो उनको उनकी फसल की लागत मिल रही है वह उनकी लगने वाली लागत से बहुत कम है। सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि मौजूदा सरकार पिछली गलतियों से सबक लेकर किसानों के बारे में जनहितैषी नीतियां बनाएगी सरकार किसानों की हितैषी बनने की बात तो करती थी कि हमारी सरकार आने के बाद हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया। खाद को लेने के लिए किसानों को अपनी बहु-बेटियों को ठिठुरती सर्दी में लाईन में सुबह पांच बजे लगाना पड़ा। जब किसानों के बारे में कोई मुद्दा आता है तो सरकार बड़ी-बड़ी बातें करती है। कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा किसान हूँ और कोई दूसरा कहता है कि मैं सबसे बड़ा किसान हूँ। आज जब किसानों के बारे में चर्चा की जाती है तो हमारा मुद्दा किसान का ही मुद्दा होना चाहिए कि हमारी किसानी प्रदेश में कैसे अच्छी हो। युवाओं के बारे में कहते थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, अब मैं युवा बेरोजगारों के बारे में अपनी बात कहना चाहता हूँ। सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि हम लाखों बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे और जो कर्मचारी ठेके पर लगे हुए हैं उनको रेगूलर करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर जब कम्प्यूटर टीचर्ज धरना दे रहे थे तो सरकार के एक मन्त्री जी ने वहां जाकर उन कम्प्यूटर टीचर्ज को आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आने के बाद आपको नियमित कर दिया जायेगा और आपको पिछले समय का वेतन भी दिया जायेगा।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कम्प्यूटर टीचर्ज के बारे में कहा, कम्प्यूटर टीचर्ज के साथ तीन बार मीटिंग मैंने भी

थी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उनके साथ मीटिंग हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने भी कम्प्यूटर टीचर्ज को नियमित करने के बारे में एक आर्बीट्रेटर नियुक्त किया है और उस आर्बीट्रेटर ने कम्प्यूटर टीचर्ज की इच्छा के अनुसार निर्णय दिया है और कम्प्यूटर टीचर्ज ने अपना धरना अब उठा लिया है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बिक्रम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यूरिया खाद की कमी के बारे में बात की है, उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को और इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि यूरिया की खरीद का आर्डर जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर महीने के लिए नहीं दिया गया था। इसलिए जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो सरकार के भण्डार में यूरिया पर्याप्त मात्रा में नहीं था। इसलिए नवम्बर के महीने में यूरिया की कमी रही है जिसके लिए पूरी तरह से पूर्व सरकार जिम्मेदार थी लेकिन दिसम्बर महीने में ऐसी कोई कमी नहीं रही।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, पिछली सरकार के समय में महिलाओं के साथ इतने ज्यादा दुष्कर्म हुए कि हरियाणा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता को पूरा विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जायेगी और हम जीरो परसैंट क्राइम अगेंस्ट वुमैन को लागू करेंगे लेकिन आज की सरकार की मौजूदा कार्यप्रणाली को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने कोई ठोस कदम उठाये हैं। पिछले दिनों महिला दिवस पर रोहतक में जो कांड हुआ उससे हरियाणा पूरे विश्व में बदनाम हो गया।

श्री अध्यक्ष : बलवान जी, आपको बोलते हुए दस मिनट हो गये हैं, इसलिए आप अब अपने भाषण को वाईड-अप कीजिए।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बलवान सिंह जी की महिलाओं के प्रति बड़ी पौजीटिव सोच है। जैसा कि उन्होंने रोहतक कांड का जिक्र किया, हमने within hour जो नौ अपराधी थे उनको पकड़ लिया। मैं पुलिस के अधिकारियों और जवानों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बरवाला काण्ड में पुलिस के 108 जवान घायल हुए परन्तु पुलिस की तरफ से एक भी लाठी व कंकड़ नहीं चला। जहां तक माननीय सदस्य रोहतक की घटना की बात कह रहे हैं, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि 9वें आदमी पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच वह सुसाईड कर गया। मैं तो फिर से हरियाणा पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री बलबान सिंह : अध्यक्ष महोदय, महिला दिवस पर सोनीपत में 62 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया था। आज सरकार जो नारा लगा रही है कि **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,** उस पर प्रश्न-चिह्न लग गया है क्योंकि लिंग पहचान के लिए एक किट की आन लाईन बिक्री हो रही है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के मामले में यह सरकार विफल हो गई है।

[श्री बलवान सिंह]

महिलाओं के उत्थान के लिए हमें 4 बातों पर सोचना होग। एक तो उनको शिक्षा दीजिए, दूसरे उनको सुरक्षा दीजिए, तीसरे उनको राजनीतिक संरक्षण दीजिए और चौथे उनको आर्थिक स्वावलम्बन दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले अपने मंत्रिमण्डल में लागू करें ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता व महिलाओं को अच्छा संदेश प्राप्त हो सके। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह पंगु हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिले के असंध में बलात्कार की घटना ने सरकार को शर्मसार कर दिया है। आज प्रदेश में 8 दिन में एक हत्या, एक बलात्कार और 10 घण्टे में एक अपहरण की घटना घटती है। (विघ्न) रिवाड़ी में बलात्कार की 5 घटनायें घट चुकी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती लतिका शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब तो प्रदेश में महिलाओं की सुनवाई ठीक से हो रही है। पहले तो एफ.आई.आर. तक भी दर्ज नहीं होती थी। महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी ने टिकट दिये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश का नागरिक सबसे पहले सुरक्षा चाहता है। मेरे हल्के फतेहाबाद में 2 महीने में 70 भैंसों की चोरी हो गई लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि एक भी चोर आज तक नहीं पकड़ा गया है। इस घटना के खिलाफ लोगों ने भूना में प्रदर्शन भी किया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप जल्दी वाइंड-अप करें।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी पूरी कर लूंगा। मैं एक गंभीर मामले पर चर्चा कर रहा था कि मेरे हल्के में 70 भैंसों की चोरी हो गई। आज कम से कम एक भैंस एक लाख रुपये की है। जब चोरी के खिलाफ लोगों ने भूना में प्रदर्शन किया तो डी.सी. व एस.पी. ने उनकी बात सुनी तथा जांच के आदेश दिये तथा पूरे स्टाफ को बदलने के लिए कहा। इस मामले में पुलिस कर्मचारी लालचन्द मुन्शी का तबादला किया गया लेकिन फिर भी वह भूना थाने में ही बैठा रहा, वह वहां से नहीं गया। बाद में उसने सुसाईड नोट में 16 आदमियों के नाम लिख दिये कि वह उनके कारण मर रहा है। इस बारे में पुलिस कप्तान व आई.जी. हिसार से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करायेंगे कि सुसाईड नोट असली है या नकली है।

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, कृपया अब आप बैठिए।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आपको बोलने के लिए 7 मिनट का समय दिया गया था लेकिन आपको बोलते हुए 14 मिनट हो गये हैं। अब आप केवल 1 मिनट में ही वाइंड-अप करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने ही जा रहा हूँ। मेरे हल्के में सेम की बड़ी भारी समस्या है। अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले सत्र में भी कहा था कि आपको बोलने के लिए भरपूर मौका दूंगा, इसलिए मुझे कंक्लूड करने दीजिए।

13.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सेम की समस्या है जो किसानों से सम्बन्धित है। इस बारे में मैंने प्रश्न भी लगाया था लेकिन किसी कारण वह प्रश्न नहीं लग पाया। शायद प्रश्नकाल खत्म होने का समय हो गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहता हूं कि सेम की समस्या अकाल और बाढ़ से भी बुरी समस्या है। इस समस्या के कारण किसान दाने दाने का मोहताज तो होता ही है लेकिन साथ ही वह पशु धन भी नहीं रख सकता। किसानों के क्रेडिट कार्ड की बात है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बैंकों को एक टारगेट दिया जाए कि कितने परसैंट तक वाले किसानों को एक्सैप्ट करेंगे क्योंकि बैंक बड़े-बड़े किसानों की बात को तो सुन लेते हैं लेकिन जिन किसानों के पास एक या दो एकड़ जमीन होती है उन किसानों की बात को नहीं सुना जाता इसलिए बैंकों को टारगेट दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : बलवान जी, आप बैठिए आपका समय समाप्त हो गया। आप 15 मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं (विघ्न) सभी सदस्य अपनी स्पीच 7 मिनट के हिसाब से तैयार करके आएं। मैं मानता हूँ कि 7 मिनट की बजाय 8 मिनट या 9 मिनट हो सकते हैं लेकिन अगर-एक सदस्य 7 मिनट की बजाय 15 मिनट बोलेगा तो सभी सदस्य अपनी बात नहीं रख पाएंगे। (विघ्न) करण सिंह दलाल जी, आप अपनी स्पीच शुरू करें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी ने श्वेत पत्र जारी किया ******

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी अब जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, I seek your protection as Hon'ble Member is continuing to speak. (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप समय देखकर अपनी बात शुरू करें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कोशिश करूंगा कि प्रदेश के जो अहम मुद्दे हैं मैं उन पर चर्चा करूं।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जितना समय निश्चित किया गया है उतने समय में ही अपनी बात खत्म करें ताकि सभी सदस्यों को टाइम दिया जा सके। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अंदर जो बी.जे.पी. की सरकार है, अगर इनके घोषणा-पत्रों को देखें तो इसमें ******और लोगों को गुमराह करने की बात कही गई है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल ने जो ******शब्द प्रयोग किया है वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उस शब्द की जगह असत्य शब्द यूज कर लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार बनी उस समय हरियाणा के लोगों को राज्यपाल के अभिभाषण से उम्मीद थी कि यह सरकार हरियाणा में न जाने कौन से अच्छे काम शुरू करने की बात लाएगी। इस सरकार से हरियाणा के लोगों को बहुत सी उम्मीदें जागृत हुई। अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने पलवल जिले के साथ लगता मेवात एरिया है। पलवल में जो यमुना निकलती है उसके किनारे पर माननीय हुड्डा साहब ने रेनीवैल स्कीम के तहत बोर करवा करके मेवात के प्यासे लोगों को पीने का पानी पहुंचाने का काम किया था।

श्री मूलचंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, रेनीवैल स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई थी और ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे और हसनपुर में पत्थर लगा था। यह सैंट्रल गवर्नमैंट की स्कीम थी। हुड्डा साहब के समय में यह स्कीम शुरू नहीं हुई थी। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि रेनीवैल की परियोजना ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेवात को पानी देने के लिए सवा चार सौ करोड़ रुपये से तैयार करवाई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, 2004 में रेनीवैल की परियोजना शुरू हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, रेनीवैल की स्कीम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री काल के दौरान मेवात जिले के लिए शुरू की गई थी और यह स्कीम 425 करोड़ रुपये की थी। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यमुना के किनारे पर बोर करवाकर मेवात और पलवल जिले के उन गांवों में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया जहां पहले एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं था और हथीन जो कि चौधरी केहर सिंह का हल्का है वहां पानी पहुंचाया गया। इसकी हमें बड़ी खुशी है लेकिन आज पलवल और मेवात के लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद इस सरकार से थी जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नदियों का और पानी के बंटवारे का जिक्र किया गया है। हमें उम्मीद थी कि सरकार यमुना के ऊपर बैराज बना करके जिसके न होने के कारण पलवल जिले की तमाम धरती का जल स्त्रोत नीचे जा रहा है उसको रोक कर ऊपर लाने का काम करेगी। इसके बनने से मेवात जिले को भी फायदा होता लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। मुझे इसका बहुत दुख है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यमुना के ऊपर बैराज बनाया जाना बहुत जरूरी है। यह पलवल, मेवात और फरीदाबाद इन तीनों जिलों की जीवन रेखा का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया गया है और यह बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे बिंदुओं को नहीं छूना चाहूंगा जिससे सत्तापक्ष को तकलीफ हो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान टाईम्स देश का माना हुआ अखबार है उसमें बहुत बड़ी खबर छपी थी कि बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ द्वारा पुत्र बीजक दवाई बेची जाती है। हम स्वामी रामदेव जी का आदर करते हैं वे हमारे हरियाणा प्रदेश से ही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ बेटी बचाने का सहारा ले रही है, दूसरी तरफ रामदेव जी पुत्र पैदा करने की दवाई बेच रहे हैं।

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम न लिया जाये। यह गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामदेव जी को हरियाणा प्रदेश का ब्रांड अंबेस्डर बनाया गया है और उसका पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। हमने उनसे प्रदेश में आयुर्वेदा और योगा पढ़ाने के लिए रिक्वैस्ट की है और उसी के लिए उनको ब्रांड अंबेस्डर बनाया गया है। जहां तक माननीय सदस्य दवाई की बात कर रहे हैं, हमने उसको एग्जामिन करवाया था। दवाई का नाम पुत्र जीवक है लेकिन उन्होंने अपनी दवाई पर कहीं यह क्लेम नहीं किया कि यह दवाई पुत्र पैदा करती है। यह वास्तव में एक फर्टीलिटी की दवाई है। माननीय साथी को इस बात की समझ नहीं है कि पुत्र जीवक क्या होता है और फर्टीलिटी क्या होती है। स्वामी रामदेव जी पूरी तरह से सरकार की बेटी बचाओ नीति के साथ सहमत हैं और वे भी इसी दिशा में काम करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत सरकार से अनुरोध है कि सरकार रामदेव जी को कुछ भी बनाये लेकिन वे व्यवसाय कर रहें हैं। उनके द्वारा खाने-पीने की चीजें भी बेची जाती हैं इसलिए उनको ब्रांड अंबेस्डर बनाने के बारे में अभिभाषण में जिक्र किया है, यह ठीक बात नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, अब कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों का मिथ्या बातें करने का काम हो गया है। (विघ्न) इन्होंने बात शुरू की है इसलिए अब इनको मेरा जवाब भी सुनना ही पड़ेगा। स्पीकर सर, जब से मौजूदा सैशन शुरू हुआ है तभी से ये हर बात को कहीं न कहीं कंफ्यूज करना चाहते हैं। जिस दिन से यह सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से इनका यही रवैया रहा है। ये किसी भी बात पर अननैसैसरी अड़ जाते हैं और वह भी ऐसे कि कहेंगे कि दो दुनी चार नहीं दो दुनी पांच होता है। हमने रामदेव जी से बात की और बात करने के लिए मैं खुद गया था और मेरे साथ आयुष के डॉयरैक्टर भी गये थे। हमने अभी उनके साथ हरियाणा प्रदेश में योगा और आयुर्वेदा को बढ़ाने की बात की है। हमने अभी तक केवल टैंटेटिव योजना बनाई है। इस बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्ज़ की भी एक मीटिंग हो चुकी है। (विघ्न) स्पीकर सर, ये जो संशय पैदा कर रहे हैं उनको क्लीयर करना बहुत ज़रूरी है। सर, हमने रामदेव जी से प्रदेश में योगा और आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए बात की है क्योंकि यह हिन्दुस्तान की पद्धतियां हैं। ये सभी पद्धतियां समय पर ठीक बैठी हुई और सिद्ध पद्धतियां हैं। हम हरियाणा प्रदेश को इसमें सिरमौर बनाना चाहते हैं। इस बारे में हमने उनसे जो-जो बातें की हैं मैं उन्हें सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि यह मुद्दा उठा दिया। अगर किसी और विषय पर इस बारे में चर्चा होती तो मैं उस समय भी बताता। हमारे हरियाणा में टोटल 6500 गांव हैं हम इन सभी गांवों में 2 एकड़ की ज़मीन में योगशाला और व्यायामशाला बनाना चाहते हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को रचनात्मक कार्यों की तरफ आकर्षित किया जा सके ऐसी हमारी सरकार की सोच है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों की तरफ आकर्षित करना चाहती है। जो हम प्रत्येक गांव में योगशाला बनवाना चाहते हैं उसमें योगा करवाने के लिए हमें एक ट्रेंड टीचर चाहिए और इसके लिए हम गांव के ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति को योग की ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं। इसलिए हमने बाबा रामदेव जी से यह प्रार्थना की है कि वे अपना कैप्शूल कोर्स चलाकर उनको ट्रेनिंग दे दें। इसमें कोई गलत बात नहीं है इसलिए विपक्ष के साथियों को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि हम प्रदेश के स्कूलों में भी ज़ीरो ऑवर में योगा करवाना चाहते हैं। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बात कहना चाहता हूं कि वे स्वामी रामदेव जी को कुछ बनायें चाहे न बनायें लेकिन जो राम लीला ग्राऊंड से वे ***पहनकर भागे थे उस *** की ये नीलामी ज़रूर करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो अभी माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा जी ने *** शब्द प्रयोग किया है इसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, इस प्रकार की बातें करने की कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों की मानसिकता बन गई है। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में सुबह 04.30 बजे 20 करोड़ लोग स्वामी राम देव जी को प्राणायाम और योग के मामले में देखते हैं। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बाबा रामदेव जी के साथ मेरे शहर नारनौल में आये थे और इन्होंने वहाँ बाबा रामदेव जी के साथ बैठ कर कपालभाती प्राणायाम किया और वे यह मानते हैं कि उनकी शूगर बाबा रामदेव जी के कपालभाती प्राणायाम से ही ठीक हुई है। अब करण सिंह दलाल बेचारे क्या करें उनके आगे उनके समधी बैठे हुये हैं और अगर वे ठीक से बात करना भी चाहें तो उनके साथ में कुलदीप शर्मा जी बैठे हुये हैं और उनके ज्ञान के बारे में सभी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का एक तरह का माइंड सैट हो गया है। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान बहुत पोजिटिव बोले थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : शर्मा जी, हम आपके ज्ञान को भी जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम भी शर्मा जी के ज्ञान के बारे में जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) हाईकोर्ट ने श्री कुलदीप शर्मा जी के बारे में स्ट्रिक्चर पास किया है। It is insult to Haryana. It is insult to this Chair. (Interruption) हम उन बातों में जाना नहीं चाहते।

Shri Kuldeep Sharma : Sir, on a point of personal explanation. (Interruption)

श्री अध्यक्ष : आप पहले मंत्री जी को अपनी बात कहने दो बाद में आपको टाईम मिल जायेगा, आप अपनी बात कह लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बाबा रामदेव के बारे में भी जो कुछ कह देते हैं। सरकार ने उनसे निवेदन किया तथा उन्होंने बहुत मुश्किल से इसको स्वीकार किया है। एक तरह का माइंड सैट हो गया है। कुछ मित्रों को वहम हो गया है और कुछ लोग ख्वाबों में अभी भी उस चेयर पर विराजमान हैं। कुछ लोग अभी भी डिक्टेशन देते हैं, कुछ लोग अभी भी धमकाने की बात करते हैं। कभी विधायक श्री कृष्ण लाल पंवार को धमका देते हैं और कभी मंत्री श्री अनिल विज को धमका देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे धमकाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ है। (हंसी)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक माइंड सैट हो गया है। लेकिन हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसको इनको स्वीकार करना चाहिए। उस जनादेश को मान कर सदन में व्यवहार करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, on a point of personal explanation. Previously when I was the Speaker, on my own wisdom passed an order as per the Constitution of this country and went for the judicial process. अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत ज्ञान की बात कही गई है। व्यक्तिगत ज्ञान किसमें कितना है, इसका पैमाना जब आदमी बोलता है तो वह सामने आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में शर्मा जी ने ऐसी बात कह दी थी जिसके बारे में खेद प्रकट करना पड़ा था। जिसके बारे में सदन से खेद प्रकट करना पड़ा हो, जिसके लिए माफी मांगनी पड़ी हो तो उसके ज्ञान की परिभाषा मैं जानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ हाईकोर्ट ने अगर कोई स्ट्रिक्चर पास किया हो तो उस जजमैंट को मंगवाईये। हालाँकि उस जजमैंट के अगैंस्ट हाई कोर्ट में डिविजन बैंच में एडमिशन हो चुका है। That judgement should be deemed as not existing. अगर हाईकोर्ट की किसी जजमैंट के बारे में सदन में चर्चा करवानी है तो क्या सदन को उस पर चर्चा करने का अधिकार है ? अगर अधिकार नहीं है तो इतने ज्ञानशील मंत्री जो 5वीं बार चुन कर सदन में आये हैं, इनको इस नियम के बारे में पता होना चाहिए। मैं तो दूसरी बार ही चुन कर आया हूँ। इनको यह पता होना चाहिए कि जो मैटर सबज्यूडिश है उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ज्ञान के मामले में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। Middle Tenancy State University में Rotary International Paul Harris Fellowship मैंने की हुई है। माननीय मंत्री जी स्कूल के लैक्चरर थे। कभी भी हमसे ज्ञान के मामले में मुकाबला मत करना। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : स्पीकर सर, शर्मा जी, बार-बार दूसरे को नीचा दिखाना और खुद चन्दगीराम बनने तथा भारत केसरी बनने का प्रयास कर रहे हैं। Speaker Sir, Hon'ble Punjab and Haryana High Court decision is in my hand. In the light of what has been dealt within detail, I hold the impugned order rendered on 13.1.2013 by the Speaker to be bad in law and hence, I set it aside. (interruption)

Shri Kuldeep Sharma : Is it a stricture? He does not know what is the stricture? I have been a lawyer. He is talking about stricture. I only pity on his shallow knowledge of law.

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, ये आपे से बाहर हो रहे हैं। I have also been advocate in punjab and haryana high court. (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने पता नहीं किस तरह से लॉ पास किया हुआ है। I have been a lawyer in Hon'ble Punjab and Haryana High court. I have got 67% marks in LL.B. from Panjab University. यह क्या बात हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, ****

श्री अध्यक्ष : श्री कुलदीप शर्मा जी की बात को रिकॉर्ड न किया जाए।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, मैं अपनी बात पूरी कर रहा था बीच में काबिलयत का झगड़ा पड़ गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, ये ऐसे कौन से बोलने वाले हैं। मैं इनको चार टर्म से जानता हूँ। सीट के ऊपर से उठने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी आज इतने बोलने वाले हो गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि मैं स्वामी रामदेव जी से बात करके आया। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था जो सरकार के रिकॉर्ड पर भी आ चुकी है और बीच में काबिलयत का झगड़ा पड़ गया और हमने पिछले पांच साल इनकी काबिलियत को कैसे झेला है वह हमें ही पता है। सारे सदन को पता है कि कैसी इनकी काबिलयत है। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सर, हमारी सरकार ने स्कूलों में भी योगा कराने की सोची है कि बच्चे स्कूल में जीरो ऑवर में योगा करें। उसके लिए सारे पी.टी.आईज को ट्रेनिंग दिलाने के लिए हमने बाबा रामदेव से बात की कि आप उनको 10-15 दिन की ट्रेनिंग दे दो ताकि वे स्कूलों में बच्चों को योगा करा सकें। उसके साथ ही हमारे पास लगभग 500 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उनका रिफ्रैसर कोर्स कराने के लिए हमने बाबा रामदेव को कहा है कि आप उनका रिफ्रैसर कोर्स करवाएं। सर, हम हरियाणा में नैच्यूरोपैथी और योगा को प्रमोट करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, अब बात तो बतानी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न किया था, मंत्री जी उसी का जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वामी बाबा रामदेव जी को लेकर मिथ्या प्रचार करने की कोशिश की है। (शोर एव व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने बाबा रामदेव की दवाईयाँ बिकवाने के लिए ठेकेदारी ले रखी है? (शोर एव व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि सदन में बहुत ज्ञानी आदमी इक्ट्ठे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि कभी भी ज्ञानी आदमी इक्टठे नहीं बैठ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूँ कि पिछले एक साल से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो आयुर्वेदा के लिए सारी डिस्पैंसरियाँ खाली पड़ी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य झूठा प्रचार प्रदेश की जनता में फैला रहे हैं। हमारी सरकार का बाबा रामदेव जी की दवाईयों से कोई ताल्लुक नहीं है।

Shri Kuldeep Sharma : Speaker Sir, "झूठ" is an unparliamentary word. It should be withdrawn from the proceedings of the House.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि क्या झूठ बोलना पार्लियामैंटरी है? ये देखिये सदन में सामने लिखा हुआ है, इसे पढ़ लें। (शोर एव व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलना अनपार्लियामैंटरी है। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है "झूठ" शब्द को असत्य कर देंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये सिद्ध करके दिखायें कि हमने बाबा रामदेव की दवाईयाँ खरीदी हैं। ये हाउस को मिसलीड कर रहें हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में फसलों के विविधिकरण की चर्चा की गई है यह बहुत अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जी हाउस में उपस्थित नहीं हैं। श्री रामबिलास शर्मा जी बैठे हुए हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो सॉयल टेस्टिंग कार्ड देने की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई है जितने भी सॉयल टेस्टिंग लैब हैं वहाँ पर स्टॉफ ही नहीं है आप इसे चैक करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्टाफ तो इनके पास है नहीं और ये सॉयल टेस्टिंग कार्ड देने की बात करते हैं। (शोर एव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जी हाउस में उपस्थित नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि ये अपनी असफलताओं और अपनी कमियों को भूल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य इतने गड्ढे छोड़कर गये हैं। उनकी स्वीकारोक्ति है कि आज सॉयल टेस्टिंग कार्ड देने के लिए कोई है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, इन सभी व्यवस्थाओं का निर्माण करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार ने पांच साल का विजन प्रस्तुत किया है कि हम क्या-क्या करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता दूँ कि हमारे पास कोई जादू का बटन तो है नहीं कि हम बटन दबा देंगे और सब चीजें एक दिन में हो जायेंगी। अध्यक्ष महोदय, पहले हम कांग्रेस पार्टी के खोदे हुए गड्ढे भरेंगे, उसे समतल करेंगे और फिर उसके ऊपर विकास करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्रॉप डायवर्सीफिकेशन पर बल दिया है। मैं मानता हूँ कि यह अच्छी बात है। क्रॉप डायवर्सीफिकेशन होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मक्का और बाजरा को न खरीदने का एफिडेविट दे रही है और यहाँ ये इन चीजों का बखान कर रही है कि फसलों का डायवर्सीफिकेशन करेंगे। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के 92 नं0 पर पयर्टन और संस्कृति के बारे में जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसा लग रहा है कि सरकार को केवल हरियाणा के अंदर जो हिन्दू मंदिर हैं या जो हिन्दुओं से जुड़े हुए संस्थान हैं उन्हीं की चिन्ता है। अध्यक्ष महोदय, मेवात का इलाका हमारे इलाके के साथ लगता है, परन्तु माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। मेवात के अंदर इतनी बड़ी-बड़ी धरोहर हैं। मेवात के लोगों ने बाबर से भी मुकाबला करके इस देश के लोगों का साथ दिया। जहाँ पर जैन धर्म के लोग हों जहाँ पर ईसाई धर्म के लोग हों और जहाँ पर इतने दूसरे धर्मों के लोग रहते हों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उनका कोई जिक्र नहीं किया गया हैं, केवल मंदिरों का जिक्र किया गया है या उनका जिक्र है जो केवल भारतीय जनता पार्टी

[श्री करण सिंह दलाल]

के मुद्दों को बढ़ावा देने वाले लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल एक वरिष्ठ विधायक है। जो पांच बार चुनकर इस महान सदन में आये हैं। अध्यक्ष महोदय, करण सिंह दलाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू और मुसलमानों को बांटने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन में वरिष्ठ विधायक श्री जाकिर हुसैन जी बैठे हैं, श्री नसीम अहमद विधायक जी बैठे हैं और श्री रहीशा खान विधायक जी बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार किसान और व्यापारी को आपस में लड़ाने और बांटने का काम कर रही थी। इसमें विधायक श्री जाकिर हुसैन जी, श्री नसीम अहमद विधायक जी और श्री रहीशा खान विधायक जी बैठे हुए हैं ये मेरी बात की ताईद करेंगे। माननीय सदस्य श्री केहर सिंह के जवाब में हमने बताया कि यह मंडना और मंडकोला मेवात का बीच है। मैं माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल से कहता हूँ कि आप हमारी जमकर आलोचना कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि यह कोई सपना नहीं है कि चार महीने में हम इतने बुरे हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल एक संघर्षशील और जुझारू नेता के तौर पर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप को हमने इसी सदन में सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आप इधर-उधर के ज्ञान से प्रभावित न हों, आप केवल ऑरिजनल ही बनकर रहें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजयपाल के अभिभाषण में बच्चों और नौजवानों के भविष्य की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर बड़ा है तो संविधान है, देश के अन्दर बड़ा है तो कानून है। कानून और संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लाखों नौजवान बच्चों ने पुलिस की भर्ती के लिए पिछले 2 सालों से गांवों की सड़कों पर दौड़ लगा लगाकर के अपने आप को तैयार किया। बाकायदा विडियोग्राफी के तहत उन्होंने फिजिकल टैस्ट पास किया। अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन बेटियों के तो फिजिकल टैस्ट के बाद इन्टरव्यू तक हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कौन से कानून और कौन से अधिकार के तहत उनके इन्टरव्यू रद्द कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा के 3200 नौजवान पिछले 2 वर्षों से इस टैस्ट और इन्टरव्यू के प्रोसैस को भुगत रहे थे, जिनमें जे.ई., कॉ-ओपरेटिव सोसायटी के इंस्पैक्टर, मण्डी सुपरवाईजर, एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एम) और एम.पी.एच.डब्ल्यू. (एफ), दुनिया भर की नौकरियाँ हैं जिनका प्रोसैस पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनके रिकॉर्ड को सील करके कमीशन के पास रखा हुआ है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह सरकार उन लाखों नौजवानों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर सकती है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय करण सिंह दलाल जी कह रहे हैं कि सरकार ने 4 महीने में भर्ती कर दी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 और वर्ष 2013 के शिक्षक भर्ती की साईंटिफिक वैरीफिकेशन करने के लिये कहा। शिक्षक भर्ती के लिये चयन बोर्ड बनाया गया उसके मैम्बर ऐसे बनाये गये जो उस बोर्ड के मैम्बर बनने की पात्रता नहीं रखते थे। अध्यक्ष महादेय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 1058 अध्यपाकों का चयन किया गया, जिनके सर्टिफिकेटों पर हाथ के

अंगूठे की जगह पांव के अंगूठे का निशान पाया गया। माननीय शुकन्तला खटक जी, इन अध्यापकों के दस्तावेज जिस संस्था में वैरीफिकेशन के लिए गये थे, उस नाम की कोई संस्था ही नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013 की भर्ती में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब तक इनको क्यों नहीं हटाया? अध्यक्ष महोदय, ऐसे फर्जीवाडे के ऊपर भर्ती हुई है। अध्यक्ष महोदय, क्या हम भी ऐसे ही फर्जीवाड़े को अपना लें? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में आने वाले दिनों में लगभग 1 लाख बेरोजगार नौजवानों की भर्ती करेगी, चाहे वह अध्यापक की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो, उनको अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार ही नौकरी दी जायेगी। **(इस समय मेजें थपथपाई गई)**

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि आप 1 लाख की बजाय 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दें, इसमें हम सरकार का समर्थन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जिन नौजवानों के पुलिस की भर्ती में फिजिकल टैस्ट पास हुए हैं, उनमें से कईयों की तो सगाई भी तय हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हैंडीकैप्ड लोगों को मदद देने के लिए जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हैंडीकैप्ड को जो पैंशन या स्टाईफण्ड मिलता है वह तब मिलता है जब उसकी उम्र 18 साल हो जाती है, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है। अध्यक्ष महोदय, ये कहां का इंसाफ है? एक अपाहिज बच्चा पैदा होता है तो सरकार को उस बच्चे के जन्म लेते ही उसको पैंशन देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अभी-अभी रामबिलास जी ने कहा है कि हम भर्ती करेंगे। ये भर्ती कहां से करेंगे जब इन्होंने स्टाफ सिलैक्शन बोर्ड ही नियुक्त नहीं किया है और टीचर्स रिक्रुटमेंट बोर्ड, पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड इन्होंने आज तक कांस्टीट्यूट नहीं किया है। इनका आपस में पदों के ऊपर इतना झगड़ा है कि ये अभी तक डिप्टी स्पीकर तक नहीं बना सके हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहीं-कहीं सुधरी है लेकिन पुलिस की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आप मेरे पलवल क्षेत्र में जाकर देखिये वहां पर पुलिस के संरक्षण में सौ-सौ ट्रक रात को चोरी का रेत लेकर चलते हैं। मैने वहां के डिप्टी कमीशनर को भी शिकायत दी है। वहां पर चोरी-डकैती बहुत ज्यादा हो रही हैं और लोगों से रैनसम मांगा जाता है। श्रीमती नैना सिंह चौटाला के सवाल के अनुसार प्रदेश में बहन-बेटियों के साथ आपकी सरकार आने के बाद बहुत बड़ी संख्या में बलात्कार हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। हमारे दलित समाज के लोग, गरीब लोग और बेरोजगार नौजवान माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से बहुत नाराज हैं। अत: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि दलितों और पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकार कोई अच्छी स्कीम लेकर आए ताकि हरियाणा के अंदर अच्छे तरीके से काम हो सके। आपका धन्यवाद। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क (असंध) : अध्यक्ष महोदय, 9 तारीख के राज्यपाल के अभिभाषण में हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को जो राहत दी है उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि मेरी बात के बीच में कोई न बोलें क्योंकि मैं किसी की बात के बीच में नहीं बोला हूँ। (विघ्न) मैं पहली बार विधायक बना हूँ लेकिन मेरा संघर्ष बहुत लम्बा है। विधानसभा एक ऐसी जगह है जिसमें आप सिर्फ दरवाजे से ही आ सकते हैं रोशनदान से नहीं आ सकते। हम पर प्रभु की कृपा हुई है जो पहली बार बहुमत से हमारी सरकार आई

[सरदार बख्शीश सिंह विर्क]

है। इस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी के गले यह बात नहीं उतर रही है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं कहना चाहता हूँ कि सन् 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था और तब से लेकर आज तक यह ही पता नहीं लगा है कि एक हरियाणा बना है या तीन हरियाणा बने हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 सालों में असन्ध विधान सभा क्षेत्र की अनदेखी होती रही है। अध्यक्ष महोदय, अभी आप से पहले माननीय कृष्ण लाल पंवार जी चेयर पर बैठे हुए थे। मैं बार-बार विनती कर रहा था कि उनके होते हुए मुझे बोलने का मौका मिले क्योंकि इन्होंने पिछले 15 साल से असन्ध विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व किया है। चाहे विकास के मामले में हो, चाहे नौकरियों के मामले में हो, पिछले 15 साल से असन्ध विधान सभा में कोई काम नहीं हुआ है। जयसिंहपुर गाँव में कहने को तो 132 के.वी.ए. का सब स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन वहां पर बिजली की कैपेसिटी केवल 66 के.वी.ए. ही चल रही है। इस तरह से मेरे असन्ध विधान सभा क्षेत्र के साथ बहुत अनदेखी हो रही है। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा के किसानों को दिन में आठ घण्टे ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली दी जाती रही है लेकिन मेरे हल्के असन्ध के किसानों को दिन में केवल पांच या साढ़े पांच घण्टे ही बिजली दी जाती थी। इस तरह मेरे हल्के के साथ बहुत अनदेखी की जा रही थी। इसी प्रकार से रतक गांव में एक बिजली घर बन रहा है तथा मुझे उम्मीद है कि यह अगले पैडी सीजन से पहले चालू हो जाये ताकि किसानों को बिजली के बारे में राहत मिल सके। इसी प्रकार से बन्दराले के चौगामें गाँव में जो पॉवर हाउस मंजूर हुए हैं वह वर्ष 2016-17 तक बन कर तैयार होने हैं। उनके बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसे वर्ष 2015-16 में बनाकर तैयार किया जाए ताकि मेरे कृषि प्रधान हल्के के किसानों को राहत मिले। पिछली सरकार के समय में 12.8.2014 को एक लड़कों का कालेज बनाया गया था। हमें बड़ी शर्म आती है क्योंकि स्कूल में दो कमरे बनाकर उस कालेज का उद्घाटन किया गया है। क्या कभी स्कूल के अन्दर भी कालेज चला है ? बड़ी हैरानी की बात है कि असन्ध जो कस्बा है यह जीन्द से 45 किलोमीटर, कैथल से 45 किलोमीटर, करनाल से 46 किलोमीटर और पानीपत से 44 किलोमीटर दूरी पर है। ये चारों जिले असन्ध से 45 और 44 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लड़कों को इतनी दिक्कत आती है कि दूसरे जिलों में पढ़ने जाने के लिए बसों में बड़ी दिक्कत आती है। इसी प्रकार जुण्डला भी असन्ध विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है वहां पर पिछले 48 सालों से कोई लड़कियों का कालेज नहीं है इसलिए लड़कियों को पढ़ने के लिए करनाल बसों में जाना पड़ता है और बड़े धक्के खाने पड़ते हैं और उनके साथ बेअदबी होती हैं इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जुण्डला में एक लड़कियों का कालेज बनाया जाये ताकि लड़कियों को पढ़ने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, बड़ी हैरानी की बात है कि पिछली सरकार के समय में पानीपत से लेकर झज्जर तक कई बाई-पास बनाये गये जोकि 80 फुट चौड़े बाई-पास बनाये गये थे लेकिन वर्ष 2013 में एक बाई पास असन्ध विधान सभा क्षेत्र में बनाया गया था जो केवल 12 फुट चौड़ा बनाकर असन्ध हल्के के साथ एक भद्दा मजाक किया गया। जहां तक असन्ध कस्बे में बस अड्डे की बात है वहां पर एक छोटा सा बस अड्डा है। अगर रात के बारह बजे कोई यात्री आ जाता है तो उसको कहीं रहने और बैठने की जगह नहीं है क्योंकि उस बस अड्डे पर कोई कमरा नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस बस अड्डे का दर्जा बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से फफड़ाना गाँव में शुगर मिल हैफेड की सहायता से चल रही हैं। मेरा हल्का पैडी का

एरिया है लेकिन किसानों को समय पर अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उस शुगर मिल में काफी जगह पड़ी है तथा उस जगह पर हैफेड की एक राईस मिल लगाई जाए। अगर यह राईस मिल बन जायेगी तो अलेवा, सफीदों, असन्ध और जुण्डला मण्डियों के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सब्जी मण्डी की बात है वहां पर कोई सब्जी मण्डी नहीं है। सड़कों पर सब्जी बिकती है। मैं कहना चाहूंगा कि नगरपालिका की जमीन भी उपलब्ध है जहाँ पर दुकानें भी बनी हुई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर एक सब्जी मण्डी बनाई जाये क्योंकि हमारा शहर इस जिले से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर अनाज मण्डी की भी समस्या है। अभी गेहूं की फसल आयेगी। किसान अपनी फसलों की पैदावार को सैलरों में फैंकने पर मजबूर होते हैं, उनकी फसलों की पैदावार सड़कों पर रूलदी-फिरदी है। मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर 37 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस एक्वायर्ड जमीन के अंदर जल्दी से जल्दी एक अनाज मण्डी बनाई जाये ताकि किसान का अनाज खराब न हो सके। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे शहर में कोई भी रैस्ट हाऊस नहीं है। पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर.) विभाग को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे शहर में नगरपालिका की जमीन उपलब्ध है। मेरी सरकार से माँग है कि वहां पर अपना एक रैस्ट हाऊस अवश्य होना चाहिए क्योंकि 45-50 किलोमीटर से कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अथवा कोई वरिष्ठ अधिकारी जब वहां पर आयेगा तो उसको रहने के लिए सुविधा मिल पायेगी। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर एक रैस्ट हाऊस बनाने की अनुमति प्रदान की जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर में कोई पार्क भी नहीं है। मेरी विनती है कि वहां पर जो नगरपालिका की 5-6 एकड़ जमीन उपलब्ध है उस जमीन पर एक पार्क बनाने की प्रोपोजल बनाई जाये। हर शहर में एक बढ़िया पार्क होना ही चाहिए। अभी बाबा रामदेव जी की बात चल रही थी। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी हमेशा हिन्दुस्तान की जनता को तन्दुरूस्त देखना चाहते हैं। इसलिए भी वहां पर एक पार्क की आवश्यकता है ताकि लोग सैर कर सकें उनकी सेहत तंदुरूस्त रहे। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : विर्क साहब, हरियाणा प्रदेश की धरती रण बांकुरों व शूरवीरों की धरती है। (विघ्न) जनानियों के कपड़े डालकर पुलिस से डरकर भाग जाना, यह कोई शूरवीरों का काम नहीं है। (हंसी)

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर 14-15 एकड़ तालाब की जमीन है। उस तालाब के अंदर इतनी गंदगी है कि यह तालाब बीमारियों का घर बना हुआ है। इस तालाब के नजदीक लगती बस्ती में रहने वाले लोगों को हमेशा बीमारियाँ फैलने का खतरा ही बना नहीं रहता है बल्कि वहां पर बीमारियाँ भी फैली हुई हैं। उन लोगों को काला पीलिया की बीमारी हो गई है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि उस तालाब को सुव्यवस्थित कर दिया जाये तथा उसकी रिटेनिंग वाल आदि बना दी जाये व सफाई करवा दी जाये तो बीमारियों से भी बचा जा सकेगा और उसका अच्छी तरह से सदुपयोग हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे यहां एक्सीयन, बिजली बोर्ड का नहीं बैठता है। जब किसान का ट्रांस्फार्मर जल जाता है तो नया ट्रांस्फार्मर व बिजली की तारें लेने के लिए वहां का जे.ई. या एस.डी.ओ. जब करनाल जाता है तो इस प्रक्रिया में उसको दोपहर के 12-1 तक बज जाते

[सरदार बख्शीश सिंह विर्क]

हैं, उसके बाद वह जे.ई. या एस.डी.ओ. फरलो मार जांदा है तथा करनाल ही स्टे कर लेता है परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र के किसान असंध में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में प्रात: 10.00 बजे से शाम के 4.00 बजे तक इंतजार करके अपने घर वापिस चले जाते हैं जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र के किसानों को बड़ी भारी दिक्कत आ रही है।

श्री अध्यक्ष : विर्क साहब, कृपया आप वाइंड-अप करें।

सरदार बख्शीश सिंह विर्क : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पक्का खेड़ा मोड़ से लेकर पबाना तक जो सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने कुछ दिन पहले उसकी एक प्रोपोजल बनवाई थी। लेकिन मुझे पता चला कि उस सड़क की प्रोपोजल रिपेयर की बन गई जबकि इस सड़क को वाईडन करने की प्रोपोजल बनाई जानी चाहिए थी किस कारण से इस सड़क को चौड़ा नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाये ताकि किसानों को अपना गन्ना शुगर मिल तक ले जाने में कोई दिक्कत न आ सके क्योंकि अभी वहां पर गन्ने से भरी ट्रालियाँ पलट जाती हैं जिससे किसानों को बहुत नुक्सान होता है। इसके अलावा एक और सड़क कतलाहड़ी से ऐंचला तक वाया बांसा है वह सड़क भी चौड़ी की जाये क्योंकि इस सड़क द्वारा किसानों को शुगर मिल तक अपना गन्ना ले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि मेरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। इस सदन में माननीय सदस्य श्री कृष्ण लाल पंवार जी बैठे हुए हैं उनको पता है कि असंध के साथ लगते 5-10 किलोमीटर एरिया का पानी इतना खराब है कि न तो वह पीने के लिए ही उपयुक्त है और न ही वह सिंचाई के लिए उपयोगी है। वहां पर जो नर्दक नहर जा रही है उस के बीच से 1 लाख 70 हजार राईट में यदि एक छोटा सा बंदराला माईनर निकाल दिया जाये जिसकी प्रोपोजल 1996 में बनाई गई थी, तो मैं समझता हूं कि असंध के किसानों को जो इतना नुक्सान हुआ है क्योंकि 50-50 एकड़ जमीन में खाने के लिए एक किलोग्राम जीरी भी पैदा नहीं हुई थी, इतना भारी नुक्सान जो सिर्फ खराब पानी की वजह से हुआ है, उसको रोका जा सकेगा। यदि वहां पर एक छोटा सा माईनर बनाकर तथा उस मोगे को बड़ा करके उन किसानों को थोड़ा बहुत नहरी पानी दिया जायेगा तो किसानों की जमीन उपजाऊ बनेगी क्योंकि अभी वहां के किसान मजबूरन अपनी जमीनें बेच-बेचकर उत्तर प्रदेश व दूसरें अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। किसानों की समस्या चल रही है और दो दिन से यहां शोर शराबा हो रहा है। यहां ओलावृष्टि और बारिश के बारे में काफी चर्चा हुई तो मैं कहना चाहूंगा कि यह तो कुदरत की देन है कि कभी धूप तो कभी छाया। यह तो कुदरत की देन है कि सूरज निकला, चढ़ा और ढल गया। जो अपने घर में गाय रखता है और जो भैंस रखता है और उसके दूध को बेच- बेचकर जो किसान बना है वही असली किसान है। जिसने 1947 में देश के बंटवारे के बाद यहां आकर जंगल को आबाद किया और जंगलों को उखाड़ उखाड़ कर मेहनतें की और मजदूरियां की वही किसान हो सकता है। ढाई करोड़ जनता की खून पसीने की कमाइयों को खाकर आज जमीनें बनाकर अपने आप को जो किसान समझता है मैं उसको किसान नहीं समझता। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एक समाचार देना चाहता हूं । 6 जनवरी को हमने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा था जिसमें मैंने उनको लिखा था कि हमारी स्टेट में कोटपुतली से लेकर हांसी तक का जो मार्ग है जिसमें कोटपुतली, नारनौल, महेन्द्रगढ़, दादरी, भिवानी और हांसी आते हैं इसको नैशनल हाइवे बनाया जाए । मुझे यह सूचना देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मुझे उनका पत्र मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है, "The proposal has been approved and the requisite notification is under publication. **(इस समय मेंजें थपथपाई गईं।)**

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्रीमती संतोष यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो घोषणा की है उसके लिए सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। पूरा अहीरवाल क्षेत्र इस काम के लिए उनका कृतज्ञ है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करूंगी जिन्होंने 9 मार्च को अपना अभिभाषण रखा। अभिभाषण सरकार का विजन होता है और सरकार की स्टेटमैंट होती है कि वह आने वाले दिनों में क्या क्या कार्य करने जा रही है। हमारे इस अभिभाषण में मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की है और जो योजनाएं बनाई हैं निश्चित तौर से इससे हरियाणा प्रदेश का चहुमुंखी विकास होगा और हम हरियाणा प्रदेश को ऊंचा ले जाने का कार्य करेंगें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास और यह संविधान की भावना के अनुरूप है। संविधान की भावना पूरी इक्वल ओपरचुनिटी देती है irrespective of class, caste and creed. उस भावना को पूर्ण रूप से इसमें सम्माहित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि अभिभाषण में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद पर गहरी चोट की गई है। मैं महेन्द्रगढ़ जिले से आती हूं, अटेली हल्का जो है वह एक तरफ तो राजस्थान से सटा हुआ है और दूसरी तरफ झज्जर और साल्हावास हल्के से सटा हुआ है, उसने पूर्ण रूप से क्षेत्रवाद की मार झेली है। अध्यक्ष महोदय, हमारे श्वेत पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि हरियाणा तीन भागों में बंटा हुआ है और यह बात पूर्ण सत्य है। अध्यक्ष महोदय, अगर रोड्स की बात करें तो मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का आदर करते हुए उनको बताना चाहूंगी कि साल्हावास-कोसली मेरे हल्के से 13 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। हमारे किसान भाई 13 किलोमीटर की यात्रा करके झज्जर की तरफ जाते हैं तो उनको पैरिस जैसी सड़कें नजर आती हैं जबकि मेरे हल्के में सारी सड़कों पर गढ्ढे नजर आते हैं जहां चलना बहुत ही मुश्किल है। क्षेत्रवाद की दूसरी बात करूं तो इस 10 किलोमीटर के एरिया के साथ नौकरियों में भी इतना भेदभाव रहा है कि महेन्द्रगढ़ का बच्चा नौकरियों के लिए तरसता रहा और रोहतक में पूरी तरह से बच्चों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्किटिंग बोर्ड की मैं बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग

बोर्ड के द्वारा जिला महेन्द्रगढ़ में पिछले दस साल के दौरान रिसोर्सिज जनरेशन का एक भी पैसा जिला महेन्द्रगढ़ पर खर्च नहीं किया जबकि रोहतक जिले में जितना पैसा जनरेट हुआ उससे कई गुणा ज्यादा पैसा खर्च किया गया। यह रिकार्ड की बात है। इस तरह का भेदभाव पूर्व सरकार के द्वारा हमारे जिले महेन्द्रगढ़ के साथ किया गया। इसी तरह से अर्बन डिवैल्पमैंट के क्षेत्र में भी जिला महेन्द्रगढ़ के साथ बहुत भेदभाव किया गया। वहां पर हुडा द्वारा एक भी नया सैक्टर पिछले दस साल के दौरान डिवैल्प नहीं किया गया और हुडा द्वारा जो रिसोर्सिज जनरेट हुए वे रोहतक जिले में खर्च किए गए। मेरे अटेली हल्के में एक भी नया सैक्टर डिवैल्प नहीं किया गया। महेन्द्रगढ़ और नारनौल में जो पुराने सैक्टर हुडा के हैं उनकी डिवैल्पमैंट की तरफ भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इस तरह से हर क्षेत्र में पिछली सरकार के समय में क्षेत्रवाद और वंशवाद का दंश रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ देने का लक्ष्य रखा है ताकि वे समाज में ऊपर उठ सकें। अंतिम व्यक्ति भी जीवन के प्रवाह में आये यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगी कि पहले वाली सरकारों ने गरीबों के बारे में बहुत बातें की लेकिन मैं फैक्ट्स के आधार पर बात करना चाहूंगी कि वर्कर सैस 2110 करोड़ रूपये का पिछली सरकार के समय खर्च नहीं किया गया फिर वह सरकार किस प्रकार से वर्कर्ज की बातें करती रही। ऐसे कार्य करके किस प्रकार से वह गरीबों की सरकार थी, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार ने अपनी कार्यप्रणाली में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है और प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 4 महीने के कार्यकाल के दौरान तहसीलों में ई-स्टैंपिंग और ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया है जो कि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है। इसी तरह से जीरो टोलरैंस की पॉलिसी, सी.एम. विंडो वैब पोर्टल आदि स्कीम्ज भी शुरू की हैं ताकि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लग सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चार महीने के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में भ्रष्टाचार और महंगाई पर लगाम लगी है तथा प्रदेश में प्रजातांत्रिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी कि शिक्षा के बगैर कोई व्यक्ति, प्रदेश या देश तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा किसी भी देश या प्रदेश की उन्नति का द्योतक रहती है। लार्ड मैकाले ने कहा था कि यदि हिंदुस्तानियों को देश प्रेम से भटकाना है तो यहां ऐसी शिक्षा प्रणाली शुरू की जाए जिससे यहां के बच्चे सरकारी बाबू ही बनकर रह जायें। पहले वाली सरकार ने भी इसी नीति पर चलते हुए सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक वार्षिक परीक्षा ही समाप्त कर दी और बच्चों को बिना पेपर दिए ही पास कर दिया जाता था जिसके कारण प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता ही खत्म होकर रह गई। यही वजह रही कि बड़ी क्लासिज में नकल एक महामारी की तरह फैल गई। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता लाने के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। उसके साथ इस सिद्धांत को सामने रखा है कि देश और प्रदेश को ऊंचा उठाना है तथा नकल जो कि एक महामारी की तरह प्रदेश में फैल गई है उसको भी रोकना है। शिक्षा को प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए to build the character of the youth and to inculcate the moral values in them की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है और इन बातों का नई शिक्षा नीति में पूरा ध्यान

रखा गया है। इसके साथ-साथ 1 से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा भी अब शुरू कर दी गई है। अध्यापकों की डायरी भी मेनटेन की जायेंगी। प्रदेश में बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए योगशालाओं और व्यायाम-शालाओं, मोरल वैल्यूज को फिर से लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के साथ-साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बच्चियों की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया है तथा मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में कन्या महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की आभारी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों की पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान इसलिए दिया है क्योंकि उनको जानकारी है कि पुरूष शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है और एक लड़की शिक्षित होने पर दो परिवार शिक्षित होते हैं तथा समाज उन्नति की तरफ बढ़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में नये महिला कॉलेज खोलने की घोषणा की है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, सर।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्रीमती संतोष यादव : स्पीकर सर, अब मैं अपने अटेली हल्के की बात करना चाहूंगी क्योंकि मैं वहां से विधायक हूं। अटेली हल्के में दो ब्वॉयज कालेज हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह बताना चाहती हूं कि गवर्नमैंट कालेज, कनीना में 1800 लड़कियां हैं और गवर्नमैंट कालेज, अटेली में 1700 लड़कियां हैं इसलिए हम अटेली में महिला महाविद्यालय खोलने की मांग करते हैं। लड़कियों की संख्या के हिसाब से अटेली में कालेज की 100 प्रतिशत पात्रता बनती है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि महिला कालेज के लिए गवर्नमैंट कालेज की 26 एकड़ ज़मीन भी देने के लिए गवर्नमैंट कालेज प्रशासन तैयार है। इसी प्रकार से अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो हमारे गिरते हुए लिंगानुपात की वजह से जो असंतुलन पैदा हो गया है उसने प्रकृति को झकझोर कर रख दिया है। विशेष रूप से हमारे महेन्द्रगढ़ और उसके साथ लगते 12 जिलों में लिंगानुपात बहुत कम रहा है। इस गिरते हुए लिंगानुपात के कारण ही प्रति दिन हमारे समाज में यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और छेड़-छाड़ की घटनायें निरंतर तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। इस समस्या की गम्भीरता को गहराई से समझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेन्द्र भाई मोदी ने "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम को पानीपत से शुरू किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस अभियान को बड़ी गम्भीरता से लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "बेटी बचाओ, बेटी

[श्रीमती संतोष यादव]

पढ़ाओ" कार्यक्रम को सफल बनाने की भीख मांगकर इस समस्या की गम्भीरता की व्याख्या की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने बेटियों के उत्थान के लिए कई योजनायें बनाई हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ जननी सुरक्षा योजना और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के साथ और भी कई योजनायें बनाई हैं। इसके साथ-साथ आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लिए धनराशि जुटाने के लिए हरियाणा कन्या कोष की भी स्थापना की गई है। सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा विधान सभा की सभी महिला विधायकों को 21-21 लाख रुपये अधिक खर्च करने के लिए कहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस दरियादिली के लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। इसी प्रकार से अगर कृषि की बात की जाये तो जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर लोगों की आजीविका खेती पर निर्भर करती है। हमारे प्रदेश में भूमि जोत छोटी होती जा रही है और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से अब ओलावृष्टि हो गई। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कृषि के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा उठाया है ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। इसके लिए किसानों को फसल चक्र बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके साथ-साथ किसानों को नये व आधुनिक कृषि यंत्र सबसिडाईज्ड रेट पर दिये जा रहे हैं। हर खेत का सॉयल कार्ड तैयार करवाया जा रहा है। अटल खेती-बाड़ी खाता योजना भी तैयार की जा रही है जिसके अंतर्गत हर किसान का रजिस्ट्रेशन होगा, भूमि का पूर्ण विवरण होगा, सॉयल का विवरण होगा और फसल का विवरण होगा। इसी प्रकार से सरकार द्वारा नये फाईनैंशियल ईयर से राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना को लागू करने का लक्ष्य सरकार द्वारा तय किया गया है ताकि अनटाईमली प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को बचाया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार 13-14-15 मार्च, 2015 को हरियाणा एग्रो समिट, 2015 का गुड़गांव में आयोजन करने जा रही है ताकि कृषि की विवधता पर विचार-विमर्श किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कृषि के साथ जुड़ा हुआ ही पशुधन है। हमारे प्रदेश में जितने लोग कृषि पर आधारित हैं उसमें पशु पालन भी उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। पशुपालन के लिए भी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। इसके लिए सरकार द्वारा गौ-संवर्धन और गौ-संरक्षण बिल लाकर सरकार ने इस ओर ठोस कदम उठाये हैं। इससे गौ माता जो वास्तव में ही हमारी माता है उसके संरक्षण और संवर्धन में विशेष योगदान मिलेगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहती हूं कि जिला महेन्द्रगढ़ में पशुधन विज्ञान केन्द्र खोला जाये क्योंकि इस समय अगर कोई पशु बीमार हो जाता है और उसका एक्स-रे करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे पशु को एक्स-रे के लिए हिसार लेकर जाना पड़ता है और कई बार रास्ते में ही पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इसलिए पशु पालकों की यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि महेन्द्रगढ़ में पशुधन विज्ञान केन्द्र खोला जाये। इसी तरह से मेरे हल्के के गांव पोला, पाथेड़ा और सीहोर में जलघर का निर्माण पिछले काफी साल पहले शुरू किया गया था। इनको पूरी तरह से अभी तक नहीं बनाया गया है और जो बन भी गये हैं वे भी ठीक तरह से नहीं बनाये गये जिसके कारण यहां पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए

ताकि आने वाले गर्मी के सीजन में वहां लोगों को पीने के पानी की कोई समस्या न हो। इसी तरह से अटेली हल्के के नावदी, रामपुरा, कांटी, खेड़ी, गणियार आदि गांवों में ग्राउंड वाटर जहरीला है जिसको पीने से लोग और पशु बीमार पड़ जाते है इसलिए इन गांवों में कैनाल वाटर सप्लाई स्कीम्ज बनाई जायें ताकि यहां के लोगों को भी पीने का स्वच्छ पानी मिल सके और इससे पहले आने वाले गर्मी के मौसम को देखते हुए इन गांवों में पीने के पानी की टैम्परेरी व्यवस्था भी की जाए क्योंकि गर्मी के मौसम में वहां के निवासी 300 से 400 रुपये में टैंकर मंगवाकर पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कनीना में पी.डब्ल्यू.डी. के गैस्ट हाऊस की मांग करती हूं क्योंकि वहां पर कोई गैस्ट हाऊस नहीं है। इसके अलावा मैं वहां पर आफिसर्ज के लिए कालोनी बनाने की भी मांग करती हूं क्योंकि वहां पर जो अधिकारी ड्यूटी करते हैं उनके रहने के लिए वहां पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य है कि हर खेत को पानी मिले चाहे इसके लिए कितने ही प्रयत्न क्यों न करने पड़ें। हमारी सरकार ने एक-एक बूंद पानी कैसे यूटीलाईज किया जा सके इस बात पर ध्यान दिया है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी, चाहे वह रेनूका-किशाऊ डैम की क्लीयरेंस की बात हो, चाहे वह ट्यूबवैल रिचार्जिंग की बात हो, चाहे वह रेन वॉटर हारवैस्टिंग की बात हो, चाहे लखवार-ब्यासी डैम की शुरूआत करने की बात हो चाहे मेवात एरिया में कोटला लेक की बात हो। इसी प्रकार से जो जे.एल.एन. कैनाल के लिफ्ट इरीगेशन के पम्प हैं उनकी सफाई और सभी चैनल्स की गाद निकालने के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो योजना बनाई है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारा महेन्द्रगढ़ का किसान सिंचाई पर निर्भर करता है। जे.एल.एन. कैनाल से खूबड़ा हैड से महेन्द्रगढ़ के लिए पानी आता है जो कि बाद में महेन्द्रगढ़ कैनाल में परिवर्तित हो जाती है । उससे आगे चल कर रामगढ़ डिस्ट्रीब्यूट्री, रामपुर डिस्ट्रीब्यूट्री, रामबास डिस्ट्रीब्यूट्री, मोहम्मदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री तथा भोजावास डिस्ट्रीब्यूट्री और रात्ता डिस्ट्रीब्यूट्री तथा अटेली सब-माइनर में बहुत ज्यादा गाद भरी हुई थी। मैं पूर्व की सरकार के बारे में विद ड्यू रिस्पैक्ट बताना चाहूँगी कि हमारी नहरों में 14-14, 15-15 फीट गाद भरी पड़ी है तथा पम्प हाउसिज भी गाद से भरे पड़े हैं मेरा एरिया ढलान में है जिसके कारण हमारी नहरों में एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचता। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जे.एल.एन. कैनाल की सफाई तथा मोटरें बदलने का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बिजली की अगर बात की जाये तो बिजली हर आदमी के लिए बहुत ही अहम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है तथा इसी के तहत यमुनानगर और पानीपत में दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट लगाने का फैसला किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ इसलिए मैं इस बात के लिए और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। हमारे हलके में कोई भी रोड़ ठीक नहीं है। अगर सबसे बुरी रोड्स की हालत देखनी हो तो अटेली हलके में देखी जा सकती है जो कि रोहतक के बिल्कुल नजदीक है। इसी प्रकार से रूरल डिवैल्पमैंट को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मंत्री द्वारा जो ग्राम सचिवालय की बात कही गई है तथा उसको पूरी तरह से पार्टीसिपेटिव, ट्रांस्पेरेंट तथा अकाउंटेबल बनाया है जो कि अपने आप में लाजवाब है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, अब मैं स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगी। पिछली सरकार में राव नरेन्द्र जी स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने दो बार मेरे साथ ही चुनाव लड़ा है। हमने सोचा था कि जिला महेन्द्रगढ़ का स्वास्थ्य

[श्रीमती संतोष यादव]

ठीक हो जायेगा, हॉस्पीटल्स ठीक हो जायेंगे लेकिन मुझे कहते हुये बहुत शर्म आती है कि हमारे जितने भी हॉस्पीटल्स हैं वे बहुत खराब हालत में हैं। उनमें कोई रैनोवेशन नहीं की गई और न ही कोई आधुनिक मशीन ही लाई गई। मैं कनीना की बात कहना चाहूँगी और मांग भी करना चाहूँगी कि कनीना का हॉस्पीटल बिल्कुल जर्जर हो चुका है। उसमें न ही कोई आधुनिक मशीन है और न ही स्टाफ उपलब्ध है। म्यूनिसिपल कमेटी हॉस्पीटल के लिए 8 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाने के लिए भी तैयार है इसलिए कनीना के हॉस्पीटल को दोबारा से बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार चुन कर विधान सभा में पहुंची हूँ और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं स्पोर्टस के बारे में भी बताना चाहूंगी। मैं इस बात को भी लेना चाहूंगी जैसे नेपोलियन ने कहा है "The battle of Waterloo was fought in the grounds of ends." तो मैं कहना चाहूंगी कि खेल के ग्राऊंड से ही हम सीखते हैं, बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं और महेन्द्रगढ़ के वीरों ने, हरियाणा के वीरों ने और विशेष रूप से मैं साऊथ हरियाणा के वीरों की बात करना चाहूंगी जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में अपनी जानें गंवाई हैं। वह केवल स्पोर्टस से गये हैं। अब मैं कहना चाहूँगी कि हमारे बाघोत गांव में, भाई शर्मा जी यहां बैठे हैं कोई भी बिरादरी चाहे वह हरिजन हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे पण्डित हो सारे के सारे पहलवान पैदा होते हैं, भाई साहब से पूछो। बाघोत गांव में गांव वाले 20 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। वहां पर एक ऐसी अकादमी बनानी चाहिए जिससे हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को स्पोर्टस में सुविधा मिले और वह देश की सेवा करने में आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, बोलना तो काफी था लेकिन गले के खराब होने से दिक्कत आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आप इस लिखे हुए को सदन में दे दो हम इसको कार्यवाही में शामिल कर लेंगे।

श्रीमती संतोष यादव : मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय का जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने इस क्षेत्रवाद और वंशवाद से निकालकर हरियाणा की जनता को एक नया सपना दिया है। हम सब मिलकर हरियाणा प्रदेश को ऊंचा उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद। (विघ्न)

श्री हरविन्द्र कल्याण : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी व सम्मानित सभी सदस्यगण मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। (विघ्न)

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाई-वे (एन.एच.डब्लू. 65) जिसको आप एन.एच.डब्लू.-52 बोलते हैं वह हल्का लोहारू से गुजरता है। वह रोड़ गांव बड़वा में और विधायक रणबीर गांगवा जी के गांव में इतना टूटा-फूटा है वहां पर बिल्कुल बुरा हाल है। कल भी सिवानी गांव में उसी रोड़ की वजह से एक नौजवान की मौत हो गई।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अभी आपको भी बोलने का मौका देंगे। तब आप बोलना।

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौण्डा) : मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। माननीय राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण में यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक लम्बी सोच के साथ काम करना चाहती है। यह सरकार हरियाणा प्रदेश को विकास के रास्ते पर और नई बुलंदियों पर लेकर जाएगी, और इस प्रदेश की बिगड़ी हुई व्यवस्था को लाईन पर लाने का काम करेगी। ऐसी उम्मीद हम सभी करते हैं। इसके साथ-साथ ये सरकार एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए भी कार्य कर रही है। आम आदमी को न्याय मिले और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। सी.एम. विन्डो, वेब पोर्टल, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, गौ रक्षा पर प्रस्तावित विधेयक और ई-रजिस्ट्री जिनका मैं यहां पर कुछ उदाहरण के तौर पर जिक्र कर रहा हूं जो इस कड़ी में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। भ्रष्टाचार रहित प्रशासन की बात करूं तो मुझे याद आता है आज से लगभग एक महीना पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक सरपंच मेरे पास आया और उसके साथ एक बहुत ही साधारण व्यक्ति जिसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और उसने मुझे आकर कहा कि आज हम आपका मुंह मीठा कराने आए हैं क्योंकि हमारी मेहनत सफल हो गई। मैंने कहा सरपंच साहब क्या मेहनत सफल हो गई। वह कहने लगे कि हम तहसील में जमीन की रजिस्ट्री के लिए 40 हजार रुपये लेकर गये थे। हमारी रजिस्ट्री हो गई और हमारे पैसे भी नहीं लगे इसलिए मुंह मीठा कराने के लिए आया हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नई सरकार से हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं और हमारी सरकार की भी यही सोच है कि "सबका साथ सबका विकास"। अध्यक्ष महोदय, खासकर जब भेदभाव की बात आती है और इसे दूर करने की बात सरकार करती है तो मेरा ध्यान सबसे पहले खासकर अपने विधान सभा क्षेत्र घरौंडा की तरफ जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं 25 साल पहले राजनीति में सक्रिय हुआ था। मैं 25 साल पहले भी जिन मसलों को सुना करता था और जिन मुद्दों का जिक्र हुआ करता था, दुर्भाग्य से आज भी मेरे इलाके में ये सारे मुद्दे ज्यों के त्यों हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारें गई मगर वे तमाम मुद्दे घरौंडा क्षेत्र में यूँ के यूँ हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मौजूदा सरकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के रेलवे पार के 22 गाँवों के लोगों की बहुत बड़ी समस्या हैं, क्योंकि उनको आज तक घरौंडा शहर में आने के लिए उन गाँवों से कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही रेलवे लाईन पार करते हैं तो वहाँ पर लगभग आधे किलोमीटर रेलवे की जमीन है जिसकी आज तक किसी भी सरकार ने रेलवे से पुल बनाने की परमीशन नहीं ली है। अध्यक्ष महोदय, लगभग बहुत से मौके ऐसे ही रहे कि जिस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी उसी पार्टी की सरकार केन्द्र में भी थी परन्तु आज तक यह समस्या दूर नहीं हो पाई। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली में फसल भर कर बेचने के लिए मंडी में जाते हैं तो उन्हें 3 किलोमीटर के रास्ते के लिए कम से कम 10-12 किलोमीटर घुमकर घरौंडा मंडी में जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, करनाल शहर के अंदर मुगल कैनाल है जिसमें शहर का पूरा गंदा पानी निकलता है और उसके बाद वह ड्रेन नम्बर दो में जाकर गिरता है। वह ड्रेन घरौंडा विधान सभा क्षेत्र से होकर जाती है। यह भी एक बहुत पुरानी समस्या है क्योंकि लगभग 32 साल पहले वर्ष 1983-84 में जब छोटी यमुना में पुल का निर्माण हुआ था उस समय यह ड्रेन बंद कर दी गई थी क्योंकि छोटी यमुना में जिन लोगों की मलकियत थी उन्होंने अपनी-अपनी जमीन बाह (जोत) ली। आज यह पानी यमुना में जाने की बजाये घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के सैंकड़ों एकड़ जमीन पर इक्ट्ठा होता है और इसकी वजह से सारी जमीन

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

बर्बाद हो चुकी है। हमारे किसान जो एक-एक, डेढ-डेढ एकड़ की जो खेती करते हैं, बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे हैरानी होती है कि इनकी किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक राज किया, मैं आपके माध्यम से उन माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि वे आज किसानों की किस मुँह से बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय तक मेरे इलाके के किसानों ने संघर्ष किया किसी भी सरकार को इन किसानों का दर्द दिखाई नहीं दिया। आज ये लोग किसानों की बात करते हैं, मुझे हैरानी होती है। अध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर की जो ड्रेन बीच में टूटी हुई है आज तक किसी भी सरकार ने उस ड्रेन को पूरा नहीं करवाया। जिसके कारण करनाल शहर का जितना भी गंदा पानी आता है वह 250 एकड़ जमीन में इकट्ठा होता है और वह जमीन आज बर्बाद हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, वे सभी किसान केवल एक-एक या डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन के मालिक हैं उनके द्वारा लम्बे समय तक संघर्ष करने के बावजूद किसी भी सरकार में सुनवाई नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आज हम सत्ता में आए हैं तो किसानों की जिम्मेदारी लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य किसानों की बात करते हैं और उनके मुद्दों पर मजाक उड़ाते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ सी.एल.यू. की खेती की है। सी.एल.यू. की खेती करने वाले लोग आज किसानों की बात करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2002-03 में तत्कालीन सरकार में मेरे हल्के के जो बड़े बड़े गाँव है जैसे बरसत और चौरा इत्यादि वहाँ पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाने के लिए मंजूरी मिली थी। मगर आज12 साल बीतने के बाद भी वहाँ पी.एच.सी. की कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद हमने पी.एच.सी. बिल्डिंग बनाने के लिए फाईल आगे चलाई है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक राज किया और बड़ी-बड़ी फिल्मों की तर्जों पर गानों के माध्यम से अपने आपको नम्बर वन होने का भी दावा करती रही। अध्यक्ष महोदय, ये गाने सुनने में तो बहुत अच्छे लगते थे मगर जब हम हरियाणा प्रदेश के इलाकों में जाते थे तो इलाकों की दुर्दशा देखकर मन में बहुत पीड़ा होती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने घरौंडा शहर की पीड़ा सुना रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा शहर में वर्ष 1992 से लड़कियों का स्कूल दो शिफ्टों में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब सर्दी का मौसम आता है तो दूसरी शिफ्ट शाम को 5:30 बजे खत्म होती है तब तक बहुत अंधेरा हो जाता है और हमारी बहन बेटियों को अंधेरे में ही अपने-अपने घरों में जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी भी सरकार ने स्कूल की दूसरी शिफ्ट के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो कार्य नहीं किये उसका जिक्र न करते हुए, सरकार ने जो कार्य किये हैं, मैं उनको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने एक तोहफा दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य अच्छे वक्ता के साथ-साथ अच्छे श्रोता भी बने। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं कह रहा था कि वर्ष 2007 में पिछली सरकार ने घरौंडा क्षेत्र को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया कि हमारी समस्याएं तो दूर नहीं कर सके मगर हमारे घरौंडा हल्के में से पब्लिक हैल्थ विभाग का जो सब डिविजन था उसको वहां से उठा दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पब्लिक हैल्थ मंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयासों से 1 जनवरी, 2015 को वह सब डिविज़न पब्लिक हैल्थ को वापिस घरौंडा में आ गया है और

उसमें कार्य भी शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों घरौंडा क्षेत्र के कुटेल गांव में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ-साथ कुटेल गांव की पंचायत का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिये 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव रखा था। अध्यक्ष महोदय, जब यूनिवर्सिटी के कंसैप्ट पेपर बनाये गये तो उसमें लगा कि उसके लिए और अधिक जमीन की जरुरत है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद कुटेल गांव की पंचायत ने 178 एकड़ जमीन देने का नया प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है, इसके लिए मैं पुन: ग्राम पंचायत, कुटेल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे घरौंडा विधान सभा क्षेत्र में आज भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको बने हुए काफी वर्ष हो गये हैं, पहले सड़कें 10 फीट की थी परन्तु अब वे सड़कें घिस कर 9 फीट की रह गई है। अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें घरौंडा से फुरलक, स्टौंडी व पुरलक से गगसीना और घरौंडा से कैमला अलीपुरा, हरसिंहपुरा, पुंडरी की ओर जाती है, इन सड़कों पर 7-7, 8-8 और 10-10 गांवों का ट्रैफिक चलता है परन्तु वहां की सड़कें 9-10 फीट चौड़ी सड़कें आज भी वहा ज्यों की त्यों कायम है। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा क्षेत्र में 16वीं सदी का एक किला है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार को चाहिए था कि इन सड़कों को आर्कियोलोजिकल डिपार्टमैंट को ट्रांसफर कर देते और आने वाली पीढ़ियों को दिखाते कि हमारे यहां भी कभी 9-10 फीट चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करुँगा कि जल्द से जल्द इन सड़कों को वाइडनिंग और स्ट्रैथनिंग स्कीम के तहत बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा शहर के अंदर आज तक कोई बस स्टैण्ड नहीं है। पिछली सरकार ने वर्ष 2010 में नया बस स्टैण्ड बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वह मात्र घोषणा बनकर ही रह गई। अध्यक्ष महोदय, जब हम पानीपत की तरफ जाते हैं तो उस सड़क के पास एक ऊपर छोटा सा बस स्टॉप है। वहां पर बरसात के दिनों में डेढ-डेढ फीट पानी खड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे घरौंडा हल्के की बात बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हम पानीपत से करनाल की तरफ आते हैं तो सड़क के किनारे छोटा सा शैल्टर बस स्टैण्ड के नाम पर फुटपाथ पर भी बना हुआ है, जब बस वहां पर रुकती है तो सारा ट्रैफिक रुक जाता है। अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात एक ही लाइन में कह कर समाप्त करुँगा। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा में सब डिविजन की एक पूरानी मांग है। अध्यक्ष महोदय, हमारे हल्के के 104 गांवों में से लगभग 70 गांवों में पानी की निकासी नहीं है। लड़कियों के लिए कॉलेज की बहुत पुरानी मांग है। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा विधान सभा क्षेत्र में आने वाले गांवों का रिकॉर्ड उठाकर देखें की पिछली सरकार ने कितने स्कूलों को अपग्रेड किया है, इससे आपको पता चल जायेगा कि पिछली सरकार शिक्षा के प्रति कितनी सजग थी। अध्यक्ष महोदय, 25 साल पहले आई.टी.आई. बनवाने के लिये पंचायत ने सवा तीन एकड़ जमीन दी थी। आज तक आई.टी.आई. नहीं बनी बल्कि पिछली सरकार ने उस जमीन को स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार न तो वहां पर आई.टी.आई. बनी है और न ही स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज का निर्माण हुआ है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत की मांग है कि वह जमीन पंचायत को वापिस दिलवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, घरौंडा शहर के अंदर न तो कोई पार्क है और न ही कोई स्टेडियम है। अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी के टूटने के कारण जितने भी गांव इसके साथ लगते हैं, लगभग हर साल किसानों की हजारों एकड़ जमीन खराब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कही

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

गई सभी बातों की ओर यह सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे दाईं तरफ बैठे हुए सभी सम्मानित सदस्यों का मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनका इसलिए भी सम्मान करता हूँ क्योंकि वे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बेकार हैं और इसके साथ-साथ ज्ञानी भी हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य तब ज्यादा सम्मान करेंगे जब ये हमारी नई सरकार को काम करने का मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, बेवजह निंदा करने से कोई अच्छा संदेश नहीं जायेगा। खासकर जब यह सरकार उसी व्यवस्था को ठीक करने का काम कर रही है जिस व्यवस्था को इन्होंने खुद बिगाड़ा है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए खास तौर से अपने सभी नये साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बार सदन का समय लम्बा किया जिससे सबको बोलने का मौका मिला है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री जसबीर देशवाल (सफीदों) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लास्ट बैंच का स्पैशल ध्यान रखा। अध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले भी मेरे साथियों ने इस अभिभाषण पर विस्तार से चर्चा की है। इसलिए मैं इस पर ज्यादा न बोलते हुए यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण सरकार के लिए पूरे वर्ष का एक विजन होता है। किसी भी प्रदेश की उन्नति और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रदेश की शिक्षा प्रणाली और इन्फ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जहां तक प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का सवाल है इस अभिभाषण में सरकार ने काफी महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। सरकार ने एक नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। अधिनियम 2009 लागू होने के बाद पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं दुबारा से शुरू की है जोकि पिछली सरकार ने इन परीक्षाओं को बन्द कर दिया था। यह वर्तमान सरकार का एक साहसिक और सुधारात्मक कदम है। इन परीक्षाओं के आधार पर आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी और इसके साथ-साथ अध्यापक के लिए डायरी बनाना भी अनिवार्य किया गया है। अध्यक्ष महोदय जी, जहां तक कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार की बात है इस बारे में भी सरकार काफी सजग दिखाई देती है। सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कही है। सी.एम. विंडो का शुभारम्भ किया गया है जिसके अच्छे परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे। 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं और बेटियों की बेहतरी के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना का आह्वान किया है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। यह भी इस अभिभाषण में दर्शाया गया है कि यह सरकार जल सुरक्षा को उचित प्राथमिकता देगी जो हमारी आने वाली पुस्तों के लिए भी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ई-रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की है यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। अध्यक्ष महोदय, सरकार का स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत अभियान भी सराहनीय कदम है। चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने का प्रयास किया है तथा कमजोर वर्गों को सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं सरकार को सफीदों हल्के की भी कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहूंगा। सफीदों को सब-डिविजन बने 35 साल हो गये हैं लेकिन आज तक सफीदों में सीयरेज व्यवस्था नहीं है। सीयरेज की पाईपें बबी हुई हैं लेकिन वे चालू नहीं की गई हैं। अत: मेरा सरकार से निवेदन

है कि इसको चैक करवाकर इसको प्रोपर तरीके से चालू करवाएं। यहां पर अब तक कोई ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं बना है। हमारे लगभग 30 गाँवों में गन्दा पानी ओवर फ्लो हो रहा है जिसके कारण बीमारी फैलने की आशंका है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन हैं कि इस गन्दे पानी की निकासी का इन्तजाम करवाया जाए। सफीदों शहर के गन्दे पानी को निकालने के लिए दो ड्रेनें बनाई गई हैं उन दो ड्रेनों में एक तो आधी पक्की बनी हुई है लेकिन दूसरी पूरी की पूरी कच्ची है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन दोनों ड्रेनों को पक्का करवाया जाए। गांगोली गाँव से निकलने वाली ड्रेन जिसे पड़ाना ड्रेन भी कहते हैं को मोरखी गाँव के पास किसानों ने उसे बन्द कर रखा है क्योंकि उन किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन गाँवों के किसानों को मुआवजा देकर इस ड्रेन को खुलवाने का काम किया जाए। सफीदों हल्के में हांसी ब्रान्च नहर भी निकलती है। सफीदों शहर का बाई पास अधूरा पड़ा है अगर हांसी ब्रान्च की दोनों पटरियां पक्की कर दी जाएं तो ये पटरियां एक किस्म से बाई पास का काम करेंगी। सफीदों शहर पानीपत-जीन्द स्टेट हाई-वे पर पड़ता है। सफीदों से पानीपत की तरफ निकलते ही बुटाना ब्रांच नहर आती है। बुटाना ब्रान्च नहर पर जो एक बड़ा पुल है वह बहुत तंग है उस पुल पर एक व्हीकल ही एक बार वहां से निकल सकता है। इसलिए इस रोड पर सप्ताह में दो तीन एक्सीडैंट हो जाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पुल को चौड़ा किया जाए। इस बारे में मैंने पिछली सरकार के समय में काफी कोशिश की थी कि यह पुल चौड़ा हो जाए लेकिन वह पुल आज तक चौड़ा नहीं हुआ है। सफीदों शहर में एक जनरल हस्पताल है जिसमें 11 पद डॉक्टरों के हैं जबकि यहां दो ही डाक्टर कार्यरत हैं वहां डॉक्टरों की बहुत कमी है। कभी यहां पर दो डॉक्टर डेपुटेशन पर आ जाते हैं और कभी एक ही डॉक्टर डेपुटेशन पर रहता है तीन से ऊपर डॉक्टर कभी यहां पर नहीं रहे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सफीदों के जनरल हस्पताल में डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। सफीदों शहर में दो ब्लॉक हैं पिल्लु खेड़ा और सफीदों। पिल्लुखेड़ा ब्लॉक में एक भी कन्या महा विद्यालय नहीं है और पिल्लुखेड़ा खण्ड की बच्चियों को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज के लिए बसों में या प्राईवेट व्हीकल्ज में जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पिल्लुखेड़ा में एक कन्या महाविद्यालय खोलने का इन्तजाम किया जाए यह हमारे हल्के की 20 साल से मांग चल रही है। इस हल्के के स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। जैसे गाँव खेड़ा खेमावती के स्कूल को 10+2 का अपग्रेड किया जाए, गांगोली गाँव के स्कूल को भी 10+2 के लिए अपग्रेड किया जाए। धड़ौली गाँव के स्कूल को मीडिल से हाई स्कूल अपग्रेड किया जाये, इसी प्रकार से भाग खेड़ा गाँव के स्कूल को मीडिल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाए। इन सभी स्कूलों की फाइलें विभाग में लम्बित पड़ी हुई हैं उनको सिरे चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी प्रकार से अन्टा गाँव में आज भी प्राईमरी स्कूल है उस स्कूल को मीडिल स्कूल में अपग्रेड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि इन पांच सात गाँवों के स्कूलों को अपग्रेड करने का काम करें। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी जीन्द गये थे। मैं यह बात सदन में कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने जीन्द जिले को पिछड़ा जिला बना कर रखा था जबकि हरियाणा की राजनीति जीन्द जिले से ही शुरू होती है। जीन्द शहर के बाई पास का उद्घाटन तीन तीन बार किया गया। जींद जिला बहुत पुराना जिला है जिसमें आज तक कोई बाईपास नहीं

[श्री जसबीर देशवाल]
है। (विघ्न) मैं जिले का प्रधान था। (विघ्न) इन्होंने लड़कियों का कॉलेज बनाया है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देशवाल जी, आप जल्दी वाइंड-अप करें।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जींद-पानीपत, पी.डब्ल्यू.डी. बी एण्ड आर. रोड़ को 4-लैनिंग करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जींद में आज तक कोई भी औद्योगिक बड़ी इकाई नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कुछ सड़कों का निर्माण किया जाना अत्यावश्क है जो छोटी-छोटी 1-2 कि.मी. लम्बी सड़कें हैं तथा इन सड़कों से संबंधित फाईलें भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कार्यालय में लंबित पड़ी हैं। उन सड़कों में अन्टा से जोशी माजरा तक, बुटानी से शिलाखेड़ी वाया रोजला तक, हाट से कुरड़ तक, ऐंचरा खुर्द से हरीगढ़ तक, बागडू से भाग खेड़ा जलधर तक, टीटोखेड़ी से करसिंधू रेलवे स्टेशन तक, सिंघाना से पाजू खुर्द तक, मुआना से कोल खेड़ा तक आदि शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : देशवाल जी, जिन सड़कों के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, आप कृपया उनके बारे में अलग से लिखकर दे दीजिए उसको सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जायेगा।

श्री जसबीर देशवाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है मैं इन सड़कों के बारे में लिखकर दे दूंगा। अंत में मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जींद जिले में औद्योगिक इकाई जरूर स्थापित की जाये तथा बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के हुए नुक्सान का मुआवजा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री नागेन्द्र भड़ाना (फरीदाबाद एन.आई.टी.) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने विशेष तौर से जल-संरक्षण पर ध्यान दिया है क्योंकि जल की हर बूंद कीमती होती है तथा हरियाणा सरकार जल संरक्षण को प्राथमिकता देने पर प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र 86-फरीदाबाद एन.आई.टी. में पानी की बड़ी भारी किल्लत है। मेरे हल्के में 80 प्रतिशत् से ज्यादा लोग कालोनीज़ के अंदर रहते हैं तथा हिन्दुस्तान के हर कोने से आकर लोग यहां पर बसे हुए हैं जिनमें से अधिकांश लोग नोकरीपेशा हैं तथा उन में से अधिकतर लोगों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। वे लोग टैंकरों से पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन लोगों को राहत देने के लिए जल-संरक्षण की नितान्त आवश्यकता है। मेरे हल्के के गाँव पाली में 100 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी जमीन है जो कि तीन तरफ से एक कटोरीनुमा पहाड़ी की दीवारों से घिरी हुई है। बारिश के समय में वहां पर कई झरने बन जाते हैं तथा वह पानी आसपास के खेतों व खलिहानों का नुक्सान करता हुआ ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है इसलिए

मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस बरसाती पानी को रोककर वहां पर एक बांध बनाया जाये जिससे बड़े नुक्सान से बचा जा सकता है तथा इस प्रकार से लाखों गैलन पानी इकट्ठा हो सकता है जो एक झील के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि जमीन का एक टुकड़ा भी अधिग्रहण किये बिना इस योजना को कार्यान्वित किया जा सकता है। वहाँ पर रॉ-मैटीरियल उपलब्ध है, मिट्टी उपलब्ध है तथा पत्थर उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बारिश के समय में यमुना नदी के अंदर शुद्ध पानी होता है। वैसे तो दिल्ली और नोएडा का सीवरेज और कैमीकल का पानी यमुना में बहता है लेकिन बारिश के 2-3 महीने के समय में यमुना नदी में शुद्ध पानी आता है। यमुना नदी से फरीदाबाद के लिए एक गुड़गाँव नहर निकलती है जिससे सिंचाई के लिए एक नेकपुर-हरिचंद माईनर भी निकलती है। इस नेकपुर-हरिचंद माईनर के आखिरी छोर पर 9 बड़ी-बड़ी मोटरें रखी हुई हैं जो वहां से पानी को हरिचंदपुर माईनर, फतेहपुर तगा माईनर और नेकपुर माईनर के लिए पम्प करती हैं। चूंकि वहां पर मोटरें पहले से ही लगी हुई हैं इसलिए 3-4 फुट की एक पाईपलाईन डाली जाये। जहां हम बांध बनाना चाह रहे हैं उस स्थान की व इस नहर की दूरी मात्र लगभग 3 किलोमीटर ही है। बारिश का यह पानी यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ में ही बह जाता है। उस पानी का सदुपयोग हम लोग कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जल संरक्षण से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जल संरक्षण के सपने को पूरा किया जा सकता है। हवा और पानी तो सबसे जरूरी चीज होती है। मैं सदन में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को अवश्य दूर करने का काम करें। इसके साथ-साथ एन.आई.टी. क्षेत्र में तीन नम्बर पुलिया से डबवा गांव और डबवा से पाली तक की जो सड़क है वह बड़खल विधानसभा और एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र को जोड़ती है जोकि मुख्य मार्ग है जिससे हजारों लोग रोज निकलते हैं। मुख्यमंत्री महोदय की अनाउंसमैंट के तहत दो सड़कें तीन नम्बर पुलिया से डबवा गांव तक और दूसरी डबवा गांव से गाजीपुर और गाजीपुर से नंगला सड़कों के लिए नगर निगम के पास पैसा भी आ गया था परंतु नगर निगम ने वह पैसा किन्हीं दूसरे कामों में खर्च कर दिया जिस कारण वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। इन सड़कों के बन जाने से बड़खल विधानसभा क्षेत्र और एन.आई.टी. क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, एन.आई.टी. क्षेत्र में गोच्छी ड्रेन है जिस पर नाला तो पक्का कर दिया गया है परंतु मैं कहना चाहूंगा कि उसके दोनों तरफ चौड़ी सड़कें बनाई जाएं क्योंकि यह बल्लभगढ़ विधानसभा और एन.आई.टी. विधानसभा को जोड़ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दो-तीन साल पहले एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र में पर्वतीय कालोनी में एक विमान गिरा था और वहां कोई चौड़ी सड़क न होने की वजह से एम्बुलैंस को पहुंचने में डेढ़-दो घंटे लग गए। मेरे क्षेत्र में कोई चौड़ी सड़क नहीं है इसलिए गोच्छी ड्रेन के दोनों तरफ चौड़ी सड़कें बना दी जाए इससे बल्लभगढ़ और एन.आई.टी. क्षेत्र के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, पाली गांव में जो पी.एच.सी. है उसको सी.एच.सी. में अपग्रेड करने की मांग मैं करना चाहूंगा क्योंकि इस गांव के अंदर सवा लाख से ज्यादा की आबादी है। एशिया का सबसे बड़ा क्रशर जोन यहां पर है और यहां लेबर कालोनीज भी हैं। यह क्षेत्र 4 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल पर बना हुआ है। सिविल सर्जन, फरीदाबाद

[श्री नागेन्द्र भड़ाना]

ने भी इस केन्द्र को अपग्रेड करने के लिए महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, चंडीगढ़ को दो बार पत्र लिखे हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे यहां वर्तमान में 7-8 किलोमीटर की परिधि में आस पास में कोई भी सी.एच.सी.भवन नहीं बना हुआ है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहां पर पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में अपग्रेड किया जाए। इसके साथ-साथ हमारे पूरे एन.आई.टी. क्षेत्र में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां जरा-सी बारिश आ जाने से घुटनों-घुटनों तक पानी भर जाता है। एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र में 60 फुट रोड, लेजर वैली पार्क, बंगला चौक पर कई-कई फुट पानी भर जाता है तथा लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर जाता है जिससे उनका सारा सामान खराब हो जाता है। अत: मेरी सदन से गुजारिश है कि वहां बारिश से पहले पहले पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, एन.आई.टी. विधानसभा में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है क्योंकि हमारे यहां कालोनीज बहुत ज्यादा हैं तथा सीवरेज की पाइप बहुत छोटी डाली गई हैं इसलिए एम.सी.,फरीदाबाद को हमारे एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के लिए दो बड़ी शोकर मशीनें दी जाएं जिससे सीवरेज व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त किया जा सके तथा इसके साथ-साथ सफाई कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक महिला विश्वविद्यालय भी बनाया जाए। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां मुस्लिम भाइयों के लिए कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है। जब हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई आयोजन करना होता है तो बैंकेट हॉल वाले उनको इजाजत नहीं देते हैं क्योंकि उनके यहां दूसरी तरह का खाना बनता है इसलिए हमारे क्षेत्र में मुस्लिम भाइयों के लिए एक मुस्लिम सामुदायिक केन्द्र भी बनाया जाए ताकि वे अपने ब्याह-शादियां वगैरह कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां स्ट्रीट लाइटों का बहुत बुरा हाल है जिस कारण रात के अंधेरे का फायदा चोर-उचक्के उठाते हैं और गलत कामों को अंजाम देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपकी मार्फत सदन में कहना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले के अंदर खनन कार्य बंद पड़ा हुआ है जिसके कारण से मैटीरियल दूसरी जगहों से प्रदेश में आता है। जिससे प्रदेश का राजस्व दूसरे प्रदेशों में जाता है। यदि फरीदाबाद जिले में खनन का कार्य खुल जायेगा तो प्रदेश के हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा प्रदेश में लोगों को अच्छा माल कम रेट पर मिलेगा क्योंकि फरीदाबाद के पत्थर की क्वालिटी बहुत अच्छी है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपके मार्फत मुख्यमंत्री जी से और सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से पार्लियामैंट में एम.पीज. को और राजस्थान, यू.पी. तथा दिल्ली आदि राज्यों में विधायकों को विधायक नीधि के तहत पैसा दिया जाता है उसी तरह से हमारे प्रदेश में भी विधायकों की विधायक नीधि लागू की जाये। अध्यक्ष महोदय, जब एक जन प्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है और लोग बिजली, पानी, सड़क और नाले आदि की समस्याओं से जनप्रतिनिधि को अवगत करवाते हैं तो उस समय विधायक कुछ भी वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। इस तरह से अपने आपको विधायक असहाय महसूस करते हैं। इसमें मेरा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि विधायकों की विधायक निधि शुरू की जाए ताकि विधायक भी अपने लैवल पर जहां कहीं जरूरी हो वहां कार्य करवा सकें। विधायक निधि लागू करके सरकार वाकई में प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोगों का सम्मान करेगी। सरकारें आती-जाती रहती हैं। आज प्रदेश में भारतीय जनता

पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और आगे किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो सकती है। यहां जितने भी विधायक बैठे हैं वे सभी तकरीबन अपने-अपने क्षेत्र के 2 से 2.50 लाख वोटर्ज का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए लोकतंत्र में विधायकों को वित्तीय पावर देना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान में रखकर विधायक निधि लागू की जाए जिसके लिए पूरा सदन मुख्यमंत्री जी का आभारी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ मांगे हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के मांगड़ गांव में तीव्र ढलान है जिसके कारण वहां बसें वगैरह रूकने में बहुत दिक्कत रहती है और आए दिन एक्सीडैंट भी होते रहते हैं इसलिए इस ढलान को कम करवाया जाए। इसी तरह से जाहड़स्थली गांव है जिसकी जमीन हुडा द्वारा एक्वायर कर ली गई थी और एक धर्मशाला की साईट छोड़ दी गई थी लेकिन बाद में वह जमीन भी औद्योगिक साइट में बदल दी गई। इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। गांव के लोगों ने सिविल पैटीशन संख्या-15675/ 2014 माननीय हाई कोर्ट में डाली थी जिसका डिसीजन 7 अगस्त, 2014 को आ चुका है और हुडा विभाग को वहां पार्क तथा ग्रीन बैल्ट डिवैल्प करने के आदेश दिए हैं। मेरी मांग है कि हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार जाहड़स्थली गांव में ग्रीन बैल्ट व पार्क डिवैल्प करने की व्यवस्था की जाये क्योंकि गांव से साथ लगती जमीन खाली है जो अभी हुडा ने अलोट नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एन.आई.टी. विधान सभा क्षेत्र में एक 60 फिट रोड़ है जहां आसपास बहुत आबादी है जिसके कारण वहां जाम की स्थिति बनी रहती है। उस रोड़ के दोनों तरफ बिजली के पोल लगे हुए हैं जिन्होंने रोड़ की 7-8 फिट जगह घेरी हुई है। यदि वहां रोड़ के बीच में डिवाइडर बनाकर पोल वहां शिफ्ट कर दिए जायेंगे तो 15-20 फिट की सड़क चौड़ी हो जायेगी जिस पर यातायात सुचारू रूप से चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे हल्के के पाली गांव की आई.टी.आई. में इस समय केवल दो ट्रेड चल रहे हैं। वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग का कार्य 2014 से चल रहा है इसलिए वहां पर सभी तरह के ट्रेड्स चालू किए जायें ताकि वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी तरह से मेरे हल्के के डाबरा कालोनी में रेनीवैल वाटर सप्लाई का बुस्टिंग स्टेशन है वहां लाईट जाने पर लोगों को पीने के पानी की बहुत दिक्कत रहती है इसलिए डाबरा फीडर पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों की बात है मेरे हल्के के पावटा गांव की सड़क जर्जर हालात में है इसलिए पावटा-सलाखरी-मांगड़ सड़क का कार्य जल्द से जल्द करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : भड़ाना जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप बैठ जायें। अगर आपकी कोई डिमाण्ड रह गई है तो आप उसके बारे में हमें लिखकर दे दें हम उसको हाउस की कार्यवाही में शामिल कर लेंगे।

श्री नागेन्द्र भड़ाना : स्पीकर सर, आप कृपा करके मुझे दो मिनट का समय और दे दें मैं जल्दी ही अपनी बात पूरी कर दूंगा। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ए.पी.एल. अर्थात हरे कार्ड हैं ये वर्ष 2005 में बनाये गये थे। इनको बने हुए 10 साल हो गये हैं इसलिए लोगों के हरे कार्ड जल्दी से जल्दी बनाये जाये। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बी.पी.एल. कार्ड हैं इनको बनाते समय बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताये बरती गई हैं। जो पात्र परिवार थे उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है और जो अपात्र लोग थे जिनके घरों में गाड़ियां खड़ी है और जो अच्छी-अच्छी नौकरियों पर लगे हुए उन्होंने बी.पी.एल. कार्ड बनवा रखे

[श्री नागेन्द्र भड़ाना]

हैं और वे इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाये और जो पात्र परिवार हैं उनके बी.पी.एल. कार्ड जल्दी से जल्दी बनाये जायें ताकि वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

श्री जाकिर हुसैन (नूंह) : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया क्योंकि समय कम है इसलिए भूमिका की बात न करते हुए मैं सीधे ही अपने हल्के की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के आगे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" एक कार्यक्रम रखा और जिसका शुभारम्भ उन्होंने पानीपत से किया। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मेवात जिला पिछड़ा हुआ है लेकिन यह खुशी की बात है कि जो जिले अपने आपको बहुत अग्रणी मानते हैं वे बेटी और बहनों को बचाने में पीछे हैं और हमारा मेवात जिला इस मामले में सबसे आगे है। जैसा कि आदरणीय सदस्या श्रीमती प्रेमलता जी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाने के लिए आज पूरा दायित्व सरकार के ऊपर है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मेवात जिला बेटियों को बचाने में पूरे प्रदेश में अग्रणी है इस प्रकार से बेटियों की सुरक्षा तो हम कर रहे हैं लेकिन हम अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए पूरी तरह से सरकार पर आश्रित हैं। अगर कहीं बेटियों के रिश्ते की बात चलती है तो लड़कियों के गोत्र से पहले लड़कियों की शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। मैं समझता हूं कि सिर्फ नौकरी करने के लिए ही नहीं अपितु एक अच्छे परिवार के पालन-पोषण के लिए भी हमारी बेटियों का उच्च शिक्षित होना बेहद अनिवार्य है। इस प्रकार से जहां बेटियों की सुरक्षा में मेवात जिला पूरे प्रदेश में अग्रणी है वहीं बेटियों की शिक्षा के मामले में पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह चौंकाने वाले तथ्य लाना चाहूंगा कि पूरे मेवात जिले में लड़कियों के गवर्नमैंट हाई स्कूल केवल मात्र दो हैं, गवर्नमैंट गर्ल्ज सीनियर सैकेण्डरी स्कूल केवल मात्र सात है और गवर्नमैंट गर्ल्ज मिडल स्कूल केवल मात्र 44 हैं। मैं एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि मेवात जिले के किसी भी गांव में लड़कियों का सीनियर सैकेण्डरी स्कूल नहीं है। यह रिकार्ड की बात है। (विघ्न) सर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में मेवात जिले में लड़कियों के प्राईमरी स्कूलों की संख्या 550 थी। यह मैट पर दिया गया सरकार का रिकार्ड है। आप देखेंगे कि जहाँ तक लड़कियाँ और बहन-बेटियाँ पैदा होने की बात है तो मेवात जिला सबसे अव्वल है । केवल लड़कियों के संरक्षण में ही अव्वल नहीं है बल्कि हरियाणा में लड़कियों को स्कूल भेजने में भी अव्वल है। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में सबसे ज्यादा चिन्ता मेवात को लेकर की गई थी।

श्री जाकिर हुसैन : बहन जी, मैं आपके समय की ही बात बता रहा हूँ कोई बहुत पहले की नहीं बता रहा हूँ। परन्तु जब इन्होंने जिक्र किया है तो मैं अवश्य बताना चाहूँगा कि जब होडल से रेवाड़ी तक और गुड़गांव से अलवर तक हाई स्कूल नहीं था तो मेरे दादा मरहूम चौधरी यासीनखां ने नूह में स्कूल बनवाया था । बाद में हमारे पिता जी ने वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाया था। जब हमारे परदादा जी की मृत्यु हुई उस समय हमारे दादा जी 12 साल के थे। अध्यक्ष

महोदय, उस समय होडल से लेकर पेशावर तक 36 जिलों का पंजाब होता था उस समय मरहूम चौधरी यासीनखां जो पंजाब सदन के सदस्य रहे, उन्होंने पूरे पंजाब को टॉप किया था और वजीफा लेकर सैंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़े थे। शिक्षा के लिए हमारा परिवार हमेशा जागरूक रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले में वर्ष 2012-13 में सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 1,60,057 थी। प्राइमरी के 550 स्कूलों के मुकाबले मिडिल स्कूल 270 हैं जबकि लड़कियों के लिए अलग से कोई स्कूल नहीं हैं। जैसा कि बहन प्रेमलता जी ने कहा कि आज जिस तरह का जमाना है उसको देखते हुये लड़कियों को दूर नहीं भेजा जा सकता और हमारे एरिया में तो न ही दूर भेजने के साधन हैं और दूसरी बात यह भी है कि कोई अपनी बहन-बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर भेजना भी नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूल में तो दाखिला दिलवा देते हैं लेकिन मिडिल स्कूल तक जाते-जाते यह संख्या 1,60,057 से घटकर 42,605 रह गई है। इस प्रकार लगभग 1,20,000 छात्र घर बैठ गये। इसमें भी ज्यादातर संख्या लड़कियों की थी जिनको कि पांचवीं के बाद की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में नहीं भेजते। अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि 2013-14 में 550 प्राइमरी स्कूल थे और मिडल स्कूल 270 रह गये। यह मैं सामान्य स्कूलों की बात कर रहा हूँ लड़कियों के स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेवात जिले में कुल 45 उच्च विद्यालय हैं। सर, इस प्रकार से मेवात में स्कूल छोड़ने वाले लड़कों के साथ लड़कियों की संख्या भी बहुत घट गई है। अब मैं उनका डाटा बताना चाहता हूँ। नौंवी कक्षा में कुल 6047 विद्यार्थी हैं जबकि दसवीं में 4926 विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार से 11वीं में 3885 तथा 12वीं में 3291 विद्यार्थी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है कि मेवात जिले में 550 प्राइमरी स्कूल हैं और 30 सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैं। सर, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ बल्कि आज इस बात की जरूरत है कि बहन-बेटियों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल अपग्रेड किये जायें, और शहरों में हम लड़कियों को नहीं भेज सकते इसलिए 4-4, 5-5 गांवों के बीच में स्कूल अपग्रेड किये जायें। इसके साथ-साथ जिस प्रकार दिल्ली में लड़कियों के लिए अलग से महिला बस चलती हैं उसी प्रकार से हरियाणा में भी लड़कियों के लिए अलग से बस चलाई जायें। इस बात का जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी किया है तथा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में क्रमांक 9 पर कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त निःशुल्क जिला स्तर छात्रा बस सेवा प्रदान की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करूँगा कि लड़कियों के लिए निःशुल्क छात्रा बस सेवा चलाई जाये। इस पर कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : जाकिर जी, आप वाइंडअप कीजिए केवल 2 मिनट का समय रहता है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, अगर टाईम कम बचा है तो या तो आप टाईम बढ़ा दीजिए या मैं कल बोल लूंगा क्योंकि अभी तो मुझे अपने हलके के बारे में भी बात करनी है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ सर, हाँ सर।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है कि आपकी उदारता और सदन के नेता निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है लेकिन समय के अनुशासन का पालन अगर हम नहीं करेंगे तो यह एक तरह से ओपन हाउस हो जाएगा। मेरा एक निवेदन है कि सबको बोलने का मौका देना यह सदन के नेता की प्राथमिकता है और आपकी उदारता है। लेकिन हमारा भी यह फर्ज बनता है कि समय के अनुशासन का हम भी पालन करें। आपसे भी निवेदन है आप हम सब पर सख्ती करें।

15.00 बजे

श्री जाकिर हुसैन : सर, इसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि हमने मेवात जिले में परिवहन महकमे के खर्चे को देखा था। लड़कियों के लिए नि:शुल्क बस सेवा चलाने के लिए करीब आठ करोड़ रुपये खर्चा बैठता है। अगर कस्बों और शहरों से लड़कियों के लिए नि:शुल्क बस सेवा चलाई जाए तो यह कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेवात जिले को प्राथमिकता देते हुए और खास तौर से बहनों को, बेटियों को बचाने के प्रोत्साहन के रूप में इसकी मेवात जिले से शुरुआत की जाए। सर, प्रोत्साहन के रूप में लड़कियों को यह सुविधा देना वजीफा वगैरह देने से भी बड़ा कदम होगा। आदमी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पीने के पानी की और नहरी पानी की। आज नहरी पानी की जहां पूरे प्रदेश में किसानों की चिन्ता व्यक्त हो रही है। मेवात क्षेत्र में भी पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और सरकार का भी जिन्होंने कोटला झील का मुआवजा इक्वीजेशन का नोटिस खत्म होने वाला था और सरकार ने बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया। खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकॉनोमिक स्टीम्यूलिस पैकेज से 51 करोड़ रुपये दिए। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करते तो दो दिन बाद उस झील परियोजना का मुआवजा देने का सैक्शन-6 का नोटिस भी खत्म हो जाता। सर, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि कोटला झील परियोजना खाली एक हल्के की नहीं पूरे मेवात जिले में सिंचाई के लिए कामयाब होगी। इसमें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए 108 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है जोकि बहुत कम है। यहां 5 हजार एकड़ जमीन में पानी भरता है। इसलिए इस परियोजना को बढ़ाया जाए यह बिल्कुल मेन अलवर रोड पर स्थित है। सर, आप यहां आकर देखना कि यह सुल्तानपुर लेक से भी बड़ी बर्ड सैंच्यूरी बनेगी चाहे आप इसके लिए बारिशों के बाद अपना प्रोग्राम रख लें। यह बहुत बड़ी बर्ड सैंच्यूरी बनेगी। यहां टूरिज्म भी होगा। दूसरा सर, जो पानी नहरों में आता है उसमें जैसे भाई भढ़ाना जी ने भी कहा कि हमें इस पानी में दिल्ली का और फरीदाबाद का सीवरेज का गन्दा पानी मिलता है। उसमें फ्रैस वॉटर नहीं होता आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। सीवरेज का जो पानी होता है उसका बी.ओ.डी. जो कोई पब्लिक हैल्थ की टैक्नीकल टर्म है यह पानी पशुओं के पीने लायक भी नहीं होता क्योंकि उसमें जहर की मात्रा इतनी होती है कि बी.ओ.डी. 30 प्रतिशत मीनिमम

और अधिकतम 70 प्रतिशत भी जाता है। उस पानी को पशु भी नहीं पी सकते। सर, ये लेक बारिशों के मौसम में गुड़गांव कैनाल से भरी जाएगी और इसमें यमुना का फ्रैस पानी भी आएगा। अगर पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट चाहे तो उस पानी से वहां पर पीने के पानी की स्कीमें भी बनाई जा सकती है। यह बहुत बड़ी परियोजना है। मैं सर, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेवात के साथ अर्थात् दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा भेदभाव रहा है कि हमें पानी के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ाने की बात होती है लेकिन जब देने का नम्बर आता है तो पिछली सरकार में हमें उम्मीद भी कि जब रोहतक का दांव बैठा तो हम समझ रहे थे कि हमारा भी नम्बर साथ जुड़ जाएगा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला हम तो उसमें फिर पीछे रह गये। सर, जो उस नहर में आज पानी आ रहा है कल पता नहीं पानी आएगा या नहीं आएगा। आज जो पानी है उसका पूरा न्यायोचित बंटवारा होना चाहिए। ज्यूडीशियल बंटवारा होना चाहिए। कई नहरों में 16-16 दिन पानी लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से कई जिलों में सेम लगी हुई है। हमारे यहाँ सरसों और गेंहू की फसल सूखे की मार से प्रभावित है। हम इस बारे में मौजूदा सरकार से पूरी उम्मीद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, जब श्री ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार वर्ष 2000-05 में थी तो मेवात जिले में नहरों का एरिया डिवैल्प कराया गया था और नहरों के लिए डिस्ट्रिब्यूट्री भी बनाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि मेवात जिले में नहरों का एरिया डिवैल्प करने के प्रयास किये जा रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर संवेदनशीलता आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके सचिवालय के प्रयासों से और सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों के प्रयासों से आज मेवात जिले की नहरों में पानी चलने लगा है **(इस समय मेजे थपथपाई गई)** लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जिले में पानी का बंटवारा हो। अध्यक्ष महोदय, ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की 6 जुलाई, 2012 को 42वीं मीटिंग हुई थी उसकी प्रोसिडिंग्स मेरे पास है इसमें जुलाई से अक्तूबर तक 600 क्यूसिक पानी देना मंजूर हुआ था, ओखला हैड पर गुड़गाँव कैनाल में। नवम्बर से फरवरी तक 600 क्यूसिक और मार्च से जून तक 700 क्यूसिक पानी देने का वादा किया गया था लेकिन अध्यक्ष महोदय बड़े अफसोस की बात है और यह रिकॉर्ड की बात है कि आज हमें सिर्फ 50 क्यूसिक भी पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, 100-150 या 200-300 क्यूसिक से ऊपर पानी नहीं आता है और जो पानी आ रहा है वह गुड़गाँव, फरीदबाद और दिल्ली से गंदा पानी आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेवात के अंदर जोहड़ भी इसी पानी से भरे जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इसकी रिपोर्ट भी मंगवा सकते हैं। जो फैक्टरियों से गंदा पानी आता है उसकी भी रिपोर्ट आप उपायुक्त महोदय से ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, फैक्टरियों से निकलने वाला पानी पशुओं को पीने के लिए दिया जाता है और वही पानी खेतों में भी छोड़ा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि 3-4 साल के बाद गंदे पानी से खेत कल्लर हो रहे हैं और पशु बीमारियों से मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कोई सयंत्र लगाया जाये जिससे हमें पानी साफ होकर मिले और जोहड़ों की साफ पानी से भराई हो सके। अध्यक्ष महोदय, जो 600 क्यूसिक पानी का हमारा हिस्सा है उसका जो फैसला हुआ है, वह भी लागू किया जाये। अध्यक्ष महोदय, पुन्हाना में आगरा कैनाल का कंट्रोल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आपको काफी समय दे दिया है, इसलिए आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, इसमें इसी तरह से हमारी मेवात फीडर कैनाल है जिसकी कैपेसिटी 741 क्यूसिक है जिसके लिए पानी मिला हुआ है 0.49 एम.एम. एलोकेटिड। यमुना का 0.37 और रावी ब्यास के लिए 0.12 पानी मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रिमिनरली प्रोजैक्ट रिपोर्ट सैंट्रल वाटर कमीशन ने अप्रूव कर दी है। इसकी डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट बननी है। अध्यक्ष महोदय, यह मेवात फीडर कैनाल बनाई जाये जिससे मेवात को पीने का पानी और नहरी पानी भी मिलेगा। इसी तरह से नूँह सब ब्रांच और नूँह डिस्ट्रिब्यूट्री जो पहले चौटाला साहब के टाईम में इसके लिए जमीन एक्वायर हो गई थी। लैंड एक्वीजिशन का नहरी पानी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, यह आर.डी. 1 लाख 31 हजार 750 तक बननी थी लेकिन वर्ष 2007 में 1 लाख 18 हजार आर.डी. तक बनाई गई। अध्यक्ष महोदय, यह 1 लाख 18 हजार आर.डी. कैपेसिटी की है जब इसमें 80 क्यूसिक से ऊपर पानी छोड़ा जाता है तो टूट जाती है। इसलिए इसे 1 लाख 31 हजार 750 आर.डी. तक जल्दी से जल्दी बनाई जाये । जितने भी खाले और चैनल थे वे खत्म हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि मेवात विकास बोर्ड की गतिविधियों को पुनर्जीवित करेगी, यह बड़ी खुशी की बात है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, और भी कई महकमें हैं जो वेंटीलेटर पर है जैसे बिजली बोर्ड वगैरह है। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड को पुनर्जीवित कर रहे हैं यह बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से विनती करना चाहता हूँ कि जो प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। यह एक बड़ी बीमारी है जो प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है उसके बीच में प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर और फिर उसके बीच में फिर प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर और आगे फिर प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, इसलिए अध्यक्ष महोदय सदन में सदस्यों को ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब सदन कल दिनांक 13 मार्च, 2015 प्रात: 10:00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*03.10 बजे (तत्पश्चात सदन शुक्रवार, 13 मार्च, 2015 प्रात: 10:00 बजे तक *स्थगित हुआ)।

53563—H.V.S.—H.G.P., CHD.